सूर्योदय 5:31 सूर्यास्त 7:25

आज का तापमान

शिमला	17.5 न्यू	22.4 अधि
धर्मशाला	19.8 न्यू	28.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	77,186
निफ्टी	24,072

सोना 1,42,000 चांदी 2,20,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 5 श्रावण, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 86, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

बिहार में 40 लोगों से भरी नाव नदी में पलटी

एजेंसी, सीतामढ़ी। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद बिहार में कोसी, बागमती समेत कई नदियां उफान पर हैं। इसी बीच रविवार को सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर स्थित बागमती नदी में 40 लोगों से भरी एक नाव पलट गई। नाव पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने नदी में छलांग लगाकर यात्रियों को बचाया। कई लोग खुद तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए। प्रत्यक्षदर्शी अमित ने बताया कि नाव चालक हम लोगों से भी कह रहा था कि आ जाइए, नदी पार करा देंगे। दूसरी बार में देर हो जाएगी, जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने नाव पर ज्यादा भीड़ देखकर मना कर दिया। थोड़ी ही देर बाद नाव पलटने की जानकारी मिली।

अश्लील फोटो वाले निहंग को संगलों से बांधा, डंडों से पिटवाया

एजेंसी, अमृतसर। निहंग जसदीप सिंह को उनके अश्लील फोटो सामने आने के बाद धार्मिक सजा दी गई है। बुड्ढा दल ने निहंग जसदीप सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। इसके तहत जसदीप सिंह को संगल (जंजीरों) से बांधा गया व दंड स्वरूप डंडों से मार भी लगाई गई। इस पूरी कार्रवाई की वीडियो और तस्वीरें बुड्ढा दल के दोआबा जोन के जत्थेदार मान सिंह ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। वीडियो में जत्थेदार मान सिंह कहते हैं कि अश्लील तस्वीरें सामने आने के बाद जसदीप सिंह को पहले भी सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह बीच में ही वहां से भाग गया था।

कोलकाता में देश के पहले 'शब्द संग्रहालय' का हुआ उद्घाटन

एजेंसी, कोलकाता। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में भारत के पहले 'शब्द संग्रहालय' (म्यूजियम ऑफ वर्ड) का उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा विकसित यह संग्रहालय देश की भाषाई विरासत, लिपियों और साहित्यिक परंपराओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। शाह ने कहा कि किसी भी देश की भाषा उसकी संस्कृति, इतिहास व विरासत की पहचान होती है।

जम्मू के पुंछ-किशतवाड़ में बादल फटे, 11 की मौत, 250 वाहन बहे

मलबे से दो साल के मासूम का शव निकाला; उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड

एजेंसी, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के पुंछ व किश्तवाड़ में शनिवार रात बादल फट गए। बाढ़-लैंडस्लाइड में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। पुंछ के सुरनकोट में लैंडस्लाइड से एक मकान मलबे में दब गया। उस वक्त घर में 8 लोग थे। इनमें 2 साल के बच्चे समेत 5 लोगों के शव बरामद किए गए। किश्तवाड़ के सुर्नू इलाके में बादल फटने से लोगों के घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा।

राजौरी में भी भारी बारिश के बाद धारहाल नदी का जलस्तर बढ़ गया। करीब 200 से 250 गाड़ियां बह गईं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा के रूट पर घोड़े- खच्चरों की सेवाएं रोक दी गईं और कैलाश-मानसरोवर यात्रियों का एक जत्था भी रुक गया। अरुणाचल में बाढ़ और भूस्खलन के इस दौर में अब तक सात

◆ नगालैंड में लैंडस्लाइड से 8 की मौत, अरुणाचल में बाढ़ से डेढ़ लाख प्रभावित

लोगों की मौत हो चुकी है, 29 लोग घायल हुए हैं और 1,49,257 लोग प्रभावित हुए हैं।

मानसून की मार से कुल 26 जिले, 328 सर्कल और 576 गांव प्रभावित हुए हैं। उधर, पिथौरागढ़ में, कैलाश-मानसरोवर यात्रा का चौथा जत्था, जिसमें 50 तीर्थयात्री शामिल हैं धारचूला बेस कैंप में रोक दिया गया है। बेस कैंप के इंचार्ज धन सिंह बिष्ट ने बताया कि गरबाधार में भूस्खलन के कारण गुंजी जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। उधर, नगालैंड के मोन इलाके में हुई लैंडस्लाइड के बाद एनडीआरएफ की टीमों ने मलबे से 8 शव निकाल लिए हैं, जबकि कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है।

जम्मू-कश्मीर में नदियां उफान पर

जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। मनावर नदी व धरावल नदी में बाढ़ आई है। ऐसे में राजौरी जिले और पीर पंजाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन व पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने के साथ-साथ घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है।

अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के सीएम व उपराज्यपाल से की बात

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में रातभर हुई भारी बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की। उन्होंने स्थिति की जानकारी ली और प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

किन्नौर में बादल फटने के बाद बाढ़ से आईटीबीपी परिसर में भारी तबाही

भारतेन्दु संवाददाता, किन्नौर। रकछम के मस्तरंग क्षेत्र में बादल फटने के बाद आई अचानक बाढ़ से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की द्वितीय वाहिनी का परिसर मलबे, पत्थरों और बोल्डरों से भर गया। बाढ़ का पानी जवानों के बैरकों तक पहुंच गया, जिससे कैंप की भोजन और अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आपदा के दौरान ग्राम पंचायत रकछम के महिला मंडल सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों ने निस्वार्थ सेवा और एकजुटता का परिचय दिया। ग्रामीणों ने फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, पर्यटकों और जरूरतमंदों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोले तथा भोजन और आश्रय की व्यवस्था की। प्रशासन और आईटीबीपी के साथ मिलकर स्थानीय लोगों ने सड़क से मलबा हटाने में भी सहयोग दिया। ग्राम प्रधान सुनीला नेगी, उपप्रधान शमशेर नेगी और वार्ड सदस्य उमा नेगी ने कहा कि एकजुटता, सेवा भावना और आपसी सहयोग से किसी भी आपदा का मजबूती से सामना किया जा सकता है।

ईरान बोला- अमेरिका का एमक्यू-9 ड्रोन मार गिराया, वीडियो किया जारी

एजेंसी, वॉशिंगटन। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने खुजेस्तान प्रांत के अहवाज में अमेरिकी एमक्यू-9 रीपर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया।

ईरानी सरकारी मीडिया ने ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। आईआरजीसी के मुताबिक, उसने अपने नए डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को निशाना बनाया। हालांकि, अमेरिका ने अब तक न तो ड्रोन गिराए जाने के दावे की पुष्टि की है और न ही जारी वीडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। एमक्यू-9 रीपर अमेरिकी सेना का अत्याधुनिक मानव रहित ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हवाई हमलों के लिए किया जाता है। दूसरी ओर, अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने लगातार आठवीं रात ईरान के खिलाफ हवाई हमले किए। इससे पहले अमेरिका ने जानकारी दी थी कि जॉर्डन में ईरान के मिसाइल हमले में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, जबकि एक सैनिक लापता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों से रूस पर प्रस्तावित प्रतिबंध विधेयक में ईरान को भी शामिल

◆ अमेरिका ने लगातार 8वीं रात तेहरान पर बम बरसाए

◆ ट्रंप बोले- रूस प्रतिबंध विधेयक में ईरान को भी शामिल किया जाना चाहिए

करने की अपील की है। ट्रंप का कहना है कि रूस के खिलाफ तैयार किए जा रहे प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।

इस साल जनवरी में ट्रंप ने उस विधेयक का समर्थन किया था, जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इनमें चीन और भारत भी शामिल हैं। कुवैत में बिजली उत्पादन और वॉटर डीसेलिनेशन संयंत्र पर दो दिनों में दूसरी बार हमला हुआ है। हमले के बाद संयंत्र की कई बिजली उत्पादन इकाइयों में आग लग गई। कुवैत के बिजली, जल एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आग बुझाने के लिए टीमें मौके पर लगातार काम कर रही हैं। मंत्रालय के मुताबिक, आग से संयंत्र की बड़ी संख्या में बिजली उत्पादन इकाइयां प्रभावित हुई हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने और नुकसान का आकलन करने का प्रयास जारी है।

हर नागरिक को है विश्वास, संकट में साथ खड़ी है सरकार: योगी

मुख्यमंत्री ने बहराइच में मगरमच्छ की चपेट में आने से बच्चे की मौत पर जताया दुख

एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) मुख्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया।

यह भवन 200 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया और यहां लगाई गई प्रदर्शनी व भवन का अवलोकन कर कार्यों के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हर आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बनाना है, जहां प्रत्येक नागरिक यह विश्वास लेकर जीवन जी सके कि संकट की खड़ी में सरकार के साथ वह भी तैयार है। यह नागरिक व राष्ट्रीय कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए। सीएम ने उम्मीद

◆ सीएम ने प्राधिकरण की वेबसाइट का शुभारंभ किया

जताई कि यह केंद्र हर नागरिक के मन में नए विश्वास का जागरण करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राय: आपदा व जनधन की व्यापक हानि के बाद हम लोग सक्रिय होते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं लेकिन आपदा के प्रति पहले से सतर्कता, तैयारी व जागरूकता जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर पर ला सकती है। दैनिक जीवन, स्कूली पाठ्यक्रम व परिवार में संवाद के जरिए इसके बचाव के बारे में बताने की आवश्यकता है। सीएम ने बचपन का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय स्कूल व परिवारों में चर्चा होती थी कि आग, भूकंप, बाढ़ के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इन घटनाओं में असामान्य आचरण नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जागरूकता के जरिए इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए तो जनधन की हानि को नियंत्रित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने घटनाओं को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति को खतरनाक बताया। उन्होंने प्रशिक्षण पर जोर देते हुए कहा कि 45 हजार होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। जिन आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया है, उन्हें इस भर्ती में प्राथमिकता देंगे। होमगार्ड को भी आपदा मित्र का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

सीबीआई की बैंक धोखाधड़ी मामले में चार राज्यों में छापेमारी

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 1,109 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में चार राज्यों में छह स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित मेसर्स गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ दर्ज मामले में की गई। सीबीआई के अनुसार कंपनी पर केनरा बैंक से वित्तीय सुविधाएं लेने के दौरान स्टॉक मूल्य बढ़ाकर दिखाने, वित्तीय विवरणों में हेराफेरी व ऋण राशि के दुरुपयोग का आरोप है। तलाशी ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तराखंड में कंपनी के कार्यालयों, निदेशकों के आवास और विनिर्माण इकाइयों में ली गई। जांच एजेंसी ने कई दस्तावेज बरामद किए हैं।

काशी भारत की सनातन चेतना का शाश्वत प्रकाश, यहां कण-कण में शिव का वास: रेखा

एजेंसी, वाराणसी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने जन्मदिन पर रविवार को काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ और काशी के कोतवाल बाबा कालभैरव के दरबार में परिजनों के साथ विधिवत हाजिरी लगाई।

दो दिवसीय काशी प्रवास पर आईं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोनों मंदिरों में विधि विधान से दर्शन पूजन के बाद दिल्ली सहित पूरे देश में सुख समृद्धि की कामना कीं। काशी के दोनों मंदिरों में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि आज, अपने जन्मदिन पर, मुझे शाश्वत, अविनाशी और मोक्ष प्रदान करने वाली काशी में

◆ जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ व काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी

बाबा श्री काशी विश्वनाथ और काशी के कोतवाल श्री काल भैरव के पवित्र चरणों में दर्शन और पूजा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। काशी भारत की सनातन चेतना का शाश्वत प्रकाश है। यहां कण-कण में शिव का वास है, हर श्वास में भक्ति है और हर कदम पर आध्यात्मिकता का स्पंदन महसूस होता है। बाबा विश्वनाथ की कृपा और काल भैरव जी का संरक्षण अनादि काल से इस पवित्र भूमि और इसके भक्तों की शक्ति रहे हैं। मैं बाबा विश्वनाथ और श्री काल भैरव जी से प्रार्थना करत हूं कि वे सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, सबको सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली का आशीर्वाद दें, और भारत निरंतर वैभव, गौरव और नई उपलब्धियों के शिखर को छूता रहे।

हरियाणा में जमीन के रिकॉर्ड होंगे पूरी तरह डिजिटल: सीएम सैनी

एजेंसी, पंचकूला। हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग में डिजिटल बदलाव की रफ्तार तेज कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को हरियाणा निवास में राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व से जुड़ी सभी सेवाएं तकनीक आधारित, पारदर्शी और तय समय सीमा में उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने सभी उपायुक्तों से कहा कि राजस्व शिकायतों के निपटान की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए तथा भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण का काम मिशन मोड में पूरा किया जाए। सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों को बिना किसी अनावश्यक देरी के सरल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त,

◆ भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण पर जोर, तय समय में सेवाएं देने के निर्देश

नगर निगम आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने शिकायत निवारण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर अस्वीकृत आवेदन में स्पष्ट कारण दर्ज किया जाए तथा उसकी समय-समय पर रैंडम जांच भी हो, ताकि कोई पात्र व्यक्ति प्रक्रियागत त्रुटि के कारण लाभ से वंचित न रह जाए। साथ ही सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि साप्ताहिक समाधान शिविरों में तहसीलदार और राजस्व अधिकारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहें, ताकि मौके पर ही समस्याओं का समाधान हो सके।

मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की

संसद में हंगामे की जगह रचनात्मक बहस जरूरी: रिजिजू

एजेंसी, नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले रविवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में सहयोग की अपील की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सरकार ने विपक्ष से महत्वपूर्ण विधेयकों पर सार्थक चर्चा और सकारात्मक सहयोग का आग्रह किया। बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने अलग गुट बनाने वाले सदस्यों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। विरोध स्वरूप विपक्ष के कुछ नेताओं ने कुछ समय के लिए सांकेतिक बहिर्गमन भी किया। हालांकि, बाद में वे बैठक में वापस लौट आए और चर्चा में शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से बुलाई गई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, संसदीय

◆ आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, 19 बैठकों का प्रस्ताव

कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एलमुरुगन सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में 40 राजनीतिक दलों के कुल 58 नेताओं ने हिस्सा लिया। संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, बैठक की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रारंभिक टिप्पणी से हुई। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक का संचालन किया। बैठक के समापन पर रक्षा मंत्री ने सभी नेताओं को उनकी उपस्थिति, सुझाव और सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार संसद के नियमों के तहत अनुमत सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वह आगामी सत्र के दौरान विधायी कार्यों में रचनात्मक भूमिका निभाएं। संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर अपने विचार रखे। कई दलों ने सरकार के समक्ष अपनी प्राथमिकताएं और चिंताएं साझा कीं। सरकार ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुनने की बात कही। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी दलों से संसद को सुचारु रूप से चलाने और विधेयकों पर सार्थक चर्चा में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। मानसून सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करने जा रही है और विपक्ष से आग्रह किया गया है कि वह इन पर सकारात्मक चर्चा कर उन्हें पारित कराने में सहयोग करे। रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र में सभी दलों को अपनी बात रखने का अधिकार है। केवल हंगामा करने और चर्चा से दूर रहने से किसी भी दल को राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र सोमवार, 20 जुलाई से शुरू होगा और सरकारी कामकाज की आवश्यकता के अनुसार यह 13 अगस्त तक चल सकता है। इस दौरान 25 दिनों की अवधि में कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट बोला- वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं, अगली सुनवाई 24 को

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा- स्वास्थ्य बिगड़ने और डिवीजन बेंच के आदेश के कारण उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

सरकार की इस कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। वांगचुक को वहीं दवाएं दी जा रहीं, जिसमें उनकी रजामंदी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ पुलिस को 3 दिन में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। दरअसल सोनम की पत्नी गीतांजलि ने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करने की मांग की थी। मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। दिल्ली पुलिस शनिवार सुबह वांगचुक को जंतर-मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। अस्पताल में भी वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है। सीजेपी और वांगचुक 28 जून

◆ सरकार-पुलिस से तीन दिन में जवाब मांगा अंतरिम आदेश नहीं दिया

से नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के समर्थन में आमरण अनशन पर हैं। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने कहा, सरकार ने कहा कि उनकी तबीयत बिगड़ रही थी इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यह दावा सही नहीं है। सबसे पहले, उनकी तबीयत बिलकुल नहीं बिगड़ रही थी। एक शाम पहले की मेडिकल रिपोर्ट देखें तो सब कुछ सामान्य था। उनका पोटैशियम स्तर 4.3 था और बाकी सभी पैरामीटर भी सामान्य थे।

ऐलान निवेशकों को हिमाचल आने का न्योता, सरकार देगी हरसंभव सहयोग, हरित हाइड्रोजन व आईटी सेक्टर पर फोकस

नई औद्योगिक नीति में उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली: सीएम सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार नई औद्योगिक नीति लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस नीति में उद्योगों के लिए बिजली की दरें कम रखने का प्रावधान किया जाएगा, जिससे राज्य में निवेश बढ़े।

उन्होंने निवेशकों से हिमाचल प्रदेश में उद्योग लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य निवेश के लिए देश के सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक है और सरकार उद्योगों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शनिवार देर शाम चंडीगढ़ में आयोजित चंडीगढ़ लीडरशिप कॉन्क्लेव और टाई (द

इंडस एंटरप्रेन्योर्स) चंडीगढ़ की 23वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध है। राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिजली की दरों में राहत देने जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश हरित हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में काम कर रहा है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बायोचार संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। किन्नौर

जीएसटी के बाद औद्योगिक राजस्व में भारी गिरावट

मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पहले प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों से राज्य को करीब चार हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था, जो जीएसटी लागू होने के बाद घटकर लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए रह गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपनी औद्योगिक नीतियों में बदलाव कर रही है।

जिले में भू-तापीय ऊर्जा परियोजना भी स्थापित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बिजली उत्पादन के मामले में अधिशेष राज्य है। इसी कारण पंजाब के साथ तीन वर्ष के बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। उन्होंने पंजाब को हिमाचल का 'बड़ा भाई' बताते हुए कहा कि दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध हैं और भविष्य में भी हिमाचल पंजाब को बिजली की आपूर्ति करता रहेगा। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए भी हिमाचल प्रदेश अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। राज्य सरकार डेटा स्टोरेज से जुड़ा बुनियादी ढांचा विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। सोलन जिले के कंडाघाट में आईटी पार्क विकसित किया जा रहा है।

हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध सरकार: सीएम धामी

एजेंसी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी होटल में शाइन अवी लर्निंग के 'समावेशी शिक्षा मिशन-2030' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विजुअल लर्निंग करिकुलम पर आधारित विभिन्न पुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल शिक्षा को अधिक सरल, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य बच्चों में समझ, नवाचार, आत्मविश्वास और जीवनोपयोगी कौशल विकसित करना

◆ 'समावेशी शिक्षा मिशन-2030' का किया शुभारंभ

है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, पीएम श्री विद्यालय, अटल उत्कृष्ट विद्यालय, डिजिटल शिक्षण सामग्री तथा विज्ञान एवं नवाचार आधारित शिक्षा को बढ़ावा दे रही है।

समावेशी शिक्षा को मजबूत करने के लिए विद्यालयों में रैंप, रेलिंग, सुगम शौचालय, अनुकूलित फर्नीचर और स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। धामी ने कहा कि प्रदेश में लगभग 5,800 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विभिन्न स्तरों पर विद्यालयों में पंजीकृत हैं।

राज्य सरकार के 11 विशेष विद्यालयों के माध्यम से 1,300 से अधिक बच्चों को विशेष शिक्षण एवं पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर 300 से अधिक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा शेष रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वह नए भारत के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके।

सेब बागीचों में बढ़ा फफूंद जनित रोगों का खतरा, बागवानों ने सरकार से लगाई गुहार

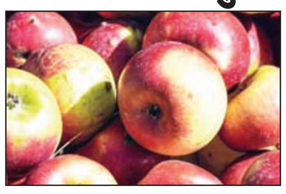

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रदेश के सेब बागीचों में इस बार मौसम की मार और कम उत्पादन की चिंता के बीच अब फफूंद जनित रोगों ने बागवानों की परेशानी बढ़ा दी है। शिमला जिले के रोहड़ू, जुब्बल और कोटखाई क्षेत्रों में अल्टरनेरिया और मार्सोनिना रोग तेजी से फैल रहे हैं। इसके अलावा किन्नौर और कुल्लू के कुछ क्षेत्रों से भी इन रोगों के लक्षण सामने आए हैं।

बागवानों के अनुसार, रोगों के कारण सेब के पेड़ों की पत्तियां समय से पहले पीली होकर गिर रही हैं। पत्तियां झड़ने से पेड़ों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता प्रभावित हो रही है, जिससे फलों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा। इसका सीधा असर सेब के आकार, रंग और गुणवत्ता पर पड़ने की आशंका है। बागवानों का कहना है कि इस वर्ष पहले ही सेब उत्पादन में कमी की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में रोगों का बढ़ता प्रकोप उनकी चिंता को और बढ़ा रहा है। भारतीय किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष और प्रगतिशील बागवान सुरेश ठाकुर ने सरकार से मामले को गंभीरता से लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था में सेब का महत्वपूर्ण योगदान है और लाखों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी है। उन्होंने बागवानी विभाग से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करवाकर वैज्ञानिक आधार पर रोग नियंत्रण की रणनीति तैयार करने की मांग की। सुरेश ने बताया कि रोहड़ू और आसपास के जंगलों में पाए जाने वाले फेकड़े नामक जंगली पौधों पर भी रोग का असर देखा जा रहा है। उन्होंने संक्रमण के स्रोत की पहचान के लिए जंगलों का सर्वे करवाने की मांग की है। बागवानों ने बाजार में उपलब्ध फफूंदनाशक दवाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, अल्टरनेरिया रोग में पत्तियों पर काले या भूरे धब्बे बनने लगते हैं, जबकि मार्सोनिना रोग में पत्तियों पर काले धब्बे पड़ने के बाद वे समय से पहले गिरने लगती हैं। गंभीर संक्रमण से वर्तमान फसल के साथ अगले वर्ष के उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है।

1949 में स्थापित 'लाजपत राय वाटर वर्क्स' टाहलीवाल जलापूर्ति योजना बनेगी हेरिटेज म्यूजियम

विंटेज मशीनरी का होगा पुनर्संरक्षण : अग्निहोत्री

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सन् 1949 में स्थापित ऐतिहासिक 'लाजपत राय वाटर वर्क्स' टाहलीवाल जलापूर्ति योजना को 'वाटर सप्लाई हेरिटेज म्यूजियम' के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना के ऐतिहासिक पंप हाउस, उसमें स्थापित विंटेज पंपिंग मशीनरी, तकनीकी अभिलेखों तथा जलापूर्ति व्यवस्था से जुड़ी धरोहर का पुनर्संरक्षण कर संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने शनिवार को योजना का निरीक्षण करने के उपरांत जल शक्ति विभाग को आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पंप हाउस में आज भी उस समय की विशाल विंटेज पम्पिंग मशीनें, फ्लाई-व्हील संचालित उपकरण तथा मूल संरचना सुरक्षित है, जो तत्कालीन अभियंत्रिकी कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन सभी ऐतिहासिक धरोहरों को यथावत संरक्षित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध पुरानी एवं ऐतिहासिक जलापूर्ति मशीनरी को भी यहां लाकर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि प्रदेश में पेयजल व्यवस्था के विकास की ऐतिहासिक यात्रा को एक स्थान पर संजोया जा सके।

1949 में हुआ था योजना का उद्घाटन

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक योजना का उद्घाटन 6 दिसंबर 1949 को तत्कालीन पूर्वी पंजाब के राज्यपाल सर चंदूलाल एम. त्रिवेदी ने किया था। उस समय योजना का नाम 'लाजपत राय वाटर वर्क्स' रखा गया था। इसका निर्माण तत्कालीन लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा कराया गया था तथा इसमें स्थापित मशीनरी विशेष रूप से इंग्लैंड से मंगवाई गई थी। उन्होंने बताया कि यह योजना उस समय बीत क्षेत्र के 31 गांवों की लगभग 20 हजार आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई थी। इसमें 156 हॉर्स पावर के दो रसटन डीजल इंजन स्थापित किए गए थे, जिनके माध्यम से वर्ष 1974 तक पेयजल की आपूर्ति होती रही।

नई पीढ़ी को मिलेगा इतिहास से जुड़ने का अवसर

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हेरिटेज म्यूजियम के रूप में विकसित होने के बाद यह परिसर विद्यार्थियों, अभियंताओं, शोधकर्ताओं और आम लोगों के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। यहां ऐतिहासिक पंप हाउस, विंटेज मशीनरी, तकनीकी अभिलेखों तथा प्रदेश में जलापूर्ति व्यवस्था के विकास से जुड़े दस्तावेजों को संरक्षित कर प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियां प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी के इतिहास और उस दौर के अभियंताओं एवं अधिकारियों के योगदान को निकट से जान सकेंगी।

आजादी के बाद की तकनीकी विरासत का जीवंत उदाहरण

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के समय की परिस्थितियों का अंदाजा इस योजना से लगाया जा सकता है। सीमित संसाधनों में तैयार की गई यह परियोजना उस दौर की तकनीकी दक्षता और दूरदर्शिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में आधुनिक पेयजल योजनाएं कार्य कर रही हैं, लेकिन यह ऐतिहासिक योजना दशकों तक बीत क्षेत्र के लोगों के लिए जीवनरेखा बनी रही और प्रदेश में जलापूर्ति व्यवस्था की मजबूत नींव रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बेटी ने पूरा किया पिता का सपना, प्रतिमा ने मंडी में संभाला बीडीओ का कार्यभार

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। भारत सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता व हिमाचल प्रदेश वुशू एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल मनहंस की छोटी बेटी प्रतिमा मनहंस ने अपने पिता के सपने को साकार करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

प्रतिमा ने वर्ष 2025-26 में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हिमाचल प्रशासनिक सेवा (एचएएस) परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रतिमा मनहंस ने जिला मंडी के चौंतड़ा में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के पद पर अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। वह बिलासपुर जिले के बरमाना क्षेत्र की पहली एचएएस अधिकारी बनी हैं। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। प्रतिमा की माता मंजू मनहंस भी बरमाना पंचायत की प्रधान रह चुकी हैं। पिता शिवपाल मनहंस ने कहा कि उनकी बेटी ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उन्हें अपनी बेटी की सफलता पर गर्व है।

माता मंजू मनहंस ने कहा कि प्रतिमा बचपन से ही मेधावी और लक्ष्य के प्रति समर्पित रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वह ईमानदारी और निष्ठा के साथ समाज की सेवा करेगी। शिवपाल मनहंस वायुसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अधिवक्ता के रूप में सेवाएं दे चुके हैं और प्रदेश सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर भी कार्य कर चुके हैं।

चौपाल विकास कार्यों में बनेगा नंबर वन : विक्रमादित्य

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। चौपाल विधानसभा के एकदिवसीय दौरे के दौरान ननहार में आयोजित विशु मेले के समापन समारोह में लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

इस दौरान उन्होंने हियून से नगाह और चाड़वाधार से गौनचा दो सड़कों का लोकार्पण कर क्षेत्र वासियों को सौगात दी। उन्होंने कहा कि चौपाल क्षेत्र के विकास में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का अहम योगदान है। प्रदेश में वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में यहां के लोगों को विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान सकारात्मक सोच के साथ अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए कार्य करें। इस विधानसभा के सभी जनप्रतिनिधि मिलकर कार्य करें, ताकि प्रदेश भर में चौपाल की पहचान विकास कार्य में नम्बर वन बन सके। उन्होंने कहा कि 350 करोड़ रुपए की लागत से पूरे विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग विकास कार्य करवा रहा है। छैला-नेरी पुल-यशवंत नगर सड़क के लिए 250 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है।

केंद्र सरकार जैसे ही इस सड़क को मंजूरी देगी, इस सड़क का कार्य शुरू किया जाएगा। एचपी रेडी प्रोजेक्ट के तहत 1400 करोड़ रुपए से विभिन्न सड़कों को बनाने की योजना है। इस प्रॉजेक्ट में चौपाल की सड़कें भी शामिल की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिलना गर्व की बात है। केंद्र सरकार ने 3500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पैकेज तीन के तहत प्रदेश को दिए है। इसी के तहत चौपाल विधानसभा में 17 सड़कें बननी प्रस्तावित हैं। ये सड़के 133 किलोमीटर बनेगी जिन पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के चरोग से अनुसूचित जाति बस्ती क्टोट सड़क, पटवार खाना झीणा सड़क को लोक निर्माण विभाग टेकओवर करेगा, चंबी से दियुंदर मंदिर मार्ग, ननहार पंचायत के सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य जिलाधीश के माध्यम से पूर्ण करवाया जाएगा। खेल मैदान ननहार का विस्तारीकरण सहित पंचायत की ओर से रखी गई अन्य सभी मांगो पर सकारात्मक कदम उठाएं जाएंगे। स्थानीय नेता रजनीश किमटा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विशु मेला हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है।

चिंतपूर्णी में भाजपा को झटका, उपप्रधान समेत 22 लोग कांग्रेस में हुए शामिल

भारतेन्दु संवाददाता, अंब। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। ग्राम पंचायत घेवट बेहड़ में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपप्रधान समेत करीब 22 लोगों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया।

यह कार्यक्रम पंजोआ स्थित विधायक कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां स्थानीय कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह बबलू की मौजूदगी में सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले भी जबेहड़ क्षेत्र में 17 लोग भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस में शामिल होने वालों में उपप्रधान रविंद्र कुमार, वार्ड सदस्य दीपक कुमार, हरिंद्र सिंह, बलविंदर सिंह, अनमोल ठाकुर, अर्जुन देव, मनीष कुमार, राजिंद्र, राहुल, जसबीर ठाकुर, महिंद्र सिंह, विजय कुमार, सीमा देवी, सुषमा देवी, मधु बाला, सुरिंद्रा कुमारी, श्वेता कुमारी, राज रानी, अनीता कुमारी, ज्योति, रानी, शौर्य ठाकुर और मोहित कौंडल शामिल हैं। नए शामिल हुए सदस्यों का कहना है कि भाजपा अब अपनी मूल विचारधारा से भटक चुकी है और पार्टी के अंदर कई गुट बन गए हैं। कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने सभी नए साथियों को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया और कहा कि जमीनी स्तर के जनप्रतिनिधियों के जुड़ने से कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी को पार्टी में पूरा मान-सम्मान दिया जाएगा।

महिला नेतृत्व से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा : रोहित

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कोटखाई क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुम्मा में खंड विकास समिति (कोटखाई) की नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय राजटा एवं स्थानीय जनता तथा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आभार समारोह की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने विजय राजटा को खंड विकास समिति की प्रथम अध्यक्षा बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि विजय राजटा निश्चित रूप से जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। रोहित ने कहा कि हाल ही में संपन्न पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में महिला शक्ति का प्रभावशाली उदय देखने को मिला है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि तीनों जिला परिषद सीटों पर महिलाओं ने विजय हासिल की है। इसके अलावा विजय राजटा खंड विकास समिति कोटखाई की प्रथम अध्यक्षा बनी हैं, नगर पंचायत जुब्बल की अध्यक्षा अनीता चौहान तथा खंड विकास समिति जुब्बल की अध्यक्षा कमलेश झगटा भी निर्वाचित हुई हैं।

उन्होंने कहा कि अनेक पंचायतों में भी महिलाओं ने प्रधान एवं उपप्रधान पदों पर जीत दर्ज कर समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में संतुलित एवं योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि गुम्मा आज उबादेश, पुडग, बलसन तथा हिमरी क्षेत्रों का एक प्रमुख बाजार एवं केंद्र बिंदु बनकर उभरा है। इसी दृष्टिकोण से यहां सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुम्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत किया गया है तथा इस स्वास्थ्य संस्थान तक जाने वाली सड़क को शीघ्र ही पक्का किया जाएगा, जिस पर लगभग 9 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रगतिनगर स्थित तकनीकी शिक्षा संस्थान क्षेत्र का सबसे बड़ा तकनीकी शिक्षण संस्थान है, जहां लगभग 1200 विद्यार्थी विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं। संस्थान के व्यापक उन्नयन के लिए 110 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

एबीवीजीआईईटी को तकनीकी शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनाने पर जोर : डॉ. अभिषेक

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने जिला शिमला के प्रगतिनगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एबीवीजीआईईटी) का दौरा किया।

उन्होंने संस्थान की शैक्षणिक, प्रशासनिक, अनुसंधान और आधारभूत संरचना से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की। डॉ. जैन ने इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और आईटीआई विंग के संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने संस्थान को और मजबूत बनाने के लिए शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में मानव संसाधन को सुदृढ़ करने, छात्र कल्याण निधि के बेहतर उपयोग, केंद्रीय पुस्तकालय में अधिक पुस्तकों और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने, प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण तथा अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोगशाला स्थापित करने पर चर्चा की गई। प्रधान सचिव ने कहा कि विद्यार्थियों को उद्योगों की कार्यप्रणाली से जोड़ने के लिए शैक्षणिक एवं औद्योगिक भ्रमण करवाए जाएं। उन्होंने संकाय सदस्यों द्वारा नियमित मार्गदर्शन, व्यक्तित्व विकास और सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। साथ ही शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए 'टॉपर गैलरी' जैसी पहलों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने परिसर विकास के लिए कक्षाओं के उन्नयन, खेल सुविधाओं के विस्तार, इनडोर जिम्नेजियम की स्थापना, हरित परिसर और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने को कहा। संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय एजेंसियों से अनुसंधान अनुदान प्राप्त करने और उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। डॉ. जैन ने कहा कि एबीवीजीआईईटी को शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और उद्योग साझेदारी के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।

बैहना वार्ड को नगर निगम मंडी से बाहर निकालने की उठी मांग

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। नगर निगम मंडी के वार्ड नंबर-14 बैहना को निगम से बाहर करने की मांग एक बार फिर उठने लगी है। रविवार को बैहना वार्ड के ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी से मिला व उन्हें ज्ञापन सौंपकर वार्ड को नगर निगम से बाहर कर दोबारा पंचायत में शामिल करने की मांग रखी। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव से पहले भी उन्होंने अपनी मांग पूर्व मंत्री के समक्ष रखी थी, लेकिन उस समय आचार संहिता लागू होने के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका था। उन्होंने आरोप लगाया कि बैहना को निगम में शामिल करने का वे शुरू से विरोध कर रहे हैं। हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में भी ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप चुनाव का बहिष्कार किया था। पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मुख्यमंत्री से समय लेकर ग्रामीणों की मांग उनके समक्ष रखी जाएगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो भविष्य में भी वे चुनावों का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे।

भल्लू पुल बस हादसे में मृतकों की स्मृति में बनेगा 'श्री सिद्ध चानों सच्ची सरकार' मंदिर

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। पिछले वर्ष 7 अक्तूबर को बरठीं के समीप भल्लू पुल के पास हुए दर्दनाक बस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मिक शांति के लिए घटनास्थल के पास 'श्री सिद्ध चानों सच्ची सरकार' मंदिर का निर्माण किया जाएगा।

मंदिर निर्माण की आधारशिला और भूमिपूजन 25 जुलाई को किया जाएगा। झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल मंदिर की नींव रखेंगे। इस अवसर पर भंडारे और धहाजे का आयोजन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते वर्ष 7 अक्तूबर को भल्लू पुल के पास पहाड़ी दरकने से मलबे की चपेट में आने से एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में बस में सवार 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग घायल हुए थे। हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। 'श्री सच्ची सरकार जनकल्याण समिति कोटलू' की ओर से दुर्घटनास्थल के समीप मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। रविवार को समिति के अध्यक्ष कुलदीप कुमार और प्रदीप कुमार सहित क्षेत्र के लोगों ने झंडूता विधायक जीतराम कटवाल से मुलाकात कर उन्हें भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। विधायक जीतराम कटवाल ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि भल्लू पुल हादसा बेहद दुखद और पीड़ादायक था। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों को हुए नुकसान की भरपाई कभी नहीं की जा सकती। इस दुख की घड़ी में पूरे क्षेत्र और प्रदेश की जनता ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह दिवंगत आत्माओं की स्मृति को चिरस्थायी बनाने, मानव सेवा और लोककल्याण का संकल्प है। यह धार्मिक स्थल आने वाली पीढ़ियों को आस्था, सेवा और प्रकृति के प्रति सजग रहने का संदेश देगा। उन्होंने ऐसे जनकल्याणकारी कार्यों में सभी से सहयोग की अपील की।

25 जुलाई को विधायक जीतराम कटवाल करेंगे मंदिर का भूमिपूजन

गांधी परिवार की चापलूसी से सत्ता में बने रहने के लिए संस्थानों के नाम बदल रहे सुक्खू : जयराम

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि साढ़े तीन साल से ज्यादा के कार्यकाल में बताने के लिए सुक्खू सरकार के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है इसीलिए वह गांधी परिवार की चापलूसी करने के लिए हिमाचल में पहले से चल रहे संस्थानों के नाम गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर रख रही है।

इसी तरीके से अपने नाम और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम से भी सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू कीं, लेकिन वह प्रदेशवासियों के साथ किसी छलावे से कम नहीं थीं। इन योजनाओं से ज्यादा धनराशि उनके प्रचार-प्रसार पर खर्च की गई। लोग फॉर्म भर कर प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना के पैसे का इंतजार कर रहे हैं और सुख की सरकार आए दिन पात्रता शर्तें बदल कर उन्हें गुमराह कर रही है।

साढ़े तीन साल से ज्यादा के कार्यकाल में सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर ढाई हजार से ज्यादा संस्थान बंद करने, पूर्व सरकार की योजनाओं का बजट रोकने, डेढ़ लाख से ज्यादा पद समाप्त करने, 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकालने, किसान, बागवानों और महिलाओं को ठगने, देश-विदेश में घूम-घूमकर झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है। पक्की नौकरी सरकार दे नहीं रही है और कच्ची नौकरी के सारे रास्ते बंद कर रही है।

हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र लिख रहे हैं विकास की नई इबारत

दुर्गम क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार को मिला नया संबल

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में विकास की नई तस्वीर उभर रही है। लाहौल-स्पीति, किन्नौर, पांगी व भरमौर जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, कम जनसंख्या और लंबे समय तक बर्फबारी जैसी चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे, महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 42.49 प्रतिशत हिस्सा हैं, जबकि यहां करीब 3.92 लाख लोग निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होने के बावजूद सरकार ने सभी स्थायी और मौसमी जनजातीय बस्तियों में बिजली और सुरक्षित पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए सरकार हर वर्ष कुल बजट का नौ प्रतिशत हिस्सा ट्राइबल सब-प्लान (एसटीपी) के तहत निर्धारित कर रही है। वर्ष 2024-25 में 890.28 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 में 638.73 करोड़ रुपए जनजातीय विकास के लिए आवंटित किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने छात्रवृत्तियों और संस्थागत सुविधाओं का विस्तार किया है। वर्ष 2025-26 में हजारों विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। प्रदेश के चार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 1,008 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा छात्रावास, पुस्तकालय और शिक्षकों के आवास जैसी सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में दो जिला अस्पताल, छह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 49 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 123 स्वास्थ्य उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं। लाहौल-स्पीति और भरमौर में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना से विशेषज्ञ चिकित्सकों, आधुनिक जांच सुविधाओं और बेहतर चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ी है। युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार और आजीविका योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में 815 जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 577 युवाओं ने रोजगार प्राप्त किया या अपना व्यवसाय शुरू किया। स्वयं सहायता समूहों और अन्य योजनाओं के माध्यम से 3,234 महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं।

पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा को रोजगार के नए माध्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। होम-स्टे योजनाओं और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है। पांगी घाटी को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित कर रसायनमुक्त खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

ई-गवर्नेंस व टेलीमेडिसिन से ग्रामीणों को मिल रही बेहतर सुविधाएं

डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के लिए भारतनेट परियोजना के तहत 3,793 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है, जिससे 705 ग्राम पंचायतें डिजिटल नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। इससे ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा और बैंकिंग सेवाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। सरकार जनजातीय क्षेत्रों में विकास के साथ-साथ संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। संग्रहालयों, सामुदायिक सुविधाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य जनजातीय समुदायों को आत्मनिर्भर बनाते हुए संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

कार्यालय ग्राम पंचायत हटवाड़
विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

निविदा सूचना

वर्ष 2026-2027 में ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए निर्माण सामाग्री कुटेशन आमंत्रित की जाती हैं।

क्रं. सं.	समाग्री	प्रति घन मीटर	दर in figure	दर in Words
1.	रेता प्लांट			
2.	बजरी क्रैसर 10 एम एम से 25 एम एम			
3.	रेता क्रैसर			
4.	बजरी क्रैसर 40 एम एम			
5.	सोलिंग			
6.	कट स्टोन 90 एम एम से 120 एम एम			
7.	पक्की ईट 2 क्लास			
8	सैटरिंग लैंटर दीवार, रास्ता			
9	पानी टैंकर			
10	जेसीबी			
11.	पी बी सी पाईप 63 एम एम से 110 एम एम 90.75 एम एम पाईप			
12.	पी बी सी पाईप सॉकेट व एलवो			
13.	मिक्चर मशीन / दिन बजरी दिलाने बाला			
14.	हैम्बर डील मशीन			
15.	बजरी क्रैसर 63 एम एम			
16.	एच डी पी पाईप			
17.	सीमेंट किराया सीविल सप्लाई स्टोर घुमारवीं से हटवाड़ पंचायत कार्यस्थल			
18.	फर्नीचर कुर्सी टेवल मेज सोफा अलमारी दीवान			

निविदाकर्ता के लिए शर्तें- 1. निविदाकर्ता का GST Registration होना आवश्यक है। GST No. की प्रति साथ में संलग्न करना आवश्यक है। 2. सामग्री कार्य स्थल पर पहुंचानी होगी। 3. ग्राम पंचायत में सप्लाई की गई सामग्री बिल की अदायगी तकनीकी मूल्यांकन के बाद होगी। 4. कुटेशने केवल 31-03-2027 तक मान्य होंगी । 5. सामग्री की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। 6 सामग्री की गुणवता सही न होने के कारण सामग्री की अदायगी नहीं की जाएगी। 7 यदि स्पलायर समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं करवाता है तो स्पलायर की निविदा पंचायत तुरंत प्रभाव से बिना कारण के रद कर सकती है। व जो प्रतिभूति 100000.00 प्रधान ग्राम पंचायत के नाम ली जाएगी वह जब्बत कर ली जाएगी। 8. हर बिल के साथ एम फार्म की प्रति साथ में संलग्न की जाएगी। दिनांक 24-07-2026 को सायं 5 बजे तक स्वीकार की जाएगी तथा 25-07-2026 को 12:00 बजे खोली जाएगी।

प्रधान/सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत हटवाड़
विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

कार्यालय ग्राम पंचायत लघढ़याणा कशल
विकास खंड बालीचौकी, जिला मंडी (हि.प्र.)

निविदा सूचना

सर्व सम्मति से पारित किया जाता है। कि ग्राम पंचायत लघढ़याणा कशल विकास खंड बालीचौकी जिला मंडी हि.प्र. हेतु निविदाएं आमंत्रित करती है कि वर्ष 2026-27 हेतु नदी रेट, क्रशर रेत, बजरी, स्टोल ढलवान, शंटरिंग, ईंटें, हार्डवयेर का पूरा सामान, जे. सी. बी. क्युवमीटर में, साइनबोर्ड 2×3 व 2×4 व क्रैटवायर व सामग्री ढलवान ट्रैक्टर जीप, टिपर, खच्चर ढलवान, सीमेंट ढलवान इत्यादि के लिए निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं। निविदाएं बंद लिफाफे में कार्यालय नाम पंचायत लघढ़याणा कशल में दिनांक 25/7/26 तक डाक द्वारा पंहुचानी चाहिए। निविदाएं 28/7/26 को सुवह 11 बजे निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष पंचायत कार्यालय लघढ़याणा में खोली जाएंगी।

1. निविदादाता के पास अपना जीएसटी पंजीकरण पैन संख्या, लॉग बुक होना आवश्यक है। 2. आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग के एम. फार्म जमा करवाने होंगे। 3. दरें अंकों व शब्दों में टैक्स इनक्युडिंग का उल्लेख देना आवश्यक है। 4. निविदादाता यदि सामग्री समय पर नहीं कर पाता है तो पंचायत अगले क्रम को आदेश जारी करेगी। 5. साइन बोर्ड कार्यस्थल पर बैंडर द्वारा पहुंचाने व लगाकर देने होंगे।

1. गाड़ी स्टेशनों के नामः- पुरे पंचायत क्षेत्र में रेत नदी, रेत क्रशर, बजरी, सीमेंट ढलवान का एक समान रहेगा।

2. खच्चर ढलवान स्टेशनों के नामः- ब्यौरा निम्न प्रकार से है। 1. भाशली भलऊण से मलारी, 2. लघढ़याणा से शडुली, 3. सड़क से कशल, 4. शाकरी नाला से हिऊणा, 5. सड़क जुही से पंजाई, 6. सड़क से ढंढुधी धार, 7. सड़क से मुहाप, 8. सड़क से रोपा गाड. 9. शाईबीड़ से गाड़।

अतः पंचायत प्रधान के पास निविदाएं बिना शर्ते बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार होगा। और न्यूनतम मूल्य एवं गुणवत्ता के आधार पर काम दिया जाएगा। सामग्री खरीद का अंतिम मूल्य निर्णय विभाग की जस्टीफिकेशन व अनुमोदित निविदाओं के साथ नेगोशियन अनुसार ही किया जाएगा। किसी कारण वश क्षती होने के उपरान्त तिथि को बदला जा सकता है। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया जाता है। अतः प्रस्ताव आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

सचिव/प्रधान
ग्राम पंचायत लघढ़याणा
बालीचौकी विकस खंड बालीचौकी, जिला मंडी (हि.प्र)

मानसिक शांति स्वस्थ समाज की आधारशिला : डॉ. चिन्मय पंड्या

- योग, ध्यान और मूल्यपरक जीवन से तनाव दूर करने का दिया प्रशिक्षण
- शांतिकुंज में पुलिसकर्मियों को मिला तनाव प्रबंधन और सकारात्मक जीवन का प्रशिक्षण

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में उत्तराखंड यातायात पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय तनाव प्रबंधन शिविर का रविवार को समापन हुआ। शिविर में पुलिसकर्मियों को तनाव से मुक्ति, योग, ध्यान, सकारात्मक चिंतन और व्यक्तित्व विकास से जुड़े प्रशिक्षण दिए गए। देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉ. चिन्मय पण्ड्या ने मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को बेहतर कार्यक्षमता का आधार बताया।

विशेषज्ञों ने जीवन प्रबंधन और तनाव नियंत्रण के व्यावहारिक उपाय सिखाए। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने और जनसेवा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक हैं।

50 लाख की बैंक ठगी मामले में महिला समेत तीन गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के हरिद्वार में नगर कोतवाली पुलिस ने आईसीआईसीआई बैंक के एक खाताधारक के खाते से करीब 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी से निकासी के मामले का खुलासा करते हुए एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 लाख रुपये नकद, एक प्लॉट की रजिस्ट्री, एक स्कूटी, मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, आईसीआईसीआई बैंक की पुराना रानीपुर मोड़ शाखा के प्रबंधक अपूर्व दुबे की शिकायत पर आठ अक्टूबर 2025 को नगर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि एक खाताधारक के खाते से लगभग एक महीने के दौरान करीब 50 लाख रुपये के संदिग्ध लेनदेन हुए हैं।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा संपन्न उत्तराखंड के 700 श्रद्धालु लौटे

700 यात्रियों के साथ शुरू हुई सोमनाथ यात्रा का हर्रावाला में हुआ समापन

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड से गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ धाम के लिए निकली **सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा** रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। कई दिनों तक चली इस धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का दल सुबह हर्रावाला रेलवे स्टेशन पहुंचा। यात्रियों के वापस लौटने के साथ ही आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ी इस विशेष यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 700 श्रद्धालु शामिल हुए थे।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा को 13 जुलाई को हर्रावाला रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से रवाना किया गया था। विशेष रेल यात्रा के माध्यम से श्रद्धालुओं का दल गुजरात के सोमनाथ धाम पहुंचा। यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के साथ ही भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ना था। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया।

हर्रावाला से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचे श्रद्धालु

यात्रा के दौरान हरेला पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं ने शारदा पीठ परिसर में पौधरोपण भी किया। इस पहल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। श्रद्धालुओं ने कहा कि धार्मिक यात्रा के साथ पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण का संदेश देना एक सराहनीय प्रयास है। इससे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रकृति के महत्व को समझने की प्रेरणा मिलेगी। यात्रा से वापस लौटने के बाद अधिकांश श्रद्धालु हर्रावाला से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचे।

धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा बनी यादगार

श्रद्धालुओं ने इस सफल आयोजन के लिए गुजरात सरकार और उत्तराखंड सरकार के संस्कृति विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बेहतर व्यवस्थाओं के कारण यात्रा सुगम और यादगार बनी। यात्रियों ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा ने उत्तराखंड और गुजरात के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने का कार्य किया है।

यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं ने बताया कि सोमनाथ धाम के दर्शन उनके लिए अत्यंत भावपूर्ण और यादगार अनुभव रहा। उन्होंने भगवान शिव के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और देश की प्राचीन धार्मिक विरासत को करीब से महसूस किया। इसके अलावा श्रद्धालुओं को राम मंदिर, गीता मंदिर, श्री गोलोकधाम तीर्थ, बाणगंगा, भालका तीर्थ, त्रिवेणी संगम और सोमनाथ संग्रहालय जैसे महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिला।

श्रद्धालुओं ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें धार्मिक स्थलों के दर्शन के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और इतिहास की समृद्ध परंपराओं को समझने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा ने उनके मन में आध्यात्मिक शांति और सांस्कृतिक एकता की भावना को और मजबूत किया। यात्रियों ने इस आयोजन को जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया।

चमोली के तपोवन में जियोथर्मल ऊर्जा परियोजना की हुई शुरुआत

तपोवन जियोथर्मल परियोजना से बदलेगी ऊर्जा तस्वीर।

भारतेंदु संवाददाता, चमोली। उत्तराखंड ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चमोली जिले के तपोवन में जियोथर्मल (भू-तापीय) ऊर्जा परियोजना के वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य की शुरुआत कर दी है। परियोजना के लिए विश्व की अग्रणी आइसलैंड की जियोथर्मल विशेषज्ञ संस्था वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स की भारतीय सहयोगी फर्म को यूजेवीएन लिमिटेड ने परामर्शदाता नियुक्त किया है।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की ओर से रविवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम् ने बताया कि परामर्शदाता प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके आधार पर ड्रिलिंग, भू-वैज्ञानिक परीक्षण तथा अन्य तकनीकी अध्ययन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में भू-तापीय ऊर्जा नीति लागू की थी और जून 2026 में तपोवन परियोजना का अन्वेषण कार्य यूजेवीएन लिमिटेड को सौंपा गया।

यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह ने बताया कि अब तक के अध्ययन में तपोवन क्षेत्र एक मेगावाट की पायलट परियोजना तथा 10 मेगावाट की वाणिज्यिक जियोथर्मल विद्युत परियोजना के लिए उपयुक्त पाया गया है। परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यूजेवीएनएल ने उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का भी गठन किया है।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के फ्रीज जोन में राहत की तैयारी, 400 मीटर प्रतिबंधों की होगी समीक्षा

- रेल परियोजना क्षेत्रों की होगी नई समीक्षा

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना से जुड़े फ्रीज जोन में लागू 400 मीटर निर्माण प्रतिबंधों की समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि जहां रेलवे परियोजना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, वहां सुरक्षा मानकों के अनुरूप विकास गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से अनुमति देने की संभावनाएं तलाश की जाएंगी।

आवास विभाग की ओर से रविवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहां रेलवे निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और प्रतिबंधों में आंशिक शिथिलता दी जा सकती है।

विभाग के अनुसार ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण के दौरान सुरक्षा कारणों से नौ जनवरी 2024 को रेलवे कॉरिडोर के आसपास 400 मीटर क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित किया गया था। इसके तहत योगनगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, व्यासी, सिराला, तिलवाड़ मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारीदेवी, तिलनी, घोलतीर और गौचर सहित विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी। सरकार का कहना है कि इन प्रतिबंधों से रेलवे परियोजना की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, लेकिन कई क्षेत्रों में होटल, होमस्टे, रिसॉर्ट, आवासीय भवन और अन्य व्यावसायिक परियोजनाएं प्रभावित हुईं।

रुद्रपुर में नकली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़

भारतेंदु संवाददाता, रुद्रपुर। उत्तराखंड एसटीएफ और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने उधम सिंह नगर के बाजपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली एलोपैथिक दवाइयों के एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में लाखों की नकली जीवनरक्षक दवाइयां, पैकेजिंग मशीनें, भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब और आबकारी होलोग्राम बरामद किए गए हैं। इस मामले में मौके से बुलंदशहर निवासी धीरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया, जबकि पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आयुर्वेदिक और फूड लाइसेंस की आड़ लेकर नकली एलोपैथिक दवाइयों का निर्माण किया जा रहा था। सटीएफ के अनुसार आरोपित स्टैडमेड, मैक्लियोड्स, इंटास और सन फार्मा जैसी नामी कंपनियों के नाम और पैकेजिंग का इस्तेमाल कर नकली दवाइयां तैयार कर रहा था। फैक्ट्री से करीब एक लाख टैबलेट और 15 हजार सिरप की बोतलें बरामद हुईं। इनमें एंटीबायोटिक, एसिडिटी, दर्द, नसों की बीमारी, प्रोस्टेट, कैल्शियम और आयरन की कमी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शामिल हैं। छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकली दवाइयों के अलावा इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी जब्त की गई हैं।

उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी

प्रदेश में अगले दिनों तक भारी बारिश का खतरा, कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट प्रभावी

- नैनीताल, चंपावत और ऊधमसिंह नगर में अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता के चलते मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। नैनीताल, चंपावत और ऊधमसिंह नगर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी और कहीं-कहीं अत्यंत भारी वर्षा की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और बागेश्वर जिलों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है। प्रशासन ने मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

मौसम चेतावनी के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है। जिला आपदा परिचालन केंद्रों को चौबीस घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा राहत और बचाव दलों को तैयार रहने तथा भूस्खलन की आशंका वाले मार्गों पर आवश्यक मशीनरी उपलब्ध रखने को कहा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण सड़क मार्गों पर मलबा और पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों के साथ ही चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और सड़कों की स्थिति की जानकारी जरूर लें। आपात स्थिति में सहायता के लिए 112, 1070 और 1077 नंबरों पर संपर्क करने की सलाह दी गई है।

बारिश से पहाड़ों में आफत यमुनोत्री हाईवे मलबे से बंद

- भूस्खलन से यात्रा पर ब्रेक कई हाईवे हुए बाधित
- उत्तराखंड में मौसम का वार कई सड़कों पर संकट

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। यमुना घाटी में भारी बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे पर जगह-जगह भूस्खलन हो गया है। पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने के कारण कई स्थानों पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। स्यानाचट्टी और हनुमान चट्टी के बीच सड़क पर कटाव होने से स्थानीय लोगों के साथ ही यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की टीम हाईवे को खोलने के लिए लगातार काम कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मलबा हटाने और सड़क को यातायात के लिए सुरक्षित बनाने के प्रयास जारी हैं। मौसम में सुधार होने के बाद जल्द ही मार्ग खोलने की उम्मीद जताई जा रही है।

बारिश का असर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग पर कई जगह पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। सुरक्षा को देखते हुए घोड़ा-खच्चर संचालन पर रोक लगाई गई है। हालांकि श्रद्धालु सावधानी के साथ संकरे रास्तों से आवाजाही कर रहे हैं।

चमोली जिले में चीन सीमा क्षेत्र को जोड़ने वाला ज्योतिर्मठ-मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग भी मलबा गिरने से कुछ समय के लिए बंद रहा। अचानक पहाड़ी का हिस्सा टूटकर सड़क पर आने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें प्रभावित मार्गों को खोलने में जुटी हुई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है।

नकारात्मक प्रचार से निपटने के लिए संघ तैयार करेगा सोशल मीडिया योद्धा

सोशल मीडिया नैरेटिव की लड़ाई में उतरेंगे दक्ष स्वयंसेवक

- सोशल मीडिया के लिए तैयार हो रही विशेष टीम

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डिजिटल मंचों पर अपनी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सोशल मीडिया पर फैलने वाले विभिन्न प्रकार के प्रचार और नकारात्मक नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए संघ दक्ष स्वयंसेवकों की एक विशेष टीम तैयार कर रहा है। इसके लिए देहरादून में कई स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा चुके हैं। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से स्वयंसेवकों को सोशल मीडिया के उपयोग, सामग्री निर्माण और प्रभावी संवाद की जानकारी दी जा रही है।

वर्तमान समय में सोशल मीडिया लोगों तक जानकारी पहुंचाने का सबसे तेज माध्यम बन चुका है। किसी भी मुद्दे पर विचार और सूचनाएं कुछ ही समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती हैं। संघ का मानना है कि डिजिटल माध्यमों पर कई बार उसके संगठन और कार्यों को लेकर भ्रामक या नकारात्मक प्रचार किया जाता है। ऐसे में तथ्यों और सही जानकारी के आधार पर अपनी बात समाज तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की आवश्यकता महसूस की गई है।

संघ द्वारा तैयार की जा रही इस विशेष टीम में ऐसे स्वयंसेवकों को शामिल किया जाएगा जो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली को समझते हों। उन्हें सामग्री तैयार करने, उसे सही तरीके से प्रसारित करने और लोगों की प्रतिक्रियाओं को समझने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

टीम के सदस्य ऑनलाइन माध्यमों पर सक्रिय रहकर संघ के विचारों, सामाजिक कार्यों और राष्ट्र निर्माण से जुड़े प्रयासों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे।

हरिद्वार में लोगों ने युवक के गले में बांधा पट्टा, फिर की जमकर पिटाई

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने युवक को पकड़कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसके गले में पट्टा बांधकर दुर्व्यवहार किया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया और लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार यह घटना शनिवार दोपहर गणपति धाम कॉलोनी में हुई। शादाब नाम का युवक अपनी परिचित युवती से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने युवक को पकड़ लिया। आरोप है कि बिना किसी कानूनी कार्रवाई के लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। कॉलोनी में हंगामे की स्थिति बन गई। लोगों ने घायल युवक को संभाला और मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियां अंतिम दौर में

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। आगामी कांवड़ मेला-2026 को सुव्यवस्थित, सुगम और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में सभी संबंधित विभागों ने मेले की तैयारियां तेज कर दी हैं और कांवड़ पटरी मार्ग से लेकर पार्किंग स्थलों तक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग 25 जुलाई तक हर हाल में व्यवस्थाएं और सुविधाएं पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि शिवभक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पेयजल, शौचालय, सड़क, सफाई, पार्किंग और सुरक्षा से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं।

अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत महेश बिश्नोई ने बताया कि जिला पंचायत की ओर से कांवड़ पटरी मार्ग पर झाड़ी कटान के साथ-साथ स्थायी और अस्थायी शौचालयों की मरम्मत का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा बैरागी कैंप और अलकनंदा पार्किंग क्षेत्र में झाड़ी कटान और जेसीबी मशीनों के माध्यम से भूमि समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है।

जल निगम की ओर से बैरागी कैंप में शिवभक्तों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नई पेयजल लाइनें बिछाई जा रही हैं। अधिशासी अभियंता ने बताया कि यह कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

पौड़ी में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत,151 केंद्र बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर

पौड़ी गढ़वाल में स्वास्थ्य क्रांति, संस्थागत प्रसव 92 प्रतिशत तक पहुंचा।

भारतेंदु संवाददाता, पौड़ी, गढ़वाल। उत्तरांखंड के पौड़ी गढ़वाल में स्वास्थ्य क्रांति का असर धरातल पर दिखने लगा है, जहाँ संस्थागत प्रसव का आंकड़ा अब 92 प्रतिशत तक पहुँच गया है। सुरक्षित मातृत्व और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति बढ़ती जागरूकता के चलते न केवल मातृ-शिशु मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है, बल्कि जिले की चिकित्सा व्यवस्था भी एक नए मुकाम पर पहुंच गई है।

पौड़ी गढ़वाल जिले के वर्तमान मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) डॉ. शिव मोहन शुक्ला के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं में हुए सुधारों का सकारात्मक प्रभाव जनपद के स्वास्थ्य सूचकांकों में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मातृ मृत्यु दर 113 से घटकर 91 तथा शिशु मृत्यु दर 34 से घटकर 27 हो गई है। कुल प्रजनन दर 2.1 से घटकर 1.8 पर पहुंची है। प्रथम तिमाही गर्भ पंजीकरण 56 प्रतिशत से बढ़कर 82 प्रतिशत, चार एएनसी जांच 62 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत, गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण 92 से बढ़कर 96 प्रतिशत तथा शिशुओं का पूर्ण टीकाकरण 92 से बढ़कर 98 प्रतिशत हो गया है। संस्थागत प्रसव 63 प्रतिशत से बढ़कर 92 प्रतिशत तथा लिंगानुपात 941 से बढ़कर 956 तक पहुंच गया है।

उनके मुताबिक, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के संकल्प के साथ, पौड़ी गढ़वाल की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक बदलाव से यह संभव हो पाया है।

बदरीनाथ चढ़ावा विवाद पर महेंद्र शर्मा का पलटवार

बदरीनाथ चढ़ावा विवाद पर बीकेटीसी सदस्य महेंद्र शर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना

भारतेंदु संवाददाता, चमोली। बदरीनाथ धाम में चढ़ावे की राशि में अनियमितता के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य महेंद्र शर्मा ने कहा कि इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस धार्मिक मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

महेंद्र शर्मा ने कहा कि मंदिर समिति और सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। चढ़ावे की गणना में गड़बड़ी सामने आने के बाद संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कदम उठाए गए और जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है और किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिरों की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता जरूरी है और जांच के दौरान सभी तथ्यों को सामने लाया जाना चाहिए। महेंद्र शर्मा ने सुझाव दिया कि मंदिर समिति के पिछले कार्यकालों की व्यवस्थाओं और निर्णयों की भी समीक्षा होनी चाहिए ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके।

उन्होंने धार्मिक संस्थाओं को राजनीति से दूर रखने की अपील करते हुए कहा कि बदरीनाथ धाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए इस मामले में आरोप-प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी है कि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो।

राष्ट्र की रक्षा में बलिदान देने वाले वीरों को मिलेगा सम्मान

नोएडा में गूंजेगा देशभक्ति का स्वर कारगिल वीरों को किया जाएगा नमन

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 26 जुलाई 2026 को नोएडा में वीर शहीदों और देश की रक्षा में जुटे जवानों के सम्मान में एक भव्य श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी कला केंद्र सेक्टर 6 नोएडा अथॉरिटी में शाम 4 बजे से आयोजित होगा। समारोह में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही देश की तीनों सेनाओं के वीर जवानों और उनके परिवारों को सम्मानित किया जाएगा।

कार्यक्रम के मुख्य संयोजक राजेंद्र चौहान ने बताया कि यह आयोजन उन वीर योद्धाओं के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। समारोह की शुरुआत देव स्तुति और शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ होगी। इसके बाद देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी।

कार्यक्रम में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को भी विशेष स्थान दिया गया है। आयोजन में उत्तराखंड की बोली और संस्कृति पर आधारित विशेष प्रस्तुतियां होंगी जबकि अधिकांश कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रस्तुत किए जाएंगे। आयोजकों का उद्देश्य देशभक्ति के साथ भारतीय संस्कृति और क्षेत्रीय परंपराओं को भी बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर महाकौथिग की टीम द्वारा आगामी नवंबर माह में आयोजित होने वाले ईगास त्योहार की तैयारियों की जानकारी भी दी गई। आयोजकों ने लोगों से अपील की है कि वे इस गरिमामय कार्यक्रम में शामिल होकर अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करें और उनके परिवारों के प्रति सम्मान एवं आभार व्यक्त करें।

अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता हुआ साफ

नई नीति लागू होने के बाद डेवलपर और आरडब्ल्यूए 30 सितंबर तक नियमितीकरण के लिए कर सकेंगे आवेदन

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब सरकार राज्यभर में वर्षों से कानूनी मान्यता का इंतजार कर रही करीब 5,000 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की तैयारी कर रही है। पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (पीएपीआर) नियमों में संशोधन के बाद सरकार नई नियमितीकरण नीति को जल्द अधिसूचित कर सकती है। इस नीति का उद्देश्य उन हजारों परिवारों को राहत देना है, जो अवैध कालोनियों में रहने के कारण अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री, निर्माण मंजूरी और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

नई नीति लागू होने के बाद कालोनियों के डेवलपर और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित किए जाने की संभावना है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार राज्य में पहले करीब 7,000 अनधिकृत कालोनियों की पहचान की गई थी। इनमें से लगभग 2,000 कालोनियां पिछली नियमितीकरण योजनाओं के तहत वैध हो चुकी हैं, जबकि बड़ी संख्या में आवेदन जरूरी दस्तावेजों की कमी के कारण खारिज कर दिए गए थे।

अधिकारियों के अनुसार नई नीति में प्रक्रिया को पहले की तुलना में आसान बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक कालोनियों को इसका लाभ मिल सके। वर्तमान में राज्य में करीब 5,000 अनधिकृत कालोनियां मौजूद हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या लुधियाना में बताई जा रही है, जहां लगभग 2,000 ऐसी कालोनियां होने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य नगर निगम और शहरी क्षेत्रों के आसपास भी बड़ी संख्या में अवैध कालोनियां विकसित हुई हैं।

सरकार ने इससे पहले वर्ष 2013, 2016 और 2018 में भी कालोनियों को नियमित करने के लिए योजनाएं शुरू की थीं, लेकिन विभिन्न कारणों से इन योजनाओं को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। नई नीति में नियमों को सरल बनाकर उन कालोनियों को भी मौका देने का निर्णय लिया गया है, जिनके आवेदन पहले किसी कारण से अस्वीकार हो चुके थे। अब वे दोबारा आवेदन कर सकेंगी। नई नीति के तहत कम से कम 25 प्रतिशत विकसित हो चुकी कालोनियां नियमितीकरण के लिए पात्र मानी जाएंगी। मास्टर प्लान में कृषि भूमि के रूप में दर्ज क्षेत्रों में बनी कालोनियों को भी राहत देने का प्रावधान रखा गया है।

हालांकि जीएमएडीए क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत आने वाली कालोनियों के लिए अलग नियम लागू होंगे। नीति में कालोनी के लिए न्यूनतम 20 फुट चौड़ी सड़क और 50 से 239.2 वर्ग गज तक के प्लॉट का प्रावधान रखा गया है। आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर अस्थायी नियमितीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था होगी। इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा करने पर संपत्ति मालिक नियमितीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने और भवन निर्माण से जुड़ी आवश्यक मंजूरियां लेने में आसानी होगी।

आरडब्ल्यूए को भी कालोनियों की ओर से आवेदन करने का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए सभी जरूरी वैधानिक मंजूरियां और अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा। नियमितीकरण और कंपाउंडिंग शुल्क प्रचलित कलेक्टर दरों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। वहीं डेवलपर और प्रमोटरों को भी नई नीति से राहत मिलने की उम्मीद है। तीन जुलाई को पंजाब मंत्रिमंडल ने पीएपीआर नियमों के नियम-31 में संशोधन को मंजूरी दी थी।

बुजुर्गों की उपेक्षा करने वालों के खिलाफ कानून के तहत होगी कार्रवाई

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और कानूनी अधिकारों को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण करना केवल नैतिक दायित्व नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। यदि संतान या उत्तराधिकारी अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते अथवा उनके भरण-पोषण से इन्कार करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी बुजुर्ग उपेक्षा, असुरक्षा या आर्थिक संकट का सामना न करे।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार बुजुर्गों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध

कराने और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

मंत्री ने बताया कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 के तहत माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करना उनकी संतान और उत्तराधिकारियों की कानूनी जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति इस दायित्व का पालन नहीं करता है तो संबंधित वरिष्ठ नागरिक उपमंडल अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत प्राप्त होने के बाद मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल मामले की सुनवाई करेगा और कानून के अनुसार आवश्यक आदेश जारी करेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 भी संचालित की है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से बुजुर्ग मानसिक, सामाजिक, कानूनी और अन्य प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए नि:शुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

न्यूज ब्रीफ

फ्लैट दिलाने के नाम पर ठगे 18 लाख

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर। जीरकपुर में फ्लैट दिलाने का झांसा देकर 18 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी करने के आरोप में एक दंपती के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई शिकायत की जांच पूरी होने के बाद की गई। मामला अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे स्थित सिंघपुरा की एस्कॉन एरिना सोसाइटी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार गीता रानी और दीपक बजाज ने उन्हें सोसाइटी में फ्लैट दिलाने और उसकी रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिया था। इस भरोसे पर उन्होंने आरोपितों को करीब 18 लाख रुपये दे दिए। आरोप है कि रकम लेने के बाद न तो फ्लैट की रजिस्ट्री कराई गई और न ही पैसे लौटाए गए। शिकायतकर्ता ने कई बार आरोपितों से संपर्क कर समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया। इसके बाद पीड़ित ने पिछले वर्ष नवंबर में पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया, जिसके आधार पर दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

इंटरनेट केबल से क्षतिग्रस्त हुई सीवर पाइपलाइन

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर। पीरमुछल्ला इलाके में कई दिनों से सीवर लाइन ओवरफ्लो होने की समस्या से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। जांच के दौरान पता चला कि इंटरनेट केबल बिछाने के दौरान सीवर की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। केबल कंपनी ने सीवर लाइन के अंदर से ही केबल डाल दी थी, जिससे पाइपलाइन जाम हो गई और सफाई मशीन से भी ब्लॉकेज नहीं खुल सकी। अब क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को बदलने और नई लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के वार्ड-10 इंचार्ज संदीप सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जांच के बाद समस्या की वास्तविक वजह सामने आई है। इससे पहले कांग्रेस पार्षदों और नेताओं ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर नई पाइपलाइन डालने के निर्देश दिए हैं। सीवर सफाई मशीन ने रातभर काम किया, लेकिन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण समस्या दूर नहीं हो सकी।

कूड़े के ढेरों से बढ़ा जलभराव का खतरा

भारतेन्दु संवाददाता, खरड़। शहर में जगह-जगह लगे कूड़े के ढेरों को लेकर भाजपा पंजाब इंडस्ट्रीज सेल के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोहित मिश्रा ने पंजाब सरकार और नगर परिषद खरड़ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान यही कूड़ा नालियों और सीवरेज लाइनों को जाम कर सकता है, जिससे जलभराव और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। रोहित मिश्रा ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ से सटे खरड़ में सफाई व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हालात और बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन जरूरी सेवाओं को सुचारु रखने में नाकाम रहा है। शहर में कूड़े के ढेर, बंद सीवरेज और टूटी सड़कों के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार और नगर परिषद से जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था बहाल करने तथा कूड़ा उठाने की व्यवस्था को नियमित करने की मांग की। मिश्रा ने खरड़ को पंजाब का प्रवेश द्वार बताते हुए शहर के विकास के लिए नागरिकों, आरडब्ल्यूए, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों से लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने की अपील की।

चंडीगढ़ में कर्मचारियों के लिए लागू होंगे नए नियम

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां नियम 2026 के तहत अब निजी कंपनियों और संस्थानों पर भी कई नए प्रावधान लागू होंगे। प्रशासन ने ड्राफ्ट पर 45 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। नए नियमों के अनुसार हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। कार्य अवधि, ओवरटाइम, अवकाश, वेतन रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों का रखरखाव भी जरूरी होगा। महिला कर्मचारियों की रात्रि पाली में सुरक्षा के लिए सुरक्षित परिवहन और अन्य इंतजाम करना नियोक्ताओं की जिम्मेदारी होगी। 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण और जोखिम वाले कार्यों में लगे कर्मचारियों की साल में दो बार मेडिकल जांच का प्रावधान रखा गया है।

जिला बोर्ड की सेवा अवधि को पेंशन लाभ से बाहर नहीं किया जा सकता : हाई कोर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन अधिकारों से जुड़े 69 वर्ष पुराने सेवा विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि जिला बोर्ड के अधीन दी गई सेवा को केवल इस आधार पर पेंशन लाभ से बाहर नहीं किया जा सकता कि उस अवधि में कर्मचारी ने कान्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (सीपीएफ) में अंशदान नहीं किया था। अदालत ने कहा कि कर्मचारी की पूर्व सेवा को पेंशन निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए और केवल तकनीकी आधार पर उसे इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस हरकेश मनुजा की एकल पीठ ने पंजाब सरकार की दूसरी अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसलों को बरकरार रखा। मामले के अनुसार लुधियाना निवासी हरदयाल सिंह ने 31 अगस्त 1953 से 30 सितंबर 1957 तक जिला बोर्ड के स्कूलों में अपनी सेवाएं दी थीं।

पेंशन अधिकारों पर महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत ने अपने फैसले के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी कर्मचारी के वैधानिक और अर्जित अधिकारों को केवल तकनीकी कारणों के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता। यदि कोई कर्मचारी वर्षों तक किसी सरकारी अथवा सरकार में विलय किए गए संस्थान में नियमित रूप से सेवाएं देता है तो उसकी उस अवधि की सेवा का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पेंशन का उद्देश्य कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है और इसे संकीर्ण तकनीकी व्याख्याओं के आधार पर नकारना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अदालत के इस फैसले से ऐसे अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी राहत मिलने की संभावना है जिनकी पूर्व सेवा अवधि को विभिन्न कारणों से पेंशन निर्धारण में शामिल नहीं किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय के बाद संबंधित विभागों को पुराने मामलों की समीक्षा करनी पड़ सकती है, विशेषकर उन मामलों में जहां संस्थानों के सरकारी विलय या प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण कर्मचारियों की सेवा अवधि को लेकर विवाद उत्पन्न हुए थे।

सेक्टर 78 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दो महीने में तैयार होगा सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

मोहाली के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेक्टर-78 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा 400 मीटर का 8 लेन वाला आधुनिक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और विभाग को उम्मीद है कि अगले दो महीने के भीतर यह ट्रैक पूरी तरह तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके शुरू होने के बाद जिले के एथलीटों को अभ्यास के लिए चंडीगढ़ या अन्य शहरों में नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने ही शहर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

ट्रैक के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। मुख्य ट्रैक के अलावा खिलाड़ियों के वार्मअप और अभ्यास के लिए अलग क्षेत्र भी विकसित किया जा रहा है। फिलहाल ट्रैक पर विशेष पेंट

की परत बिछाने के बाद उस पर रबर के गोल आकार के चिप्स डाले जा रहे हैं। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जा रही है ताकि ट्रैक मजबूत सुरक्षित और लंबे समय तक उपयोग के योग्य बन सके। निर्माण कार्य में लगे कर्मचारी परत दर परत सामग्री बिछाकर अंतिम फिनिशिंग देने में जुटे हुए हैं।

इस परियोजना को वर्ष 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन कुछ कारणों से निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सका। अब अधिकांश काम पूरा हो चुका है और अंतिम फिनिशिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि निर्धारित समय के भीतर ट्रैक खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया जाएगा।

जिला खेल अधिकारी रूपेश कुमार ने बताया कि इस आधुनिक सिंथेटिक ट्रैक के शुरू होने से जिले के खिलाड़ियों को उच्च स्तर की अभ्यास सुविधा मिलेगी। इससे एथलीट राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बेहतर तैयारी कर सकेंगे।

पंजाब में खराब परीक्षा परिणाम पर 68 पिंसिपलों से मांगा जवाब

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब के सरकारी स्कूलों में लगातार कमजोर परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए 68 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि जिन स्कूलों का दसवीं और बारहवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम लगातार निर्धारित मानकों से नीचे रहा है, वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस संबंध में संबंधित प्रिंसिपलों से पहले स्पष्टीकरण मांगा गया था और अब उनके जवाबों की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा पूरी होने के बाद विभाग नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाना स्कूल प्रमुखों की प्रमुख जिम्मेदारी है। यदि किसी स्कूल में लगातार कमजोर परिणाम सामने आते हैं तो उसके कारणों की गंभीरता से जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि केवल औपचारिक शिक्षण से बेहतर

परिणाम हासिल नहीं किए जा सकते, बल्कि नियमित निगरानी, प्रभावी शैक्षणिक योजना और विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान भी आवश्यक है।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से स्कूलों के परीक्षा परिणाम, विद्यार्थियों की उपस्थिति, कक्षा शिक्षण, शिक्षकों के कार्य निष्पादन और स्कूल प्रबंधन की नियमित समीक्षा की जा रही है। जिन स्कूलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि लगातार कमजोर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के लिए विशेष सुधार योजना लागू की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे स्कूलों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और विशेष प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। सूत्रों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे स्कूलों की नियमित निगरानी करें और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। यदि आगामी शैक्षणिक सत्र में भी अपेक्षित सुधार नहीं होता है तो संबंधित प्रिंसिपलों और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ और कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

शिक्षा विभाग का मानना है कि जवाबदेही तय करने की इस व्यवस्था से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। विभाग ने सभी स्कूल प्रमुखों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नियमित मूल्यांकन, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाओं तथा अभिभावकों के साथ बेहतर समन्वय पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कमजोर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के लिए मासिक कार्ययोजना तैयार करें और उसकी नियमित समीक्षा करें।

जीरकपुर में बिजली तारों में लगी आग बड़ा हादसा टला

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर। बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की बढ़ती मांग ने शहर की बिजली व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। शुक्रवार देर रात जीरकपुर के दो अलग-अलग इलाकों में बिजली की तारों से तेज चिंगारियां निकलने और आग की लपटें उठने से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि बिजली विभाग की तत्परता से समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा होने से बच गया।

◆ गुरुदेव नगर और हेम विहार में बिजली तारों से निकली चिंगारी

पहली घटना भबात के गुरुदेव नगर में हुई। यहां बिजली की तारों से अचानक तेज स्पार्किंग शुरू हो गई। तारों से निकलती चिंगारियां देखकर स्थानीय लोग डर गए और कई लोग अपने घरों से बाहर आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था जैसे आतिशबाजी हो रही हो। घटना के बाद लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और आपूर्ति व्यवस्था को नियंत्रित किया।

वहीं दूसरी घटना बलटाना के हेम विहार इलाके में सामने आई, जहां ट्रांसफार्मर को जाने वाली बिजली लाइन में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने घटना के वीडियो भी बनाए, जिनमें तारों से निकलती चिंगारियां और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं।

बीटेक पास दो दोस्तों ने सर्वर हैक कर चुराए 19 लाख के वाउचर

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

दोस्ती, जुए में हुए नुकसान की भरपाई और जल्दी अमीर बनने की चाह ने दो बीटेक पास युवकों को साइबर अपराध की दुनिया में धकेल दिया। दोनों ने मिलकर एक निजी कंपनी का सर्वर हैक किया और करीब 19 लाख रुपये मूल्य के अमेजन गिफ्ट वाउचर कोड चोरी कर लिए। इन चोरी किए गए वाउचर कोड का इस्तेमाल कर उन्होंने अमेजन से सोने के सिक्के और अन्य कीमती सामान खरीदे। बाद में इन सोने के सिक्कों को अलग-अलग ज्वेलरी दुकानों में बेचकर नकदी हासिल की और रकम आपस में बांट ली। मामले का खुलासा होने पर चंडीगढ़ साइबर क्राइम थाना पुलिस ने दोनों आरोपितों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान प्रयागराज निवासी गौरव सिंह उर्फ दीपु और सिद्धार्थ पांडे उर्फ अंकित के रूप में हुई है। यह मामला मनीमाजरा स्थित कारपोरेट इंसेंटिव

सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों तक पहुंचने में सफलता हासिल की।

पुलिस जांच में सामने आया कि सिद्धार्थ पांडे तकनीकी रूप से बेहद दक्ष था और वही पूरे साइबर अपराध का मास्टरमाइंड था। उसने कंपनियों के सर्वर में सेंध लगाकर गोपनीय डाटा और अमेजन गिफ्ट वाउचर कोड चुराए। चोरी किए गए वाउचर कोड वह अपने साथी गौरव सिंह को देता था। गौरव फर्जी अमेजन खाते बनाकर इन वाउचर कोड को रिडीम करता और उनसे सोने के सिक्के तथा अन्य महंगे उत्पाद खरीदता था। इसके बाद वह इन सामानों को प्रयागराज और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित ज्वेलरी दुकानों में बेचकर नकदी प्राप्त करता था।

पूछताछ के दौरान दोनों आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। जुए में लगातार पैसे हारने के बाद उन्होंने नुकसान की भरपाई और कम समय में अधिक पैसा कमाने के उद्देश्य से साइबर अपराध का रास्ता अपनाया।

चंडीगढ़ नगर निगम में जल्द शुरू होगी सीधी भर्ती

कर्मचारियों की भारी कमी दूर करने के लिए निगम सरकारी एजेंसी के माध्यम से करेगा पारदर्शी भर्ती

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

नगर निगम चंडीगढ़ में लंबे समय से कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे विभिन्न विभागों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नगर निगम के 276 पदों पर सीधी भर्ती संबंधी प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद अब नगर निगम किसी प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और इसमें केंद्र सरकार के सभी आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

नगर निगम के बजट दस्तावेजों के अनुसार निगम में कुल 5611 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 3767 पद वर्तमान में रिक्त हैं। यानी निगम के 60 प्रतिशत से अधिक पद खाली पड़े हैं। कर्मचारियों की भारी कमी के कारण इंजीनियरिंग, फायर, स्वास्थ्य, प्रवर्तन, लेखा और अन्य कई विभागों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। कई

स्थानों पर नियमित कर्मचारियों के अभाव में संविदा कर्मियों के सहारे व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे कार्यों के निष्पादन में देरी भी हो रही है।

प्रस्तावित भर्ती में सबसे अधिक 118 क्लर्क के पद शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 79 फायरमैन, 33 ड्राइवर, 20 जूनियर इंजीनियर, दो सब डिविजनल इंजीनियर, पांच प्रवर्तन सब इंस्पेक्टर, चार ड्राफ्ट्समैन, चार स्टेनो टाइपिस्ट तथा तीन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही कुछ लेखा और तकनीकी श्रेणी के पद भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं, ताकि विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता को मजबूत किया जा सके।

गौरतलब है कि वर्ष 2021 में नगर निगम ने लगभग 170 स्थायी पदों पर भर्ती के लिए पंजाब विश्वविद्यालय को भर्ती एजेंसी बनाया था। उस प्रक्रिया को पूरा होने में एक वर्ष से अधिक समय लगा था। इस बार भी निगम किसी अनुभवी और विश्वसनीय सरकारी एजेंसी का चयन करेगा। एजेंसी के चयन के बाद भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें पात्रता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया और चयन संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि नई भर्ती पूरी होने के बाद विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी काफी हद तक दूर होगी। इससे शहर में सफाई व्यवस्था, अग्निशमन सेवाएं, विकास कार्य, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

भर्ती से सेवाओं में सुधार

नगर निगम प्रशासन भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की तैयारी कर रहा है ताकि विभिन्न विभागों में लंबे समय से चल रही कर्मचारियों की कमी को शीघ्र दूर किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार भर्ती पूरी होने के बाद नए कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे आधुनिक कार्यप्रणाली और नागरिक सेवाओं से जुड़े मानकों के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। प्रशासन का मानना है कि पर्याप्त संख्या में नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति होने से विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और लंबित कार्यों का समय पर निपटारा संभव होगा। नगर निगम का कहना है कि बढ़ती आबादी और शहर के लगातार विस्तार के कारण नागरिक सुविधाओं की मांग भी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होना बेहद आवश्यक है। नई नियुक्तियों से भवन निर्माण संबंधी अनुमतियों, अग्निशमन सेवाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, जल निकासी, सड़क रखरखाव और प्रवर्तन कार्यों में सुधार आने की उम्मीद है।

निवेश रैंकिंग में पिछड़ा पंजाब, भाजपा ने उठाए सवाल

नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर भाजपा ने पंजाब सरकार पर औद्योगिक विकास और निवेश को लेकर साधा निशाना

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स-2026 में पंजाब की रैंकिंग को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ओर से निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर किए जा रहे बड़े-बड़े दावों की हकीकत अब सामने आ गई है। ढिल्लों ने कहा कि पंजाब को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 22वां स्थान मिलना सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार पिछले कई वर्षों से पंजाब में बड़े पैमाने पर निवेश आने और उद्योगों के विस्तार के दावे करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कई निवेश सम्मेलनों का आयोजन किया और लाखों करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की जानकारी सार्वजनिक की लेकिन जमीनी स्तर पर इसका अपेक्षित असर दिखाई नहीं दिया। उनका कहना है कि निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में राज्य सरकार सफल नहीं हो सकी।

ढिल्लों ने कहा कि सरकार की ओर से औद्योगिक विकास को लेकर किए गए प्रचार और वास्तविक स्थिति में काफी अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने विज्ञापन और प्रचार गतिविधियों पर भारी खर्च किया लेकिन प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में ठोस काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि निवेशकों का भरोसा मजबूत करने के लिए बेहतर कानून व्यवस्था पारदर्शी नीतियां और मजबूत औद्योगिक ढांचा जरूरी है।

भाजपा नेता ने कहा कि पंजाब कभी देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में शामिल रहा है। यहां के उद्यमियों और उद्योगों ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीतिगत कमजोरियों के कारण राज्य की औद्योगिक छवि प्रभावित हो रही है। उनके अनुसार उद्योगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने और नए निवेश को आकर्षित करने के बजाय सरकार राजनीतिक प्रचार को प्राथमिकता दे रही है।

ढिल्लों ने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति और प्रशासनिक नीतियों को लेकर निवेशकों में चिंता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को स्थिर माहौल और सरकार से स्पष्ट नीतियों की आवश्यकता होती है। यदि निवेशकों को विश्वास नहीं मिलेगा तो राज्य में औद्योगिक विकास की गति प्रभावित होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित रहेंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश के कई राज्यों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है लेकिन पंजाब इस दौड़ में पीछे रह गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी सरकार से मांग की कि वह केवल दावों और प्रचार से बाहर निकलकर उद्योगों के लिए वास्तविक सुविधाएं उपलब्ध कराए।

उन्होंने कहा कि पंजाब को फिर से औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत स्थान दिलाने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की जरूरत है। इसमें छोटे और बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देना नए निवेशकों को आकर्षित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना शामिल होना चाहिए। ढिल्लों ने कहा कि प्रदेश की जनता अब सरकार के दावों और वास्तविक विकास कार्यों के बीच अंतर को समझ रही है। भाजपा ने कहा कि राज्य सरकार को निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि पंजाब में औद्योगिक विकास को नई गति मिल सके।

जगराओं पुल पर हादसे का खतरा, प्रशासन बेखबर

एक साल बाद भी नहीं हुई मरम्मत, पुल की हालत खराब

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना । महानगर की लाइफलाइन माने जाने वाले जगराओं पुल की हालत लगातार खराब होती जा रही है। प्रशासनिक लापरवाही और नगर निगम की उदासीनता के कारण यह पुल कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। बीते वर्ष भारी बारिश के दौरान पुल की सुरक्षा दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था। इसके बाद मिल्लरगंज की तरफ जाने वाले हिस्से को असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। बावजूद इसके एक साल बीतने के बाद भी नगर निगम पुल की मरम्मत या नए निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।

हालात यह हैं कि पुल के ऊपर सड़क भी धीरे धीरे धंसने लगी है। इस कारण दिल्ली, जालंधर और अमृतसर की ओर आने जाने वाले हजारों वाहन चालकों की सुरक्षा खतरे में बनी हुई है। लोगों का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण पुल की खराब हालत के बावजूद प्रशासन की ओर से समय रहते कार्रवाई नहीं की गई।

जगराओं पुल के ढांचे की स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली है। पुल की नींव और सुरक्षा दीवारों के आसपास चूहों ने बड़े गड्ढे कर दिए हैं, जिससे ढांचा कमजोर हो

जगराओं पुल की सुरक्षा दीवार टूटी मरम्मत में निगम की लापरवाही।

रहा है। इसके अलावा पुल की दीवारों और जोड़ों में उगी जंगली घास और झाड़ियों की जड़ें भी दीवारों को नुकसान पहुंचा रही हैं। बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या इस स्थिति को और गंभीर बना रही है।

नगर निगम के अधिकारियों के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। निगम के एसई रणजीत सिंह ने पहले दावा किया था कि जगराओं पुल को चौड़ा करने और रिटेनिंग वॉल की मरम्मत का काम शहर में चल रहे वर्ल्ड क्लास सड़कों के प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़े राहुल वर्मा ने स्पष्ट किया कि जगराओं पुल को चौड़ा करने या सुरक्षा दीवार बनाने की कोई योजना इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत केवल सड़कों को बेहतर बनाया जाना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम कमिश्नर ओजस्वी अलंकार ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है।

अश्लील तस्वीर विवाद में निहंग जसदीप सिंह पर बुड्ढ़ा दल की कार्रवाई

जसदीप सिंह ने गलती स्वीकार कर पंथ आदेशों पालन का दिया भरोसा

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। अश्लील तस्वीरों से जुड़े विवाद के बाद निहंग जसदीप सिंह के खिलाफ बुड्ढा दल की ओर से धार्मिक अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उन्हें संगल यानी जंजीरों से बांधकर पारंपरिक धार्मिक दंड दिया गया। बुड्ढा दल के दोआबा जोन के जत्थेदार मान सिंह ने इस पूरी कार्रवाई से जुड़े वीडियो और तस्वीरें अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की हैं।

जत्थेदार मान सिंह ने वीडियो संदेश में कहा कि आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आने के बाद जसदीप सिंह को पहले भी धार्मिक सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह कार्रवाई पूरी होने से पहले ही वहां से चले गए थे। उन्होंने दावा किया कि बुड्ढा दल की ओर से उन्हें अब तक कोई आधिकारिक माफी नहीं दी गई थी। जबकि जसदीप सिंह ने पहले एक साक्षात्कार में माफी मिलने की बात कही थी।

बुड्ढा दल के अनुसार, अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद अगले आदेश तक जसदीप सिंह निहंग बाणा धारण नहीं कर सकेंगे। वहीं जसदीप सिंह ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि वह भविष्य में पंथ के आदेशों का पालन करेंगे और बिना अनुमति कोई कदम नहीं उठाएंगे।

यह विवाद तब सामने आया जब निहंग विक्की थॉमस ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और एक वीडियो साझा किया था। उन्होंने दावा किया था कि तस्वीरों में दिखाई देने वाला व्यक्ति निहंग जसदीप सिंह है। विक्की थॉमस ने आरोप लगाया कि तस्वीरें आपत्तिजनक स्थिति से जुड़ी हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये तस्वीरें कब और किन परिस्थितियों में ली गई थीं।

इसके बाद मामले ने धार्मिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का रूप ले लिया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक वीडियो कॉल के अंश में जसदीप सिंह ने कथित तौर पर तस्वीरों को अपना बताया और कहा कि उस समय वह नशे की स्थिति में थे।

छह महीने से नहीं मिला वेतन, मनरेगा कर्मियों में रोष

भारतेंदु संवाददाता, गुरदासपुर। जिला गुरदासपुर में मनरेगा कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंचायत भवन में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान यूनियन के जिला प्रधान संदीप सिंह ने पंजाब सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मचारियों को पिछले छह महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

संदीप सिंह ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय नए फरमान जारी कर रही है। यूनियन प्रधान ने आरोप लगाया कि सरकार ने मनरेगा कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जगह दूसरे विभागों के कर्मचारियों को मनरेगा कार्यों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे कर्मचारियों में असुरक्षा और रोष बढ़ गया है।

इश्कनामा रिलीज से पहले विवादों में घिरी फिल्म

कहानी और किरदारों पर सवाल उठने से फिल्म बनी विवादों का केंद्र

भारतेंदु संवाददाता,चंडीगढ़। पंजाबी फिल्म इश्कनामा रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। अभिनेता जय रंधावा और अभिनेत्री शहनाज गिल की यह फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की कहानी भारतीय पंजाबी सिख युवक निम्मा और पाकिस्तानी पंजाबी युवती नसीमा की अधूरी प्रेम कहानी पर आधारित बताई जा रही है। 14 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस शुरू हो गई।

फिल्म की कहानी और किरदारों को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तैमूर अहमद ने दावा किया कि फिल्म की कहानी फर्जी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नसीमा नाम आम नहीं है। वहां लोग नसीम या सीमा जैसे नाम रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कहानी को दर्शकों के सामने लाने से पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी।

वहीं ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान शहनाज गिल के एक बयान को लेकर

पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर ने फिल्म की कहानी को बताया फर्जी

भी विवाद खड़ा हो गया। शहनाज ने कहा था कि अगर निम्मा को नसीमा मिल जाए तो वह दोनों को एक कमरे में छोड़ देंगी और कहेंगी कि जफ्फी डाल लो और जी भरकर प्यार कर लो। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

फिल्म की कहानी वर्ष 1981 से 1988 के बीच की बताई जा रही है। इसमें निम्मा नाम का एक सिख युवक पाकिस्तान जाता है, जहां उसकी मुलाकात नसीमा नाम की मुस्लिम युवती से होती है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है। नसीमा भारत घूमने की इच्छा जताती है और निम्मा उसे भारत लेकर आता है। बाद में नसीमा के परिवार को इस रिश्ते की जानकारी मिलती है और दोनों प्रेमियों को अलग कर दिया जाता है।

फिल्म की शूटिंग के दौरान जय रंधावा भी हादसे का शिकार हुए थे। एक जंप सीन के दौरान क्रेन में तकनीकी खराबी आने से वह दीवार से टकरा गए थे। हालांकि चोट के बाद उन्होंने जल्द ही शूटिंग पूरी कर ली।

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म को लेकर निजी जिंदगी और पुराने प्रेम प्रसंग को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है।

मानसिक परेशानी में युवक ने नहर में लगाई छलांग

भारतेंदु संवाददाता नंगल । लुधियाना से नंगल आए एक युवक की नंगल हाइडल नहर में कथित तौर पर कूदने से मौत हो गई। घटना नंगल में सांसद के घर के पास की बताई जा रही है। पुलिस ने युवक का शव बरामद कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

नंगल थाने के जांच अधिकारी एएसआई बलराम ने बताया कि मृतक की पहचान अमृतपाल सिंह पुत्र तरसेम सिंह निवासी लुधियाना के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अमृतपाल सिंह बीती रात अपनी कार लेकर घर से निकला था। इसके बाद वह नंगल पहुंचा।

पुलिस के अनुसार सुबह करीब पांच बजे अमृतपाल ने अपने परिवार को फोन कर बताया कि उसकी गाड़ी सांसद के घर के पास खड़ी है और परिवार वाले उसे तलाश लें। इसके बाद उसने

नहर के पुल के पास अपनी चप्पलें उतारीं और कथित तौर पर नहर में छलांग लगा दी।

परिवार को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे तुरंत नंगल पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। परिजनों और पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने गोताखोरों और अन्य माध्यमों की मदद से तलाश अभियान चलाया। एएसआई बलराम ने बताया कि पुलिस ने अमृतपाल सिंह का शव गुंगवाल के पास से बरामद किया।

बड़े कारोबार का सपना दिखाकर व्यक्ति को लगाया लाखों का चूना

लुधियाना में निवेश के नाम पर कारोबारी से 3 .27 करोड़ रुपये की ठगी

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना । महानगर में व्यापार और निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ शातिर लोगों ने ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स के कारोबार में मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 3 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपये निवेश करवा लिए। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने बाद में पूरी रकम लौटाने से इनकार कर दिया और केवल 27 लाख 50 हजार रुपये देकर उसे टालने की कोशिश की।

पीड़ित गगन जिंदल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ समय पहले कुछ लोगों ने उससे संपर्क किया और खुद को ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स कारोबार से जुड़े बड़े

व्यापारी के रूप में पेश किया। आरोपियों ने उसे भरोसा दिलाया कि उनका कारोबार पहले से चल रहा है और इसमें निवेश करने पर हर महीने अच्छा मुनाफा मिलेगा। उन्होंने निवेश को सुरक्षित बताते हुए बड़े लाभ का लालच दिया। आरोपियों की बातों पर विश्वास करते हुए गगन जिंदल ने अपनी जमा पूंजी और बैंक खातों से कुल 3 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपये उनके बताए अनुसार कारोबार में लगा दिए। शिकायतकर्ता के अनुसार निवेश की अवधि पूरी होने के बाद जब उसने अपने मूलधन और मुनाफे की मांग की तो आरोपी बहाने बनाने लगे।

पीएम मोदी की हरे रंग की पगड़ी बनी चर्चा का विषय

भारतेंदु संवाददाता, पंजाब । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे के दौरान पहनी गई हरे रंग की पगड़ी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। खास बात यह है कि इस पगड़ी को जालंधर के सनप्रीत सिंह ने अपने हाथों से बांधा था। सनप्रीत इससे पहले भी दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पगड़ी बांध चुके हैं।

सनप्रीत सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सिर पर महज दो मिनट में पगड़ी सजा दी। उन्होंने बताया कि इस पगड़ी के लिए छह मीटर लंबे कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। पांच लड़ वाली इस पगड़ी का स्टाइल सेमी पटियाला था। पगड़ी बांधने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह काफी पसंद आई और उन्होंने खुशी जाहिर की। सनप्रीत ने अपने अनुभव को यादगार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के इतने करीब जाकर पगड़ी बांधना उनके लिए गर्व का पल था।

अमृतसर में डेंगू और वायरल बुखार का बढ़ा खतरा अस्पतालों में बढ़े मरीज

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर । मानसून के आगमन के साथ ही अमृतसर में डेंगू और वायरल बुखार का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लीनिकों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार, खांसी, जुकाम, गले में संक्रमण, शरीर में दर्द और कमजोरी की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

चिकित्सकों के अनुसार मौसम में बदलाव, बढ़ती नमी और जगह-जगह जमा पानी के कारण वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं जलभराव के कारण डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर के पनपने के लिए भी अनुकूल वातावरण बन गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को देखते हुए जिलेभर में एंटी-डेंगू अभियान तेज कर दिया है।

स्वास्थ्य विभाग की टीमें विभिन्न इलाकों में घर-घर जाकर मच्छरों के लारवा की जांच कर रही हैं। इसके अलावा फॉगिंग, साफ-सफाई और लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों और आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले, पुराने टायर, पानी की टंकियों और अन्य बर्तनों की नियमित सफाई करें।

डॉक्टरों का कहना है कि इन दिनों बड़ी संख्या में मरीज तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द और गले में संक्रमण जैसी समस्याओं के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। कई मरीजों में डेंगू जैसे लक्षण दिखाई देने पर उनकी रक्त जांच और प्लेटलेट्स की जांच कराई जा रही है। विशेषज्ञों ने कहा कि हर बुखार डेंगू नहीं होता, लेकिन तेज बुखार को नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है।

30 साल पुरानी बिजली तार बनी खतरा कार्रवाई नहीं होने से लोगों में रोष

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना। पुरानी माधोपुरी की एक नंबर गली में जर्जर मुख्य बिजली तार को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि करीब एक वर्ष पहले पावरकॉम के एसडीओ और वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर पुरानी तार बदलने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लंबे समय से खराब हालत में पड़ी बिजली तार कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

इलाकावासियों के अनुसार गली की मुख्य बिजली तार करीब 30 वर्ष पुरानी हो चुकी है। इसमें जगह-जगह 10 से 12 जोड़ लगाए गए हैं, जिसके कारण आए दिन स्पार्किंग होती रहती है। कई बार तारों से तेज धमाकों जैसी आवाजें भी आती हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल

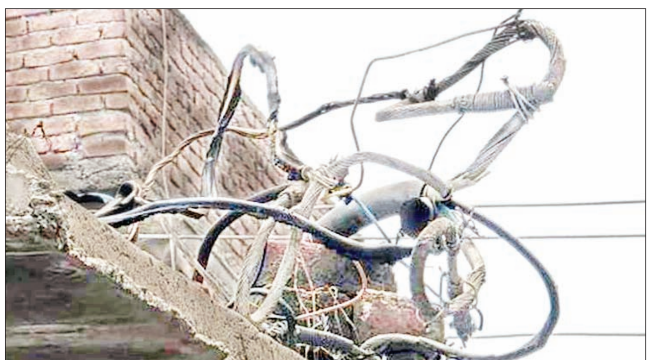

जर्जर बिजली तार बदलने की मांग, पुरानी माधोपुरी में बढ़ी नाराजगी।

बना रहता है। लोगों का कहना है कि बिजली आपूर्ति में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण कई घरों में एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन और अन्य महंगे बिजली उपकरण खराब हो चुके हैं। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट की घटनाओं में कई बार घरों का सामान भी जल चुका है।

क्षेत्रवासी योगेश अरोड़ा बब्बू ने बताया कि करीब एक साल पहले पूरे मोहल्ले के लोगों के हस्ताक्षर करवाकर पावरकॉम अधिकारियों को शिकायत सौंपी गई थी।

गंदगी 1500 रुपये पर्ची के बावजूद सफाई बदहाल, फड़ी विक्रेता गंदगी में व्यापार को मजबूर

जस्सियां में कूड़े के ढेर से परेशान जनता, निगम व्यवस्था पर उठे सवाल

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना

हल्का नॉर्थ के अंतर्गत आने वाले जस्सियां क्षेत्र में नगर निगम के स्वच्छ लुधियाना अभियान के दावे सवालों के घेरे में आ गए हैं। इलाके में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर और फैली गंदगी के कारण स्थानीय लोगों और फड़ी विक्रेताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जस्सियां चौक के पास लगने वाली सब्जी मंडी में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दुकानदारों को बदबू और गंदगी के बीच बैठकर अपना कारोबार चलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

फड़ी विक्रेताओं का आरोप है कि नगर निगम की ओर से उनसे हर महीने 1500 रुपये की पर्ची वसूली जाती है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था के नाम पर रोजाना 20 रुपये प्रति फड़ी देने पड़ते हैं। इसके बावजूद इलाके में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। दुकानदारों का कहना है कि इतनी राशि देने के बाद भी उन्हें मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। कूड़े के बड़े बड़े ढेरों के कारण ग्राहकों ने भी मंडी में आना कम कर दिया है जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है।

सब्जी विक्रेता बाल किशन पप्पी, दर्शन साहनी और पिंकी देवी ने बताया कि वे कई वर्षों से यहां फड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफाई के लिए लगातार शिकायतें करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। गंदगी के

कूड़े के पहाड़ों के बीच सब्जी विक्रेताओं की जिंदगी बेहाल

कारण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है और सबसे ज्यादा परेशानी गरीब दुकानदारों को उठानी पड़ रही है।

स्थानीय निवासियों अमन गुप्ता, तरसेम सिंह और राजन कुमार ने बताया कि जस्सियां में बने कूड़े के अघोषित डंप को हटाने के लिए कई बार नगर निगम अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। जोन ए कार्यालय से लेकर निगम कमिश्नर तक शिकायतें भेजी गई हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इलाके की खराब स्थिति की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। बावजूद इसके समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।

लोगों ने स्थानीय पार्षद पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब पार्षद विपक्ष में थे तो इसी कूड़ा डंप को हटाने को लेकर आवाज उठाई गई थी और प्रदर्शन भी किए गए थे। लेकिन अब सत्ता में आने के बाद इस गंभीर समस्या पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजनीतिक कारणों के चलते जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सोमवार सिखाता है हर नई सुबह के साथ नए सपनों, नए संकल्पों और नई उम्मीदों को जीना

सप्ताह का पहला कार्यदिवस माने जाने वाला सोमवार केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं है बल्कि नई शुरुआत नए संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। भारतीय संस्कृति में सोमवार का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है क्योंकि यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। देशभर के शिवालयों में इस दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। लोग व्रत रखते हैं जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव से सुख समृद्धि तथा उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आधुनिक जीवन में भी सोमवार लोगों को बीते सप्ताह की थकान को पीछे छोड़कर नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

सोमवार शब्द का संबंध सीधे चंद्रमा से माना जाता है। संस्कृत में चंद्रमा को सोम कहा गया है इसलिए इस दिन का नाम सोमवार पड़ा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन भावनाओं और मानसिक संतुलन का कारक माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है और मन को शांति मिलती है। यही कारण है कि अनेक लोग इस दिन ध्यान योग और प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करते हैं।

केशव शर्मा 'रसिक'
कोटला, घुमारवीं, बिलासपुर

पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र धतूरा और भस्म अर्पित की जाती है। श्रद्धालु महामृत्युंजय मंत्र और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। ऐसा विश्वास है कि सच्चे मन से की गई आराधना जीवन की अनेक कठिनाइयों को दूर करती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है।

भारत के विभिन्न राज्यों में सोमवार की पूजा परंपराओं में कुछ भिन्नताएं अवश्य हैं लेकिन श्रद्धा का भाव हर जगह समान दिखाई देता है। उत्तर भारत में शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। दक्षिण भारत में भी शिवालयों में विशेष अभिषेक और आरती का आयोजन किया जाता है। सावन के सोमवार का महत्व तो और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दौरान लाखों कांवड़िए पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। यह परंपरा श्रद्धा अनुशासन और सामूहिक आस्था का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है।

सोमवार का व्रत भी भारतीय समाज में अत्यंत लोकप्रिय है। अनेक महिलाएं और पुरुष भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार का उपवास रखते हैं। मान्यता है कि इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। अविवाहित युवक युवतियां भी योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए सोलह सोमवार का व्रत रखते हैं। इस व्रत में सात्विक भोजन किया जाता है तथा दिनभर भगवान शिव के मंत्रों का स्मरण किया जाता है।

धार्मिक महत्व के साथ साथ सोमवार का व्यावहारिक महत्व भी कम नहीं है। अधिकांश सरकारी कार्यालय निजी संस्थान विद्यालय और महाविद्यालय इस दिन पूरे उत्साह के साथ अपने नियमित कार्य आरंभ करते हैं। कर्मचारी नई योजनाओं की शुरुआत करते हैं विद्यार्थी नए विषयों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और व्यापारी भी सप्ताह के लक्ष्य तय करते हैं। इस प्रकार सोमवार केवल धार्मिक आस्था का नहीं बल्कि कार्य संस्कृति और अनुशासन का भी प्रतीक है।

मनोविज्ञान के अनुसार सप्ताह की शुरुआत व्यक्ति की सोच और कार्यक्षमता पर गहरा प्रभाव डालती है। यदि सोमवार की शुरुआत सकारात्मक विचारों और स्पष्ट लक्ष्य के साथ की जाए तो पूरे सप्ताह का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोमवार को समय पर उठना हल्का व्यायाम करना संतुलित भोजन लेना और दिनभर की कार्य योजना पहले से तैयार करना लाभदायक होता है। इससे तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।

आज के तेज गति वाले जीवन में बहुत से लोग सोमवार को चुनौतीपूर्ण दिन मानते हैं क्योंकि सप्ताहांत के बाद फिर से काम शुरू करना पड़ता है। लेकिन यदि इसे अवसर के रूप में देखा जाए तो यही दिन नई उपलब्धियों का आधार बन सकता है। प्रत्येक सोमवार यह संदेश देता है कि बीती हुई गलतियों से सीख लेकर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हर नया सप्ताह जीवन में कुछ नया करने का अवसर लेकर आता है।

पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की शुरुआत भी सोमवार से की जा सकती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति सप्ताह के पहले दिन एक पौधा लगाने जल की बचत करने स्वच्छता बनाए रखने या किसी जरूरतमंद की सहायता करने का संकल्प ले तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े बदलाव का आधार बनते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अंतरिक्ष विज्ञान तक हर क्षेत्र को नई शक्ति देगा भारत का सेमीकंडक्टर मिशन

इक्कीसवीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में यदि किसी तकनीक को सबसे अधिक रणनीतिक महत्व प्राप्त है तो वह सेमीकंडक्टर है। आज दुनिया का लगभग हर आधुनिक उपकरण किसी न किसी रूप में सेमीकंडक्टर चिप पर आधारित है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, दूरसंचार, रक्षा प्रणाली, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, बैंकिंग नेटवर्क और अंतरिक्ष मिशन जैसे अनेक क्षेत्रों का संचालन इन्हीं चिप्स की सहायता से संभव हो रहा है। यही कारण है कि सेमीकंडक्टर को आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाता है। ऐसे समय में भारत सरकार द्वारा 1.27 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी देना केवल एक औद्योगिक योजना नहीं बल्कि भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

रजनीश रांगड़ा
प्रधानाचार्य, स्वर्ण जयंती राजकीय (उत्कृष्ट) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, टौणी देवी

पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने यह अनुभव किया कि तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कितनी आवश्यक है। कोविड महामारी के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से सेमीकंडक्टर चिप्स की भारी कमी उत्पन्न हुई। इसका सीधा प्रभाव वाहन उद्योग, मोबाइल निर्माण, कंप्यूटर उत्पादन और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पड़ा। कई बड़ी कंपनियों को उत्पादन रोकना पड़ा और उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि हुई। इस संकट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी देश के पास चिप निर्माण की अपनी क्षमता नहीं है तो उसकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकती हैं। भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल राष्ट्र के लिए यह स्थिति एक महत्वपूर्ण सीख थी।

आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में शामिल है। करोड़ों लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और फाइव जी जैसी तकनीकों का तेजी से विस्तार हो रहा है। इन सभी क्षेत्रों की सफलता का आधार सेमीकंडक्टर उद्योग है। ऐसे में भारत के लिए केवल चिप्स का आयात करने वाला देश बने रहना दीर्घकालिक दृष्टि से उचित नहीं था। इसलिए सरकार ने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत को केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाया जाए।

सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह केवल चिप निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी मूल्य श्रृंखला को विकसित करने पर जोर देता है। इसमें चिप डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, फैब्रिकेशन संयंत्र, एडवांस्ड पैकेजिंग, परीक्षण सुविधाएं, आवश्यक उपकरणों का निर्माण, कच्चे माल की उपलब्धता तथा कुशल मानव संसाधन तैयार करने जैसे अनेक क्षेत्रों को एक साथ मजबूत करने की योजना बनाई गई है। यह व्यापक दृष्टिकोण भारत को दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रदान कर सकता है।

मानव संसाधन विकास इस योजना का सबसे मजबूत पक्ष माना जा रहा है। देश के सैकड़ों विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने की योजना भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इससे भारतीय युवाओं को विश्वस्तरीय तकनीकी ज्ञान प्राप्त होगा और वे वैश्विक कंपनियों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी दक्षता विकसित कर सकेंगे। भारत के पास पहले से ही बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली इंजीनियर उपलब्ध हैं। यदि उन्हें अत्याधुनिक प्रशिक्षण और अनुसंधान का अवसर मिले तो भारत डिजाइन और नवाचार दोनों क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

> 'सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।'
> — डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

संपादकीय

समयबद्ध सेवा ही सुशासन की वास्तविक पहचान

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता केवल अच्छी नीतियां बनाने से नहीं मापी जाती बल्कि इस बात से तय होती है कि उन नीतियों और सरकारी सेवाओं का लाभ आम नागरिक तक कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता के साथ पहुंचता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने छोटे से काम के लिए महीनों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें तो विकास की बड़ी से बड़ी योजनाएं भी उसके लिए महत्व नहीं रखतीं। इसके विपरीत जब नागरिक को निर्धारित समय के भीतर बिना किसी भेदभाव के आवश्यक सेवा प्राप्त हो जाती है तब उसे शासन व्यवस्था पर विश्वास होता है। यही कारण है कि समयबद्ध सेवा को सुशासन की वास्तविक पहचान माना जाता है। सुशासन का अर्थ केवल सरकार चलाना नहीं है बल्कि ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है जो पारदर्शी हो उत्तरदायी हो संवेदनशील हो और नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति तत्पर हो। सुशासन में सरकार स्वयं को जनता का स्वामी नहीं बल्कि सेवक मानती है। नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान करना उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुनना और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना अनावश्यक देरी के उपलब्ध कराना सुशासन के प्रमुख आधार हैं।

समयबद्ध सेवा का अर्थ है कि किसी भी सरकारी कार्य के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित हो और उस समय सीमा के भीतर संबंधित अधिकारी सेवा उपलब्ध कराएं। जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र पेंशन स्वीकृति बिजली जल और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के लिए यदि निश्चित समय तय हो तथा उसका पालन किया जाए तो नागरिकों का समय धन और श्रम तीनों की बचत होती है। इससे प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत होता है। पहले के समय में सरकारी कार्यालयों में किसी साधारण कार्य को पूरा कराने में कई सप्ताह या कई महीने लग जाते थे। नागरिकों को बार बार दस्तावेज जमा करने पड़ते थे और एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक भटकना पड़ता था। कई बार जानकारी के अभाव या अनावश्यक प्रक्रियाओं के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस स्थिति ने भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया क्योंकि कुछ लोग जल्दी काम कराने के लिए अनुचित तरीकों का सहारा लेने लगे। इसलिए समयबद्ध सेवाओं की व्यवस्था लागू करना प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

आज देश के अनेक राज्यों ने लोक सेवा गारंटी कानून या समयबद्ध सेवा अधिनियम लागू किए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत अनेक सरकारी सेवाओं के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि अधिकारी निर्धारित समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई और दंड का भी प्रावधान है। इससे सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ी है और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई है। डिजिटल तकनीक ने समयबद्ध सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया है। अब अनेक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नागरिक घर बैठे आवेदन कर सकते हैं दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और कई प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इससे कार्यालयों में भीड़ कम हुई है पारदर्शिता बढ़ी है और अनावश्यक देरी में कमी आई है। डिजिटल भुगतान ऑनलाइन शिकायत पोर्टल और मोबाइल आधारित सेवाओं ने प्रशासन को अधिक सुलभ और उत्तरदायी बनाया है।

समयबद्ध सेवा केवल सुविधा का विषय नहीं बल्कि नागरिकों के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। जब किसी गरीब किसान को समय पर फसल सहायता मिलती है किसी छात्र को समय पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है किसी वृद्ध को निर्धारित समय पर पेंशन मिलती है या किसी मरीज को समय पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होती है तब शासन के प्रति उसका विश्वास मजबूत होता है। इसके विपरीत यदि सहायता समय पर नहीं पहुंचे तो उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। सुशासन का एक महत्वपूर्ण तत्व पारदर्शिता भी है। समयबद्ध सेवाओं के साथ यदि प्रक्रिया स्पष्ट हो आवेदन की स्थिति ऑनलाइन दिखाई दे और नागरिक को यह जानकारी हो कि उसका कार्य किस अधिकारी के पास लंबित है तो अनिश्चितता समाप्त होती है। इससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होती हैं और अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ती है। सूचना का अधिकार और ई गवर्नेंस जैसी व्यवस्थाओं ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

समयबद्ध सेवा का प्रभाव केवल नागरिकों तक सीमित नहीं रहता बल्कि इसका लाभ पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को मिलता है। जब उद्योगों को समय पर अनुमति मिलती है तो निवेश बढ़ता है। व्यापारियों को समय पर लाइसेंस और स्वीकृतियां मिलती हैं तो आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। किसानों को समय पर बीज खाद और अनुदान मिलता है तो कृषि उत्पादन बढ़ता है। विद्यार्थियों को समय पर प्रमाण पत्र और छात्रवृत्ति मिलती है तो उनकी शिक्षा बाधित नहीं होती। इस प्रकार समयबद्ध सेवाएं विकास की गति को तेज करती हैं। हालांकि समयबद्ध सेवाओं को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए कई चुनौतियां भी हैं। कुछ स्थानों पर कर्मचारियों की कमी है कहीं तकनीकी संसाधनों का अभाव है तो कहीं डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण लोग ऑनलाइन सेवाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। कई बार इंटरनेट की समस्या या सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण भी देरी होती है। इन चुनौतियों का समाधान बेहतर प्रशिक्षण आधुनिक तकनीक पर्याप्त संसाधन और प्रभावी निगरानी से किया जा सकता है।

–शिवांश धाकड़

सोनम वांगचुक का आमरण अनशन: आंदोलन क्यों कर रहे हैं और उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं?

प्रख्यात शिक्षा सुधारक, पर्यावरण कार्यकर्ता और नवाचार के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले सोनम वांगचुक एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर उनका आमरण अनशन देशभर में बहस का विषय बन गया है। उनके इस आंदोलन को केवल एक व्यक्ति का विरोध नहीं बल्कि युवाओं, शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक संवाद से जुड़े व्यापक मुद्दों के रूप में देखा जा रहा है। अनशन के दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। बाद में प्रशासन उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया।

सुखदेव सिंह
स्वतंत्र लेखक, नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

सोनम वांगचुक लंबे समय से शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी के समर्थक रहे हैं। वर्ष 2026 में उन्होंने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। उनका कहना है कि यह आंदोलन केवल किसी एक संगठन का नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं की आवाज है जो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपने अनशन के माध्यम से सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जिन्हें वे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मानते हैं।

इस आंदोलन का सबसे प्रमुख मुद्दा प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग है। आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि बार बार होने वाली अनियमितताओं ने लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित किया है। उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का विश्वास तब टूट जाता है जब परीक्षाएं रद्द होती हैं या प्रश्नपत्र लीक होने की खबरें सामने आती हैं। इसलिए वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह हो।

सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उनका तर्क है कि यदि लगातार परीक्षा संबंधी विवाद सामने आ रहे हैं तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आंदोलनकारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अनशन के दौरान सोनम वांगचुक की सेहत लगातार गिरती गई। चिकित्सकों ने उनके वजन में उल्लेखनीय कमी और स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे की चेतावनी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सरकार को उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। इसके बाद चिकित्सकीय सलाह के आधार पर पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले गई। हालांकि वांगचुक ने कहा कि उनका आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है और वे अपनी मांगों पर कायम रहेंगे।

उनके अस्पताल ले जाए जाने के बाद आंदोलन और तेज हो गया। उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध हटाया गया, जबकि प्रशासन का कहना था कि यह कदम उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सकीय सलाह के आधार पर उठाया गया। इस घटनाक्रम के बाद कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा सरकार से संवाद स्थापित करने की अपील की।

आंदोलन से जुड़े संगठनों ने 'चलो संसद' मार्च का भी आह्वान किया है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और अतिरिक्त बल की तैनाती की।

सोनम वांगचुक का कहना है कि उनका संघर्ष किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि देश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था के भविष्य के लिए है। उन्होंने कई अवसरों पर कहा कि यदि परीक्षाओं की विश्वसनीयता कमजोर होगी तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का विश्वास भी कमजोर होगा। उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए आवश्यक है।

इस आंदोलन ने देश में लोकतांत्रिक विरोध की भूमिका पर भी चर्चा शुरू कर दी है। एक पक्ष का मानना है कि शांतिपूर्ण अनशन लोकतंत्र में अपनी बात रखने का वैध माध्यम है, जबकि दूसरा पक्ष यह कहता है कि लंबे अनशन से जीवन को खतरा उत्पन्न होने पर प्रशासन का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

सादगी की मिसाल ग्रेसी सिंह

ग्रेसी सिंह

20 जुलाई 1980 को जन्मी ग्रेसी सिंह हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने सहज अभिनय, सादगी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के बल पर फिल्म उद्योग में एक अलग पहचान बनाई। ग्रेसी सिंह का जन्म दिल्ली में हुआ। बचपन से ही उन्हें नृत्य और अभिनय का शौक था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद अभिनय की दुनिया में कदम रखा। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने टेलीविजन धारावाहिकों से की, जहां उनके अभिनय को दर्शकों ने पसंद किया।

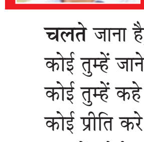

कविता

चलते जाना है

प्रवीण कुमार, गांव बाड़ा द घाट (सरेल) त. घुमारवीं

चलते जाना है, रुकना नहीं है, कोई तुम्हें समझे या ना समझे
कोई तुम्हें जाने या ना जाने, कोई तुम्हें पहचाने या ना पहचाने
कोई तुम्हें कहे अच्छा या कहे बुरा, कोई निंदा करे या करे स्तुति
कोई प्रीति करे या करे घृणा, रुकना नहीं है, चलते ही जाना है
जग में कोई नहीं है अपना, कौन कब स्वार्थ हेतु साथ छोड़ जाए
कोई नहीं जानता, अक्सर हमने लोगों को कलिकाल में
विश्वास को तोड़ते-मरोड़ते देखा है, हृदय को विदीर्ण करते देखा है
प्रेम में हमने देखे हैं, धोखे-सादगी का हमने मजाक बनते देखा है
ऐसा लगता है कि सब ओर गिरगिटों का अंबार है
अरे! फिर भी, फरेब से भरी दुनिया में, चलना तो है,
हर कदम फंक-फूंक कर चलिए, रुकना नहीं है, बस चलते ही जाना है
हे मानव! जग में स्वकर्तव्य का कर निर्वहन,
ईश्वर का सुमिरन करते जाओ तुम, प्रेमपूर्ण, भक्तिपूर्ण प्रार्थनाएं होती हैं
दया भाव से, करुणा से नित्य कबूल, तभी उस करुणामय, प्रेम के सागर
ईश्वर को हृदय से नमन है, वाणी से वंदन है, जो है इस सृष्टि का पालक
इस सृष्टि का मूल, रुकना नहीं है हमें जीवन में, प्रेम से, सच्चाई से
परोपकार हेतु, निरंतर आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है।

चंद्रमा तक पहुंचने का सपना बना मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि

हर वर्ष 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मानव इतिहास की उस ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में समर्पित है जब पहली बार इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मान्यता देकर अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान वैश्विक सहयोग और मानवता की साझा उपलब्धियों के महत्व को रेखांकित किया है। यह दिवस केवल अतीत की एक महान सफलता का स्मरण नहीं है बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों वैज्ञानिक खोजों और नई पीढ़ी को विज्ञान के प्रति प्रेरित करने का अवसर भी है।

डॉ. दुनी चंद
स्वतंत्र लेखक

20 जुलाई 1969 का दिन विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इसी दिन अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर उतरकर वह कर दिखाया जिसकी कल्पना सदियों से की जा रही थी। उस समय माइकल कॉलिन्स कमांड मॉड्यूल में चंद्रमा की कक्षा में मौजूद रहे। नील आर्मस्ट्रांग ने जब चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा तो उन्होंने कहा कि यह एक व्यक्ति का छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग है। यह कथन आज भी मानव साहस विज्ञान और नवाचार का प्रतीक माना जाता है।

चंद्रमा सदियों से मानव की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे देवत्व का प्रतीक माना तो वैज्ञानिकों ने इसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह समझकर इसके रहस्यों को जानने का प्रयास किया। दूरबीन के आविष्कार के बाद चंद्रमा के बारे में अध्ययन तेज हुआ और बीसवीं शताब्दी में अंतरिक्ष विज्ञान के विकास ने इसे वास्तविकता में बदल दिया। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा ने विज्ञान और तकनीक को नई दिशा दी। इसी प्रतिस्पर्धा का परिणाम अपोलो कार्यक्रम था जिसने मानव को पहली बार चंद्रमा तक पहुंचाया।

अपोलो 11 मिशन का प्रक्षेपण 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से किया गया था। शक्तिशाली सैटर्न फाइव रॉकेट के माध्यम से यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से रवाना हुआ और चार दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। इसके बाद लूनर मॉड्यूल ईगल अलग होकर चंद्रमा की सतह पर उतरा। उतरने की प्रक्रिया अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि वहां कोई वायुमंडल नहीं था और हर निर्णय कुछ ही क्षणों में लेना था। फिर भी वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों की तैयारी ने इस अभियान को सफल बनाया।

नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने लगभग ढाई घंटे तक चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक कार्य किए। उन्होंने चंद्र मिट्टी और पत्थरों के नमूने एकत्र किए वैज्ञानिक उपकरण स्थापित किए और कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इन नमूनों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को चंद्रमा की आयु उसकी संरचना और सौर मंडल के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इन खोजों ने ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले।

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 में 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में घोषित किया। इस निर्णय का उद्देश्य चंद्र अन्वेषण के इतिहास को सम्मान देना अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और सभी देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करना था। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अंतरिक्ष किसी एक देश की संपत्ति नहीं बल्कि पूरी मानवता की साझा धरोहर है। इसलिए अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग पारदर्शिता और जिम्मेदारी अत्यंत आवश्यक है।

आज चंद्रमा केवल वैज्ञानिक अध्ययन का विषय नहीं रह गया है बल्कि भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं का आधार भी बनता जा रहा है। कई देश चंद्रमा पर स्थायी अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहां उपलब्ध जल बर्फ खनिज और अन्य संसाधनों का अध्ययन भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों को नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर विकसित होने वाली तकनीकें भविष्य में मंगल ग्रह और उससे आगे की मानव यात्राओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगी।

भारत ने भी चंद्र अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान अभियानों के माध्यम से दुनिया में अपनी वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया है। चंद्रयान एक मिशन ने चंद्रमा पर जल अणुओं के प्रमाण खोजकर वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को नई जानकारी दी। इसके बाद चंद्रयान दो ने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आंकड़े जुटाए। वर्ष 2023 में चंद्रयान तीन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना जिसने दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सुरक्षित लैंडिंग की। इस सफलता ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के अग्रणी देशों की श्रेणी में स्थापित कर दिया।

चंद्र अनुसंधान का महत्व केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से विकसित होने वाली तकनीकें पृथ्वी पर भी अनेक क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध होती हैं। संचार प्रणाली उपग्रह तकनीक कंप्यूटर प्रणाली रोबोटिक्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सा उपकरण और मौसम पूर्वानुमान जैसी अनेक आधुनिक तकनीकों के विकास में अंतरिक्ष अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार चंद्र अभियानों से प्राप्त ज्ञान मानव जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी योगदान देता है।

अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस युवाओं और विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रेरणा का अवसर है। इस दिन विद्यालयों महाविद्यालयों और विज्ञान संस्थानों में व्याख्यान विज्ञान प्रदर्शनी निबंध प्रतियोगिता मॉडल निर्माण खगोल विज्ञान शिविर और अंतरिक्ष विषयक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य नई पीढ़ी में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उन्हें अनुसंधान तथा नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

न्यूज ब्रीफ

माँ भुवनेश्वरी धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

एजेंसी, हमीरपुर। आषाढ़ माह के तीसरे रविवार को हमीरपुर जिले के कुरारा विकास खंड क्षेत्र के झलोखर गांव स्थित करीब 700 वर्ष प्राचीन भुइयाँरानी माँ भुवनेश्वरी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। आयोजित विशाल धार्मिक मेले में दूर-दराज क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु पहुंचे और माँ भुवनेश्वरी की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और परंपरा के अनुसार भौरियां बनाकर माँ को अर्पित कीं। मंदिर परिसर की पवित्र रज के लेपन की धार्मिक मान्यता भी लोगों की आस्था का केंद्र रही। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इससे जोड़ों के दर्द और अन्य परेशानियों में लाभ मिलता है। मेले में महिलाओं और बच्चों ने जमकर खरीदारी की। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा। मंदिर प्रबंधक निर्भयदास प्रजापति ने बताया कि अगला विशाल मेला 26 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।

खेल विश्वविद्यालय में प्रवेश शुरू 31 जुलाई तक करें आवेदन

एजेंसी, मुरादाबाद। मेजर ध्यान चंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्रीड़ाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रवेश संबंधी विवरण और प्रॉस्पेक्टस जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। इस सत्र में बीपीईएस, बीएससी योग, एमएससी योग, खेल पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा तथा खेल प्रशिक्षण के पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। खेल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती और योग जैसे विषय शामिल हैं। उन्होंने बताया कि खेल क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए यह विश्वविद्यालय बेहतर अवसर प्रदान करेगा। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है।

यात्रियों से अभद्रता पर नौ किन्नर गिरफ्तार

एजेंसी, कानपुर। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से अभद्रता करने, जबरन पैसे मांगने और विरोध करने पर हंगामा करने के आरोप में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने नौ किन्नरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ शांति भंग की आशंका में बीएनएसएस की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। जीआरपी थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह ने बताया कि स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि प्लेटफॉर्म संख्या-10 और ट्रेनों में कुछ लोग यात्रियों से जबरन पैसे मांग रहे हैं और विरोध करने पर अभद्र व्यवहार कर रहे हैं।

सौ साल पुराने कुएं के जीर्णोद्धार की उठी मांग

एजेंसी, वाराणसी। वाराणसी के नदेसर से घोसाबाद मार्ग पर स्थित सौ वर्ष पुराने कुएं के जीर्णोद्धार की मांग स्थानीय लोगों ने उठाई है। नदेसर विकास समिति से जुड़े लोगों ने कुएं के रखरखाव और सुंदरीकरण की मांग की है। समिति के शिव प्रकाश ने बताया कि यह प्राचीन कुआं लंबे समय से उपेक्षित है और अब खराब स्थिति में पहुंच गया है। स्थानीय निवासी सच्चिदानंद तिवारी ने कहा कि पहले मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत इसी कुएं से होती थी। आज भी लोग यहां पूजा करने आते हैं।

सड़क पर बिखरी गिट्टी से फिसली बाइक से मौत

एजेंसी, मीरजापुर। पड़री थाना क्षेत्र के उसरहवा गांव के पास सड़क पर बिखरी गिट्टी के कारण बाइक फिसलने से एक अधेड़ की मौत हो गई। शिवगढ़ निवासी रामदास (46) डगमगपुर चौराहे से घर लौट रहे थे, तभी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पड़री पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने सड़क पर फैली गिट्टी को हादसे का कारण बताते हुए सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। सड़क पर फैली गिट्टी हटाने के लिए ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से कार्रवाई की मांग की।

प्रतापगढ़ में सई नदी में डूबे तीन किशोर, तलाश अभियान जारी

एजेंसी, प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। नगर कोतवाली क्षेत्र के खीरी बीर घाट पर घूमने गए तीन किशोर सई नदी के तेज बहाव में डूब गए। हादसे में दो सगे भाई भी शामिल हैं। घटना के बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार तीनों किशोरों की तलाश में जुटी हुई है।

जानकारी के अनुसार, अचलपुर लेखपाल कॉलोनी निवासी कृष्णा सोनी (13), अनुराग सोनी (15) पुत्र रामजी सोनी और अमित सोनी (16) पुत्र राजू सोनी रविवार सुबह सई नदी के खीरी बीर घाट पर पहुंचे थे। तीनों किशोर नदी में नहाने के लिए उतरे, लेकिन अचानक गहरे पानी और तेज धारा की चपेट में आ गए और डूब गए। घटना के समय नदी में मौजूद कुछ मछुआरों ने किशोरों को डूबते देखा। उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई।

नगर कोतवाली पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान शुरू कराया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नदी के तेज बहाव के कारण खोज अभियान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समाचार लिखे जाने तक तीनों किशोरों का पता नहीं चल सका था। हादसे की जानकारी मिलने के बाद किशोरों के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। बच्चों के नदी में डूबने की खबर से परिवार में चीख-पुकार मच गई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में उफनती नदियों और गहरे जलाशयों में जाने से बचें। सुरक्षा नियमों का पालन कर ऐसे हादसों से बचा जा सकता है।

भारत में शिक्षा थी पूर्णतया नि :शुल्क अंग्रेजों ने लगाया शुल्क : डॉ. कृष्ण गोपाल

डॉ. कृष्ण गोपाल ने अंग्रेजों की शिक्षा नीति पर उठाए सवाल

एजेंसी, लखनऊ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा कि प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह नि:शुल्क थी। गुरुकुलों में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ भोजन, वस्त्र, औषधि और पुस्तकों की सुविधा भी बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाती थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा में शुल्क लगाने की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई।

डॉ. कृष्ण गोपाल रविवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में महामना शिक्षण संस्थान के नए सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश तेजी से भौतिक विकास कर रहा है। बड़े बड़े राजमार्ग और हवाई अड्डे बन रहे हैं, लेकिन अभी भी समाज का बड़ा हिस्सा उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। इससे समाज में असंतोष की स्थिति पैदा होती है।

उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत समृद्ध रहा है। भारत ने दुनिया को व्याकरण, अक्षर ज्ञान, दशमलव प्रणाली, गणित, त्रिकोणमिति और खगोलीय गणना जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने दावा किया कि भारत ने प्राचीन समय में जहाज निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

सह सरकार्यवाह ने कहा कि भारत के लगभग हर गांव में शिक्षा के केंद्र मौजूद थे। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में देश विदेश से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रमणों और बाद में अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय शिक्षा व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईआईटी लखनऊ के निदेशक प्रो. अरुण मोहन शेरी ने कहा कि महामना शिक्षण संस्थान समाज को दिशा देने और बदलाव लाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों में बढ़ते तनाव और आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दुर्ग सिंह चौहान ने कहा कि संस्कारों की शुरुआत घर से होती है। उन्होंने कहा कि देश की कई समस्याओं का समाधान बेहतर शिक्षा व्यवस्था से संभव है।

डॉ. अणिमा जामवाल ने बताया कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और भाऊराव देवरस की प्रेरणा से महामना मालवीय शिक्षण संस्थान समाज में शिक्षा और संस्कारों के प्रसार का कार्य कर रहा है।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील की

एजेंसी, लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए छात्रों और उनके अभिभावकों का समर्थन किया है। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि यूनिवर्सिटी को लेकर चल रही मुहिम में समाजवादी पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और जौहर यूनिवर्सिटी को राजनीतिक निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर होते हैं और इन्हें बचाना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने देशभर के लोगों से शिक्षा संस्थान को बचाने के लिए साथ आने की अपील की।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी भी तरह की कागजी कमी है तो उसे पूरा करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में विभिन्न वर्गों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और किसी भी कार्रवाई से छात्रों और उनके परिवारों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।

अखिलेश यादव ने भाजपा पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षित और जागरूक लोग सवाल उठाते हैं, इसलिए सरकार को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है और इसका समाधान संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में छात्रों और उनके परिवारों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से संवेदनशीलता के साथ समाधान निकालने की मांग की और कहा कि किसी भी कार्रवाई से विद्यार्थियों की शिक्षा व भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है।

चुनावी रणनीति को धार देने में जुटा रालोद संगठन

बरेली में 1 .30 करोड़ का कैमिकल बरामद

एजेंसी, बरेली

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) बरेली यूनिट ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार सक्रिय तस्करों को गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपितों के कब्जे से 498.35 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड प्रीकर्सर कैमिकल बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1.30 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

एएनटीएफ ने बरेली में 498 किलो कैमिकल संग चार तस्करों को किया गिरफ्तार

यह कार्रवाई 18 जुलाई को थाना शाही क्षेत्र के ग्राम जुनहाई बिजलीघर के सामने की गई। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान जोगेश उर्फ पिंकू, वासिद, तेजपाल सिंह और अरुण कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से दो वाहन, पांच मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी हरियाणा के मेवात से कैमिकल लेकर आए थे और इसे आगे सप्लाई करने की योजना थी। एएनटीएफ अधिकारियों के अनुसार, इस कैमिकल का उपयोग हेरोइन जैसे मादक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है।

जालौन में पुलिस ने 467 लीटर अवैध कच्ची शराब कराई नष्ट

एजेंसी, उरई। अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए जालौन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के तहत कोंच कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर वर्ष 2024 में आबकारी अधिनियम के मामलों में बरामद की गई 467 लीटर अवैध कच्ची शराब को नष्ट कराया। रविवार को कोंच कोतवाली क्षेत्र के पहाड़गांव कैलिया बाईपास रोड पर यह कार्रवाई की गई। नष्टीकरण की प्रक्रिया क्षेत्राधिकारी परमेश्वर प्रसाद की मौजूदगी में पूरी हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह शराब आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 37 मुकदमों में अलग-अलग स्थानों से बरामद की गई थी। पुलिस टीम ने निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए शराब को नष्ट कराया। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। अधिकारी ने कहा कि अवैध शराब निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

कालपी में लाखों की चोरी, ताला तोड़ जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार बदमाश

एजेंसी, उरई

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कालपी कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब छह लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना का पता रविवार सुबह उस समय चला, जब गृहस्वामी विपिन कुमार घर लौटे और मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि अलमारी और बक्सों का सामान बिखरा पड़ा था तथा जेवरात और नकदी गायब थे।

जानकारी के अनुसार, कालपी के इंद्रानगर मोहल्ला निवासी विपिन कुमार किसी जरूरी काम से घर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान देर रात अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के मुताबिक, चोरी हुए सामान की कुल कीमत लगभग छह लाख रुपये है। घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए। सूचना मिलते ही कालपी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तथा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

जनसंवाद में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने सुनीं लोगों की समस्याएं

एजेंसी, मीरजापुर

अपना दल (एस) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने रविवार को सरदार पटेल चौराहा स्थित सांसद जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में आमजन की समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों, एनडीए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन तथा अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें और मांगें मंत्री के समक्ष रखीं।

आमजन की शिकायतों पर गंभीर हुए मंत्री आशीष पटेल अधिकारियों से मांगा शीघ्र समाधान।

आशीष पटेल ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की और सभी मामलों का शीघ्र, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का समयबद्ध लाभ मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जनता की सेवा ही जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्व है और प्रत्येक नागरिक की समस्या का समाधान उनकी प्राथमिकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादियों ने प्रार्थना पत्र सौंपे, जिन पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मंत्री ने सभी मामलों की निगरानी कर समाधान सुनिश्चित करने की बात कही।

डंफर की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत

एजेंसी, महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में रविवार को तेज रफ्तार डंफर की चपेट में आने से बाइक सवार दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा कबरई कस्बे के पाठक पुलिया के पास हुआ। दोनों युवक चित्रकूट से मध्य प्रदेश के सागर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार, कुबेर गंज कर्वी निवासी सोनह्यू सोनी (32) और शंकर बाजार निवासी अश्विनी सोनी (30) रात में बाइक से घर से निकले थे। कबरई क्षेत्र में तेज रफ्तार डंफर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अश्विनी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाते समय सोनू की भी मौत हो गई। कबरई थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस टक्कर मारने वाले डंफर की तलाश कर रही है। शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद मृतकों के परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने बताया कि दोनों युवक आपस में दोस्त थे और किसी काम से मध्य प्रदेश के सागर जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया है। डंफर चालक की पहचान और तलाश के लिए पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और डंफर चालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है।

परीक्षा में चयन न होने से आहत छात्रा ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत

एजेंसी, उरई

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के मोहल्ला दीवानपुरा में नीट परीक्षा में चयन न होने से आहत 18 वर्षीय छात्रा श्रुति साहू की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना से परिवार और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। परिजनों के अनुसार, नीट परीक्षा का परिणाम आने के बाद से श्रुति मानसिक तनाव में थी। अपेक्षित अंक न मिलने के कारण उसका मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं हो सका, जिससे वह काफी निराश रहने लगी थी।

बताया गया कि देर रात उसने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जालौन के उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्रा की मृत्यु की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और आसपास के लोग भी घर पहुंच गए। पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है। क्षेत्राधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी।

जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा के परिजनों, पड़ोसियों और परिचितों से पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि घटना से जुड़ी सभी परिस्थितियों की स्पष्ट जानकारी मिल सके। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, छात्रा की असमय मौत से पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है और लोग परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंपकर आगे की कार्रवाई शुरू की।

आत्मनिर्भरता खेत तालाबों से जल संरक्षण के साथ किसानों को मिल रहा अतिरिक्त आय का अवसर

मत्स्य पालन और मोती खेती बनी कमाई का जरिया

एजेंसी, कानपुर

खेत तालाब अब केवल सिंचाई और जल संरक्षण का माध्यम नहीं रह गए हैं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का नया जरिया भी बन रहे हैं। कानपुर जिले में खेत तालाबों को मत्स्य पालन, मोती की खेती और अन्य आयवर्धक गतिविधियों से जोड़कर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल की जा रही है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार को कहा कि इस मॉडल को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाया जाएगा।

बिधनू विकासखंड के ग्राम सम्भुआ में एक किसान ने खेत तालाब में मोती उत्पादन और मत्स्य पालन को जोड़कर आय बढ़ाने का अनोखा उदाहरण पेश किया है। यहां किसान रश्मि वर्मा के खेत तालाब में करीब 30 हजार सीपियों के माध्यम से मोती तैयार किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि विशेष मोल्ड तकनीक की मदद से स्वस्तिक, भगवान गणेश, फूल और पत्तियों जैसी विभिन्न आकृतियों वाले डिजाइनर मोती तैयार किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भूमि संरक्षण अनुभाग की ओर से रश्मि वर्मा के खेत में 22 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और तीन मीटर गहरा तालाब बनवाया गया था।

योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण के लिए उन्हें 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 52,500 रुपये का अनुदान सीधे बैंक खाते में दिया गया। कृषि विभाग और मणि एग्रो हब से प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने मोती उत्पादन का कार्य शुरू किया। इस परियोजना में लगभग 18 से 20 लाख रुपये की लागत आई है। प्रत्येक सीपी से दो मोती तैयार किए जा रहे हैं। परियोजना को शुरू हुए करीब नौ महीने हो चुके हैं और लगभग 18 महीने में मोती पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि तैयार होने वाले मोतियों की बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपये तक हो सकती है।

इस तकनीक की खासियत यह है कि सीपियों में विशेष मोल्ड लगाए जाते हैं, जिन पर धीरे धीरे मोती की परत चढ़ती है। इससे सामान्य मोतियों की तुलना में आकर्षक डिजाइन वाले मोती तैयार होते हैं, जिनकी बाजार में अधिक मांग रहती है और किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

रश्मि वर्मा ने बताया कि उनके दूसरे खेत तालाब में मत्स्य पालन भी किया जा रहा है। अब तक तीन बार मछली उत्पादन हो चुका है और इससे हर साल लगभग चार लाख रुपये की अतिरिक्त आय मिलने की उम्मीद है। उन्होंने अन्य किसानों से भी खेत तालाबों का उपयोग आय बढ़ाने वाली गतिविधियों से जोड़ने की अपील की।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के अन्य खेत तालाब लाभार्थियों को भी मत्स्य पालन, मोती की खेती और अन्य बहुउद्देशीय कार्यों से जोड़ा जाए। उन्होंने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण भी किया तथा खेत तालाबों की साफ सफाई और आसपास वृक्षारोपण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कृषि विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे और किसानों को उन्नत किस्म के ज्वार और सांवा की मिनीकिट भी वितरित की गई।

नेपाल सीमा पर 53 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, भारतीय और नेपाली मुद्रा भी बरामद

एजेंसी, बहराइच

भारत-नेपाल सीमा पर नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बहराइच पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। रूपईडीहा थाना पुलिस और एसएसबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 53 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से भारतीय और नेपाली मुद्रा भी बरामद हुई है।

भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस की कार्रवाई, स्मैक तस्करी का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में और प्रभारी निरीक्षक हरेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, 18 जुलाई की रात सीमा क्षेत्र में गश्त के दौरान संयुक्त टीम नेपाल सीमा की ओर जाने वाले रास्ते पर निगरानी कर रही थी। इसी दौरान पिलर संख्या 651/2 के पास नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जो भारतीय सीमा से नेपाल की तरफ जा रहा था।

रूपईडीहा पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता

संदेह होने पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से 53 ग्राम अवैध स्मैक, 200 रुपये भारतीय मुद्रा और 100 रुपये नेपाली मुद्रा बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान शमीम अहमद (38 वर्ष) पुत्र लल्लन रायनी, निवासी चिकवन मोहल्ला मुनीरगंज, थाना रूपईडीहा, जनपद बहराइच के रूप में बताई। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ रूपईडीहा थाने में मुकदमा संख्या 182/2026 दर्ज किया है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की प्रक्रिया शुरू की गई है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं। वर्ष 2022, 2023 और 2025 में भी उसके विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस ने कहा कि सीमा क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

पंचकूला में कांग्रेस का मंथन, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला

हरियाणा कांग्रेस ने संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में पंचकूला में जिला कांग्रेस कमेटी की संवाद एवं संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने की। इसमें हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, पंचकूला के विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई, जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय चौहान सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

बैठक के दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और जनसंपर्क अभियान को प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं से संगठन की वर्तमान स्थिति, स्थानीय मुद्दों और जनता के बीच पार्टी की गतिविधियों को लेकर फीडबैक भी लिया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में संगठन को सक्रिय बनाने के लिए आवश्यक सुझावों पर भी विचार किया गया। प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि मजबूत बूथ संगठन किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत होता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से संगठन को और मजबूत बनाया जाएगा। बैठक में जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने, स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए जनता के बीच लगातार संवाद बनाए रखने तथा भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने पर भी सहमति व्यक्त की गई।

हरियाणा में अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करने की नई नीति हुई लागू

सरकार देगी सड़क पेयजल सीवरेज समेत सुविधाएं हजारों उद्योगों और श्रमिकों को मिलेगा लाभ

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने राज्य की अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नई नीति लागू कर दी है। इस नीति के तहत अब ऐसी औद्योगिक कॉलोनियों को सिविक अमेनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशिएंट एरिया घोषित किया जा सकेगा। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और काम करने वाले उद्यमियों व श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

नई व्यवस्था के तहत नियमित किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और अन्य जरूरी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य उन औद्योगिक क्षेत्रों को राहत देना है, जहां बड़ी संख्या में उद्योग संचालित हो रहे हैं लेकिन अभी तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

नीति के अनुसार किसी भी औद्योगिक कॉलोनी को नियमित कराने के लिए उसका क्षेत्रफल कम से कम 10 एकड़ का लगातार क्षेत्र होना जरूरी होगा। इसके अलावा उस क्षेत्र में न्यूनतम 50 औद्योगिक इकाइयों का संचालन होना भी अनिवार्य किया गया है। केवल वही औद्योगिक इकाइयां इस योजना का लाभ ले सकेंगी, जो 3 अक्तूबर 2025 से पहले स्थापित की गई होंगी।

सरकार ने वर्ष 2022 की नीति और वर्ष 2023 में जारी राहत संबंधी निर्देशों में संशोधन करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की है। पहले अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियां इस नीति के दायरे में शामिल नहीं थीं, लेकिन वर्ष 2025 में कानून में बदलाव के बाद अब औद्योगिक क्षेत्रों को भी नियमितीकरण प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है।

स्वामित्व प्रमाण के लिए 3 अक्तूबर 2025 से पहले के पंजीकृत बिक्री विलेख या एग्रीमेंट टू सेल को मान्य माना जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पिछले बजट में इस संबंध में घोषणा की थी। इसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। संशोधित नीति जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर इच्छुक औद्योगिक कॉलोनियों को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ शजरा प्लान, लेआउट प्लान, ड्रोन और सेटेलाइट इमेज, स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज, बिजली बिल, फैक्ट्री लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति, फायर एनओसी सहित करीब 15 प्रकार के दस्तावेज जमा करने होंगे।

डीएलएफ फेज-चार में अवैध निर्माण हटाए, 10 भवनों को किया गया सील

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीपीई) ने गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-चार में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। शनिवार को चलाए गए रेस्टोरेशन और सीलिंग अभियान के दौरान रिहायशी भवनों में संचालित 10 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माणों को भी हटाया गया और भवनों को मूल स्वरूप में बहाल करने की प्रक्रिया अपनाई गई। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अभियान का उद्देश्य रिहायशी क्षेत्रों में नियमों के विरुद्ध चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाना और न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना था। कार्रवाई के दौरान कार डिटेलिंग सेंटर, पीजी, गेस्ट हाउस, क्लीनिक, जिम, स्पा, डांस स्टूडियो, क्लाउड किचन तथा कार्यालयों सहित विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने वाले भवनों को सील किया गया। इसके अलावा भवनों के सेटबैक और स्टिल्ट पार्किंग क्षेत्रों में किए गए अवैध निर्माणों को भी हटाया गया। अभियान सुबह से शुरू होकर पूरे दिन चला। इस दौरान पुलिस बल और डीटीपीई की टीम संयुक्त रूप से विभिन्न स्थानों पर मौजूद रही, ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की जा सके। अधिकारियों ने सबसे पहले प्लॉट नंबर-1210 पर संचालित स्काईलाइन कार डिटेलिंग सेंटर को सील किया। यहां साइड सेटबैक में किए गए अतिरिक्त निर्माण को भी ध्वस्त कर भवन को मूल स्वरूप में बहाल कराया गया। इसके बाद अन्य चिन्हित भवनों पर भी क्रमवार कार्रवाई की गई। विभाग का कहना है कि रिहायशी क्षेत्रों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना नियमानुसार प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में पहले संबंधित संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सीलिंग और रेस्टोरेशन की कार्रवाई करनी पड़ी।

न्यूज ब्रीफ

महम में युवक ने फांसी लगाकर दी जान पिता ने लगाए गंभीर आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, रोहतक। महम क्षेत्र में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। परिजनों के अनुसार, दो दिन पहले युवक का गांव के कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था। मृतक के पिता का आरोप है कि विवाद के बाद लगातार मानसिक दबाव और प्रताड़ना के कारण उनका बेटा आत्महत्या करने के लिए विवश हो गया। उन्होंने मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के अनुसार उचित कदम उठाए जाएंगे।

रोहतक में हुड्डा का भाजपा पर हमला, बोले लोकतंत्र की उड़ रही धज्जियां

भारतेन्दु संवाददाता, रोहतक। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य और केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी कर रही है। अपने संबोधन के दौरान हुड्डा ने हरियाणवी अंदाज में कहा, 'भाजपा में कौन बाबू, मन्नै कोनी बेरा', जिस पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रतिक्रिया दी। हुड्डा ने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान हटाकर राजनीतिक लाभ लेने में लगी हुई है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार प्रभावी कदम नहीं उठा रही। कांग्रेस जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और लोगों तक पार्टी की नीतियां पहुंचाने का आह्वान किया। भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए सरकार की नीतियों का बचाव किया।

शराबी थार चालक की टक्कर से हवा में उछली बलेनो, बड़ा हादसा टला

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। कथित तौर पर शराब के नशे में धुत थार चालक ने एक बलेनो कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बलेनो हवा में उछलकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के बाद थार भी पलट गई, लेकिन चालक बाहर निकलकर मौके पर मौजूद लोगों से बहस और बदसलूकी करने लगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच कराई। मामले की जांच जारी है और वीडियो सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

वृंदावन से लौट रहे पांच दोस्तों की कार हादसे का शिकार, दो की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, पलवल। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर रविवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में ग्रेटर नोएडा के दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवक वृंदावन में शनिदेव के दर्शन कर एक ही कार से अपने घर लौट रहे थे। सुबह करीब 6:30 बजे उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर दूसरी कार से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दादरी निवासी हिमांशु और राजपुर निवासी निशांत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

ऑनलाइन शॉपिंग के पार्सल बॉक्स से डेटा चुराकर लोगों को ठग रहे साइबर अपराधी

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता चलन लोगों के लिए सुविधा लेकर आया है, लेकिन इसके साथ साइबर ठगों ने ठगी के नए-नए तरीके भी अपनाने शुरू कर दिए हैं। अब अपराधी घरों से फेंके गए ऑनलाइन शॉपिंग के पार्सल बॉक्स और उनके शिपिंग लेबल का इस्तेमाल कर लोगों की निजी जानकारी चुराकर उन्हें निशाना बना रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए फतेहाबाद पुलिस ने लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

पुलिस के अनुसार, पार्सल बॉक्स पर लगे शिपिंग लेबल में उपभोक्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर और कई बार अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी दर्ज होती है। साइबर अपराधी इन जानकारियों का दुरुपयोग कर खुद को ई-कॉमर्स कंपनी, बैंक या कूरियर एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर लोगों से संपर्क करते हैं। इसके बाद वे कैशबैक, गिफ्ट वाउचर, रिफंड या इनाम का लालच देकर फर्जी लिंक भेजते हैं और लोगों से बैंकिंग या व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं।

पुलिस ने बताया कि कई मामलों में ठग ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी या अन्य गोपनीय विवरण लेकर लोगों के खातों से रकम भी निकाल लेते हैं। इसलिए किसी भी अनजान कॉल, संदेश या लिंक पर बिना जांच किए भरोसा नहीं करना चाहिए। फतेहाबाद पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन शॉपिंग के बाद पार्सल बॉक्स को सीधे कूड़ेदान में फेंकने के बजाय पहले उस पर लगे शिपिंग लेबल को पूरी तरह फाड़ दें या नष्ट कर दें, ताकि उस पर लिखी जानकारी किसी के हाथ न लगे। इसके अलावा संदिग्ध कॉल, संदेश या लिंक मिलने पर तुरंत सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की निजी या बैंकिंग जानकारी साझा न करें।

अंबाला कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला

अंबाला की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी निर्धारित जुर्माना जमा नहीं करता है, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 9 सितंबर 2023 को सामने आया था। सिविल अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली थी कि 16 वर्षीय एक नाबालिग गर्भवती पाई गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सीय परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। सभी तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने के बाद सजा पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पानीपत हत्याकांड, गठरी में शव बांधकर साइकिल से ले गया आरोपी

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत। पानीपत में एक दिल दहला देने वाला हत्या का मामला सामने आया है। आरोपित ने एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद शव को गठरी में बांधा और उसे साइकिल पर रखकर करीब ढाई किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर फेंक दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने सनसनी फैला दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जांच में आरोपित की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने हत्या की वजह भी बताई। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस ने बताया कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।

करनाल के कुंजपुरा गोदाम से 9951 गेहूं के कट्टे गायब, पूर्व निरीक्षक विभागीय जांच में दोषी

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल

करनाल के कुंजपुरा स्थित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सरकारी गेहूं गोदाम में करोड़ों रुपये के कथित गबन मामले में विभागीय जांच के दौरान नया खुलासा हुआ है। जांच में 9,951 गेहूं के कट्टे और गायब पाए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2.73 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस मामले में विभाग ने सेवानिवृत्त निरीक्षक अशोक शर्मा को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इससे पहले भी गोदाम में गेहूं की कमी को लेकर जांच चल रही थी।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, नवीन जांच में सामने आई कमी के बाद अब गोदाम से कुल 16,355 गेहूं के कट्टे गायब होने की बात सामने आई है। इन कट्टों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 4.49 करोड़ रुपये आंकी गई है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि गोदाम के संचालन और भंडारण व्यवस्था में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके आधार पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। दूसरी ओर, सेवानिवृत्त निरीक्षक अशोक शर्मा ने विभाग के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें गलत तरीके से दोषी बनाया जा रहा है। उनका दावा है कि इस पूरे मामले के लिए तत्कालीन एएफएसओ मुकेश गुप्ता जिम्मेदार हैं।

उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आने पर वास्तविक जिम्मेदारों का पता चल जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर ने गोदाम में अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद विस्तृत जांच के आदेश दिए थे। जांच आगे बढ़ने के साथ लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब विभाग की रिपोर्ट और दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार, जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अभिलेखों, स्टॉक रजिस्टर और गोदाम में रखे गेहूं के भौतिक सत्यापन का मिलान किया गया। अधिकारियों का कहना है कि मामले में वित्तीय अनियमितताओं के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।

तालाब में नहाने गया युवक नहीं लौटा, डूबने से हुई मौत

भारतेन्दु संवाददाता, नारनौल। नारनौल क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से युवक के शव को तालाब से बाहर निकलवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार, युवक नहाने के लिए तालाब में गया था। नहाते समय वह अचानक गहरे पानी में चला गया और बाहर नहीं निकल सका। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मृतक तीन बच्चों का पिता था। उसकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया और उसे परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हादसे का प्रतीत होता है।

टोल प्लाजा सुरक्षा ठेकेदार की हत्या पार्टी के बहाने बुलाकर बरसाई गोलियां

भारतेन्दु संवाददाता, झज्जर

झज्जर जिले में टोल प्लाजा के एक सुरक्षा ठेकेदार की गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात में बीच-बचाव करने आए ठेकेदार के भतीजे को भी गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने सुरक्षा ठेकेदार को पार्टी के बहाने एक स्थान पर बुलाया था। वहां पहुंचते ही आरोपितों ने उस पर ताबड़तोड़ तीन राउंड फायर कर दिए। गोलियां लगने से ठेकेदार गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। इस दौरान उसे बचाने के लिए आगे आए उसके भतीजे के पैर में भी गोली मार दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल भतीजे का अस्पताल में इलाज जारी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश या आपसी विवाद की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। घायल और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं तथा आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया और आसपास के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। पुलिस ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ की। अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा।

हेरिटेज दर्जे के बावजूद कैथल की सरस्वती नदी जलकुंभी, गंदगी और दुर्गंध से हुई बदहाल

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल

हरियाणा के कैथल जिले के पोलड गांव से होकर गुजरने वाली पौराणिक सरस्वती नदी हेरिटेज नदी का दर्जा मिलने के बावजूद बदहाली का सामना कर रही है। नदी के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। नदी का बड़ा हिस्सा जलकुंभी से ढका हुआ है और गंदगी के कारण इसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, नदी के पानी से तेज दुर्गंध उठती है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलकुंभी के अत्यधिक फैलाव के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही नदी में जहरीले सांप, बिच्छू और अन्य कीटों का बसेरा बन जाने से आसपास के क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।

सरस्वती नदी के किनारे स्थित प्राचीन सरस्वती मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां वर्षभर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन नदी की बदहाल स्थिति श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों दोनों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सफाई और संरक्षण का कार्य नहीं किया गया तो नदी की स्थिति और अधिक खराब हो सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी की नियमित सफाई, जलकुंभी हटाने और रिवर फ्रंट योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि हेरिटेज का दर्जा तभी सार्थक होगा, जब नदी का संरक्षण और रखरखाव प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

पर्यावरण विशेषज्ञ भी मानते हैं कि जलकुंभी का बढ़ता फैलाव जल गुणवत्ता को प्रभावित करता है और जलीय जीवों के लिए भी खतरा पैदा करता है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि संबंधित विभाग जल्द प्रभावी कदम उठाएगा, ताकि सरस्वती नदी अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप स्वच्छ और संरक्षित स्वरूप में दिखाई दे सके। नियमित निगरानी और समयबद्ध सफाई अभियान से ही इस पौराणिक धरोहर को संरक्षित रखा जा सकता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रभावी सफाई अभियान नहीं चला, तो वे प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे।

बिजली कटौती से हाहाकार, हिसार में सब स्टेशन घेरा, भिवानी में हाईवे जाम

बढ़ती बिजली मांग के बीच अघोषित कटौती से जनजीवन प्रभावित, रोजाना 1300 से 1500 शिकायतें, लोग परेशान

भारतेन्दु संवाददाता, भिवानी

हरियाणा में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। हिसार में उपभोक्ताओं ने बिजली संकट से परेशान होकर सब स्टेशन का घेराव किया, जबकि भिवानी में बिजली और पानी की समस्या से नाराज लोगों ने दिल्ली-पिलानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।

लगातार बिजली बाधित रहने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को भीषण गर्मी के बीच भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भिवानी शहर के हनुमान ढाणी चौक पर रविवार सुबह बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हुए और दिल्ली-पिलानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि क्षेत्र में रोजाना चार से पांच बार आधे से पौने घंटे तक अघोषित बिजली कट लगाए जा रहे हैं। इससे लोगों की रातों की नींद खराब हो रही है। उनका कहना था कि बिजली निगम न तो कटौती की पूर्व सूचना देता है और न ही शिकायतों का समय पर समाधान किया जाता है। कई लोगों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के फोन भी नहीं उठते।

प्रदर्शन के दौरान स्थानीय पार्षद विनोद प्रजापति भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और बिजली निगम के अधिकारियों से कई बार अनुरोध किया जा चुका है कि यदि किसी कारण बिजली आपूर्ति बाधित करनी हो तो पहले से लोगों को सूचना दी जाए। इसके लिए बिजली निगम को उपभोक्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने हेतु व्हाट्सएप समूह या अन्य सूचना प्रणाली शुरू करनी चाहिए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। बिजली कटौती का असर पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। लगातार बिजली बाधित रहने से जलापूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे लोगों को दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

उधर, हिसार में भी बिजली संकट को लेकर लोगों ने संबंधित सब स्टेशन का घेराव कर अपना विरोध दर्ज कराया। उपभोक्ताओं का कहना है कि बार-बार बिजली गुल होने से घरेलू कामकाज, व्यापार और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लोगों ने नियमित और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। बिजली निगम के आंकड़ों के अनुसार, इन दिनों बिजली की मांग में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।

लगभग एक पखवाड़े पहले जहां प्रतिदिन करीब 98 लाख यूनिट बिजली की खपत हो रही थी, वहीं अब यह बढ़कर एक करोड़ यूनिट से अधिक पहुंच गई है। बढ़ी हुई मांग के कारण कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। विभाग को रोजाना लगभग 1300 से 1500 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में बिजली कटौती और फॉल्ट से संबंधित अनेक शिकायतें दर्ज की जा रही हैं।

जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली निगम के एसडीओ मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं बिजली निगम का कहना है कि बढ़ती मांग और तकनीकी फॉल्ट के कारण कुछ स्थानों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन व्यवस्था को सामान्य बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि अघोषित बिजली कटौती और पेयजल संकट का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। वहीं अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि तकनीकी खामियों को दूर कर बिजली व्यवस्था जल्द सामान्य करने के लिए अतिरिक्त टीमें लगातार काम कर रही हैं।

30 साल बाद माउंट एवरेस्ट से मिला आईटीबीपी जवान का शव

1995 एवरेस्ट अभियान में लापता हुए जवान डोरजे मोरुप के अवशेष 30 साल बाद हुए बरामद

एजेंसी, नई दिल्ली

लद्दाख में तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवान डोरजे मोरुप का शव करीब 30 साल बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से बरामद किया गया है। वर्ष 1996 में एवरेस्ट अभियान के दौरान लापता हुए डोरजे मोरुप का शव अब जाकर मिला है। यह घटना पर्वतारोहण इतिहास की एक बेहद भावुक और दुर्लभ घटनाओं में शामिल हो गई है।

जानकारी के अनुसार, डोरजे मोरुप के एक विशेष पर्वतारोहण दल का हिस्सा थे। वर्ष 1996 में एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों के कारण कई पर्वतारोही हादसे का शिकार हुए थे। उसी अभियान के दौरान डोरजे मोरुप भी लापता हो गए थे। कई वर्षों तक उनकी तलाश की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। हाल ही में एवरेस्ट क्षेत्र में एक अभियान के दौरान पर्वतारोहियों की नजर एक शव पर पड़ी। जांच के बाद इसकी पहचान जवान डोरजे मोरुप के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि शव करीब 26 हजार फीट की ऊंचाई पर मिला, जहां बेहद ठंडे मौसम के कारण शरीर काफी हद तक सुरक्षित रहा। अधिकारियों के अनुसार, डोरजे मोरुप का शव भारत लाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उनके परिवार को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। तीन दशक बाद अपने प्रियजन के अवशेष मिलने की खबर से परिवार भावुक है। डोरजे मोरुप एक अनुभवी पर्वतारोही थे और उन्होंने कई कठिन अभियानों में हिस्सा लिया था।

वर्ष 1996 का एवरेस्ट हादसा दुनिया के सबसे चर्चित पर्वतारोहण हादसों में से एक माना जाता है। उस दौरान कई अनुभवी पर्वतारोहियों की जान चली गई थी। ने अपने जवान की बहादुरी और साहस को

याद करते हुए कहा कि डोरजे मोरुप ने देश सेवा और पर्वतारोहण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा।

माउंट एवरेस्ट पर दशकों बाद मिले इस शव ने एक बार फिर उन पर्वतारोहियों की यादें ताजा कर दी हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने जुनून और साहस के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने का प्रयास किया था। यह घटना पर्वतारोहण के जोखिम और वीरता दोनों को दर्शाती है। माउंट एवरेस्ट से जवान डोरजे मोरुप का शव मिलने के बाद तीन दशक पुराने अभियान की यादें फिर ताजा हो गईं। जवान के साहस और बलिदान को देश ने नमन किया। 30 साल बाद मिले जवान डोरजे मोरुप के शव को सम्मान के साथ भारत लाने की तैयारी की जा रही है। उनकी बहादुरी को याद किया जा रहा है।

दिल्ली में देशभक्ति का रंग, 'हर घर तिरंगा-2026' अभियान की तैयारी तेज

एजेंसी ,नई दिल्ली

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली एक बार फिर देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आएगी। लोगों में राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 'हर घर तिरंगा-2026' अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत दिल्लीवासियों को 15 लाख से अधिक राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए जाएंगे, ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों पर तिरंगा फहरा सकें।

सरकार का उद्देश्य है कि इस अभियान के माध्यम से हर नागरिक को स्वतंत्रता दिवस के उत्सव से जोड़ा जाए और देश की आजादी के महत्व को जन-जन तक पहुंचाया जाए। अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगे

दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान, 15 लाख झंडे बांटे जाएंगे

उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियमों और उसके सम्मान से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसे अभियानों से नागरिकों में देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना मजबूत होती है।

पिछले वर्षों में भी 'हर घर तिरंगा' अभियान को लोगों का व्यापक समर्थन मिला था। बड़ी संख्या में दिल्लीवासियों ने अपने घरों, कार्यालयों और संस्थानों पर तिरंगा लगाकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया था। इस बार अभियान को और व्यापक स्तर पर चलाने की योजना बनाई गई है। सरकार की ओर से संबंधित विभागों को तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय संस्थाओं को भी अभियान से जोड़ने की तैयारी है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका संदेश पहुंच

गाजियाबाद से शादी करने बिहार पहुंचा दूल्हा, सात फेरे के बाद दुल्हन फरार

एजेंसी ,नई दिल्ली

गाजियाबाद से शादी करने बिहार पहुंचे एक युवक के साथ गयाजी जिले में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। युवक ने पूरे रीति-रिवाज के साथ शादी की, दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और अग्नि के सामने सात फेरे भी लिए। शादी के बाद युवक अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर काफी खुश था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी खुशियां चिंता में बदल गईं। जानकारी के अनुसार, युवक गाजियाबाद से बिहार के गयाजी जिले में शादी करने आया था। परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी में विवाह की सभी रस्में पूरी की गईं। शादी के दौरान सब कुछ सामान्य रहा और दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। लेकिन शादी के बाद अचानक दुल्हन के फरार होने से हड़कंप मच गया।

युवक और उसके परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन दुल्हन का कोई पता नहीं चल सका। घटना के बाद युवक ने मामले की जानकारी स्थानीय लोगों और संबंधित अधिकारियों को दी। परिवार इस घटना से काफी परेशान है और पूरे मामले की जांच की मांग कर रहा है। स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि, दुल्हन के अचानक चले जाने के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

10 दिन से परेशान निवासी सड़क पर उतरे बिजली-पानी समस्या के खिलाफ प्रदर्शन

एजेंसी ,नई दिल्ली

ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-86 स्थित एडोर हैप्पी होम सोसायटी के निवासियों ने बिजली कटौती और पेयजल संकट को लेकर रविवार को बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पिछले करीब दस दिनों से बिजली की समस्या और पानी की कमी झेल रहे लोगों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। बड़ी संख्या में सोसायटी के निवासी एकत्रित हुए और बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द समाधान की मांग की।

प्रदर्शन कर रहे निवासियों का कहना है कि लंबे समय से उन्हें मूलभूत सुविधाओं की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पेयजल की कमी ने समस्या को और बढ़ा दिया है। गर्मी के मौसम में बिजली और पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं के अभाव से बुजुर्गों, बच्चों और अन्य लोगों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। निवासियों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। लोगों ने बिल्डर प्रबंधन से जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था सुधारने और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की है।

हरियाली और सुंदरता पर जोर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शुरू की बड़ी पहल

एजेंसी ,नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर की खूबसूरती और हरियाली को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर परी चौक से जीरो प्वाइंट तक हरित क्षेत्र का रखरखाव प्राधिकरण खुद करेगा। इस कार्य पर करीब 1.65 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए एक साल के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और निविदा जारी कर दी गई है।

आगामी सितंबर माह में इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होना है। इस आयोजन में देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने शहर की बेहतर छवि प्रस्तुत करने के लिए एक्सप्रेसवे और आसपास के क्षेत्रों के सुंदरीकरण की योजना तैयार की है। योजना

के तहत परी चौक से जीरो प्वाइंट तक हरित क्षेत्र, सेंट्रल वर्ज और आसपास स्थित दो पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। क्षेत्र में पौधों की देखभाल, घास की कटाई, सफाई और हरियाली को बनाए रखने से जुड़े कार्य किए जाएंगे। प्राधिकरण का उद्देश्य है कि एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले लोगों को स्वच्छ और आकर्षक वातावरण दिखाई दे। अधिकारियों के अनुसार, ट्रेड शो जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन शहर की पहचान को मजबूत करते हैं। इसलिए प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थानों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्राधिकरण का प्रयास है कि विकास कार्यों के साथ-साथ शहर की सुंदरता और पर्यावरण को भी बढ़ावा दिया जाए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे की हरियाली बढ़ाने और शहर को आकर्षक बनाने की योजना बनाई है। ट्रेड शो से पहले सुंदरीकरण कार्य तेजी से पूरा करने की तैयारी है।

एनसीआर में निवेश का नया केंद्र बनेगा जेवर-आगरा कॉरिडोर

एजेंसी, नई दिल्ली

एनसीआर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की योजना तैयार की जा रही है। यह कॉरिडोर जेवर से आगरा की दिशा में विकसित किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित होने की संभावना बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देना और निवेश को आकर्षित करना है। जेवर क्षेत्र में बन रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखते हुए इस कॉरिडोर को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, कॉरिडोर के विकास से मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और अन्य क्षेत्रों की कंपनियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

न्यूज ब्रीफ

नोएडा में नए मेट्रो रूटों का रास्ता साफ निर्माण के लिए 13 एजेंसियां आगे आईं

एजेंसी ,नई दिल्ली नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। शहर में नए मेट्रो रूटों के निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है। नोएडा में मेट्रो विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए निर्माण कार्य के लिए 13 एजेंसियां आगे आई हैं। इससे आने वाले समय में लोगों को बेहतर और आसान सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मेट्रो के नए रूटों के निर्माण के लिए एजेंसियों ने अपनी रुचि दिखाई है। अब संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभाग इस परियोजना को जल्द आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। नए मेट्रो रूट शुरू होने से शहर के विभिन्न इलाकों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी और सड़क यातायात का दबाव भी कम होने की संभावना है। मेट्रो सेवा के विस्तार से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन और अधिक सुविधाजनक हो सकेगा।

फरीदाबाद में कटे पेड़ों की होगी भरपाई, 90 हेक्टेयर जमीन पर लगेंगे पौधे

एजेंसी, नई दिल्ली फरीदाबाद में पिछले दस वर्षों के दौरान विकास परियोजनाओं के लिए काटे गए पेड़ों की भरपाई करने की तैयारी शुरू हो गई है। अरावली वन क्षेत्र में हुई पेड़ों की कटाई के बाद अब हरियाली बढ़ाने के लिए 90 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग एजेंसियों ने डायवर्जन के तहत जमीन उपलब्ध कराई है। वन विभाग ने पौधारोपण अभियान से जुड़ा पूरा प्रस्ताव राज्य और केंद्र सरकार को भेज दिया है। अधिकारियों के अनुसार, मंजूरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अनुमति मिलते ही क्षेत्र में बड़े स्तर पर पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि शहर में कई बड़ी विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अरावली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की गई थी। हालांकि, पिछले एक दशक में कितने पेड़ काटे गए, इसका सटीक आंकड़ा वन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन पेड़ों की कटाई से पर्यावरण संतुलन प्रभावित हुआ है और शहर में हरित क्षेत्र भी कम हुआ है। पौधारोपण अभियान का उद्देश्य पर्यावरण को बेहतर बनाना, हरियाली बढ़ाना और अरावली क्षेत्र के प्राकृतिक संतुलन को मजबूत करना है।

गाजियाबाद के मत्स्य पालकों के लिए विभाग ने जारी किए आवेदन

एजेंसी ,नई दिल्ली

गाजियाबाद में मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने मत्स्य पालकों और पात्र लाभार्थियों से 31 जुलाई तक विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार, सरकार का उद्देश्य मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना और आधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इच्छुक लाभार्थियों को प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।

सहायक निदेशक मत्स्य ऋचा चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार मत्स्य पालकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को अनुदान और आवश्यक

सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम स्थापना योजना, उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के अंतर्गत मोबाइल विद आइस बॉक्स परियोजना, माता सुभद्रा महिला मत्स्य पालक सशक्तिकरण परियोजना, अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में नए तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश योजना, उत्तर प्रदेश मोती संवर्धन योजना तथा वरिष्ठ प्रजाति की मत्स्य हैचरी स्थापना योजना शामिल हैं। विभाग ने बताया कि प्रत्येक योजना के लिए पात्रता, अनुदान, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक विस्तृत जानकारी विभागीय पोर्टल या विकास भवन स्थित सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

पक्षियों के संरक्षण को प्राथमिकता गुरुग्राम मेट्रो डिपो स्थानांतरण की तैयारी

एजेंसी ,नई दिल्ली

गुरुग्राम में विदेशी प्रवासी पक्षियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित मेट्रो डिपो के स्थान में बदलाव की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में संबंधित विभागों द्वारा विस्तृत सर्वे कराया जा रहा है ताकि पर्यावरण और पक्षियों के प्राकृतिक आवास पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे का उद्देश्य केवल पक्षियों की संख्या का आकलन करना नहीं, बल्कि बदलते मौसम के साथ इस पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना भी है।

विशेषज्ञों की टीम क्षेत्र में आने वाले विदेशी प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों, उनके ठहरने के स्थान, भोजन की उपलब्धता और उनके आवागमन के पैटर्न का अध्ययन

गुरुग्राम में पक्षियों के लिए बदलेगा मेट्रो डिपो स्थान

कर रही है। इसके साथ ही जलाशयों, हरित क्षेत्रों और स्थानीय वनस्पतियों की स्थिति का भी आकलन किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि मेट्रो डिपो के लिए कौन-सा स्थान पर्यावरण की दृष्टि से अधिक उपयुक्त रहेगा। अधिकारियों का मानना है कि विकास परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि किसी निर्माण कार्य से पक्षियों के प्राकृतिक आवास या पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका होगी, तो परियोजना में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।

ग्रेटर नोएडा के स्पा सेंटरों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 28 युवतियां रेस्क्यू

एजेंसी, नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक बड़े अभियान के तहत कई स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ स्पा सेंटरों की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और पर्याप्त जानकारी जुटाने के बाद विशेष टीमों का गठन कर अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दबिश दी।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुल 28 लड़कियों को रेस्क्यू किया। अधिकारियों के अनुसार, सभी लड़कियों की पहचान और परिस्थितियों की जांच की जा रही है। जरूरत पड़ने पर उन्हें आवश्यक सहायता और परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, मौके से 15 लड़कों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस उनसे यह जानने का प्रयास कर रही

है कि वे वहां किस उद्देश्य से पहुंचे थे और क्या उनका किसी अवैध गतिविधि से कोई संबंध है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्पा सेंटरों के दस्तावेज, लाइसेंस और संचालन से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।

यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या अवैध गतिविधियों की पुष्टि होती है, तो संबंधित संचालकों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली के जहांगीरपुरी में खूनी हमला, 20 वर्षीय युवक की हत्या

सैलून से बुलाकर युवक पर जानलेवा हमला, चाकू गोदकर उतारा मौत के घाट

एजेंसी, नईदिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी जिला अंतर्गत जहांगीरपुरी इलाके में एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां शनिवार रात को एक 20 वर्षीय युवक, जिसकी पहचान इरफान के रूप में हुई है, को चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक इरफान जहांगीरपुरी इलाके के ही एक सैलून में मौजूद था, जहां वह काम करता था या काम सीख रहा था। वारदात के वक्त अचानक दो अज्ञात युवक सैलून के पास पहुंचे।

उन्होंने किसी बहाने से इरफान को सैलून से बाहर बुलाया। जैसे ही इरफान बाहर गली में आया, उन बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करना शुरू कर दिया। इस जानलेवा हमले में इरफान बुरी तरह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया, जिसके बाद हमलावर मौके से तुरंत फरार हो

दिल्ली में युवक इरफान की चाकू मारकर हत्या

गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल इरफान को तुरंत नजदीकी बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि, अस्पताल लाते ही डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की सघन जांच शुरू कर दी है।

वारदात की असल वजह का पता लगाने के लिए पुलिस घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि, शुरुआती जांच में हत्या का स्पष्ट मकसद या पुरानी रंजिश का कोई कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस अचानक हुई वारदात से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

नशामुक्त हरियाणा अभियान को मिली रफ्तार,सीएम ने पुलिस को दिए सख्त निर्देश

एजेंसी ,नई दिल्ली

हरियाणा में नशामुक्त समाज के लक्ष्य को लेकर पुलिस विभाग ने 'नशामुक्त हरियाणा' अभियान के तहत थाना प्रभारियों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नशा तस्करों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज को नशे की समस्या से मुक्त कराने के लिए पुलिस, प्रशासन और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। साथ ही, युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इस अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उन्होंने थाना प्रभारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की भी सलाह दी गई।

उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग नशे की लत का शिकार हो चुके हैं, उन्हें अपराधी नहीं बल्कि उपचार और पुनर्वास की आवश्यकता वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे लोगों को नशा मुक्ति केंद्रों से जोड़कर उनकी काउंसलिंग और इलाज की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव भी साझा किए। सरकार ने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और समाज के सहयोग से हरियाणा को नशामुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

न्यूज ब्रीफ

जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ ने तवी नदी में फंसे तीन लोगों को बचाया

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। एक तेज़ और बेहतर तालमेल वाले बचाव अभियान में जम्मू पुलिस और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स ने पीर खो मंदिर के पास तवी नदी में पानी का स्तर अचानक बढ़ने के कारण फँसे तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिलने पर कि नदी में नहाने गए तीन लोग पानी का स्तर अचानक बढ़ने के कारण फँस गए हैं। सूचना मिलते ही एसडीपीओ सिटी नॉर्थ, एसएचओ पुलिस स्टेशन पक्का डंगा, पुलिस पोस्ट प्रभारी चौक चबूतरा और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुँची। एक अच्छी तरह से समन्वित बचाव अभियान के ज़रिए तीनों लोगों को बिना किसी चोट के सुरक्षित बचा लिया गया। तीनों की पहचान रणदीप सिंह पुत्र चमेल सिंह निवासी झुल्लाका मोहल्ला, मुनीष शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी अफ़ग़ाना मोहल्ल, विकास कुमार पुत्र कुंदन प्रसाद वर्मा निवासी बिहार (वर्तमान निवासी बस स्टैंड जम्मू के रूप में हुई है।

धरती को बेहतर बनाकर अगली पीढ़ी को सौंपना हमारी जिम्मेदारीः मनोज सिन्हा

भारतेंदु संवाददाता, बारामुला। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामुला में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में प्रकृति संरक्षण को हर नागरिक का आध्यात्मिक और नैतिक दायित्व बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह धरती को सुरक्षित और बेहतर बनाकर आने वाली पीढ़ियों को सौंपे। उपराज्यपाल ने भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। नदियों, वृक्षों और धरती के प्रति सम्मान हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की। मनोज सिन्हा ने कहा कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा सभी धर्मों, विचारों और आस्थाओं का सम्मान करते हुए शांति, सद्भाव और सहअस्तित्व का संदेश देती है।

बीजेपी ने 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन को टालने का किया फैसला : सुनील शर्मा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। विधानसभा में विपक्ष के नेता व प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा ने रविवार को कहा कि राजनीति बाद में हो सकती है और इंसानियत सबसे पहले आनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में 20 जुलाई को होने वाले अपने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को टालने का फ़ैसला किया है क्योंकि पुंछ और राजौरी ज़िलों में अचानक आई बाढ़ से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि पार्टी ने कल होने वाले विरोध प्रदर्शन को टालने का फ़ैसला किया है। यह प्रदर्शन घंटा घर, लाल चौक से शुरू होकर सिविल सचिवालय पर खत्म होना था लेकिन मौजूदा हालात में राजनीतिक गतिविधियों के बजाय मानवीय मदद की ज़रूरत है।

वैष्णो देवी भवन के पास अश्लील हरकत का मामला, दो आरोपी हिरासत में

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास अश्लील हरकत करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। कार्रवाई वायरल वीडियो के आधार पर की गई। पुलिस के अनुसार भवन बाजार क्षेत्र में अनुचित गतिविधियों से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुईं। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

गुरेज में खेलों से बदलाव की पहल इंटर विलेज फेस्टिवल शुरू

क्रिकेट से हॉकी तक खेलों का उत्सव, गुरेज में दिखेगी प्रतिभाओं की चमक

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर की सीमावर्ती गुरेज घाटी में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल 1.0 का शुभारंभ हुआ है। यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा देने, सामाजिक एकता को मजबूत करने और क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़कर उनकी प्रतिभा को सामने लाना और उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता तथा टीम भावना का विकास करना है। फेस्टिवल की शुरुआत भव्य मार्च पास्ट के साथ हुई, जिसमें गुरेज घाटी के विभिन्न गांवों से आए प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मार्च पास्ट ने एकता, अनुशासन और सामूहिक भावना का संदेश दिया। आयोजकों के अनुसार खेल युवाओं के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं और ऐसे आयोजनों से उनमें जिम्मेदारी, सहयोग और सम्मान जैसे मूल्यों का विकास होता है। इस खेल महोत्सव में महिलाओं की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है। आयोजन के माध्यम से महिलाओं को खेल और सामुदायिक गतिविधियों में आगे आने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

गुरेज घाटी में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज

फेस्टिवल में खेल प्रतियोगिताओं के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। इसके तहत स्वच्छ गांव प्रतियोगिता और वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य स्थानीय लोगों में अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और गांवों को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखना है। इस आयोजन को सफल बनाने में भारतीय सेना और स्थानीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। सेना की ओर से आयोजन के लिए आवश्यक सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

बादल फटने के बाद चिनैनी में बड़ा हादसा, 25 फीट नीचे धंसी पूरी मार्केट

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के चिनैनी क्षेत्र में रविवार को प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। नगालदा इलाके में तेज बारिश के साथ बादल फटने की घटना के बाद पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि जम्मू-श्रीनगर हाईवे के पास प्रेम मंदिर के निकट स्थित मार्केट की जमीन धीरे-धीरे धंसने लगी। देखते ही देखते वहां मौजूद आठ दुकानें करीब 20 से 25 फीट नीचे चली गईं और पूरी तरह तबाह हो गईं। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

स्थानीय लोगों के अनुसार बादल फटने के बाद पहाड़ी क्षेत्र से पानी का तेज बहाव नाले के रास्ते नीचे की ओर आया, जिससे मार्केट को भारी नुकसान पहुंचा। दुकानदारों ने बताया कि अचानक दुकानों में कंपन महसूस होने लगी और जमीन बैठने लगी। खतरे को भांपते हुए दुकानदार और वहां मौजूद लोग तुरंत बाहर निकल आए, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि दुकानों में रखा सामान और व्यापारिक सामग्री पूरी तरह बर्बाद हो गई।

◆ 25 फ़ीट नीचे चली गईं दुकानें, सामान हुआ बर्बाद

कटड़ा में मानसून आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम शुरू

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में मानसून के दौरान भारी बारिश, अचानक बाढ़, भूस्खलन, जलभराव और सड़क अवरोध जैसी संभावित आपदाओं को देखते हुए कटड़ा प्रशासन ने मानसून आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम स्थापित किया है। उपमंडल मजिस्ट्रेट कटड़ा पीयूष धोतरा के आदेश पर शुरू किए गए इस कंट्रोल रूम की निगरानी तहसीलदार कटड़ा जितेंद्र सिंह करेंगे। कंट्रोल रूम के माध्यम से आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई और राहत कार्यों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, जल शक्ति विभाग, नगर निकाय और अन्य संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य बारिश के दौरान किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटना और लोगों व श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

बालटाल और पहलगाम मार्ग से अमरनाथ यात्रा अगले आदेश तक अस्थायी रूप से स्थगित

सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश भूस्खलन और अचानक बाढ़ की आशंका जताए जाने के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 19 जुलाई 2026 से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बालटाल और नुनवान चंदनवाड़ी दोनों बेस कैंपों से किसी भी यात्री को पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर

◆ **मौसम सामान्य होने पर लिया जाएगा अगला फैसला**

आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि खराब मौसम के कारण पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन और तेज जलधाराओं का खतरा बढ़ गया है जिससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है। इसलिए यह निर्णय पूरी तरह एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। अधिकारियों ने

सुरक्षा समीक्षा के बाद ही दोबारा शुरू होगी यात्रा

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यात्रा को स्थायी रूप से बंद नहीं किया गया है बल्कि मौसम सामान्य होने और पूरे यात्रा मार्ग की विस्तृत सुरक्षा समीक्षा के बाद ही इसे दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन लगातार मौसम विभाग और सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है तथा यात्रा मार्ग की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन तथा श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का ही पालन करें। साथ ही बेस कैंपों में ठहरे यात्रियों के लिए भोजन स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

स्पष्ट किया है कि यात्रा को स्थायी रूप से बंद नहीं किया गया है बल्कि मौसम सामान्य होने और पूरे यात्रा मार्ग की विस्तृत सुरक्षा समीक्षा के बाद ही इसे दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा।

सोनम वांगचुक के इलाज को लेकर पत्नी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

अनशन के बीच वांगचुक की पत्नी ने हाईकोर्ट से लगाई मदद की गुहार

भारतेंदु संवाददाता, लेह। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण संरक्षण अभियान से जुड़े सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर कानूनी और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। वांगचुक की पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए उनके बेहतर उपचार की मांग की है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर सोनम वांगचुक को वर्तमान अस्पताल से किसी अन्य उपयुक्त चिकित्सा संस्थान में स्थानांतरित करने की अपील की है।

याचिका में कहा गया है कि लंबे समय से जारी अनशन के कारण सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार निगरानी रखने की जरूरत है। उनकी पत्नी का कहना है कि उन्हें ऐसी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में बेहतर उपचार और जांच की व्यवस्था हो सके। उन्होंने अदालत से मामले में हस्तक्षेप कर उचित निर्देश जारी करने की मांग की है।

वहीं सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए 20 जुलाई को प्रस्तावित कार्यक्रम को लोकतांत्रिक अधिकारों और जनभागीदारी से जुड़ा बताया है। उन्होंने इसे आजादी का दूसरा आंदोलन बताते हुए लोगों से जुड़ने की अपील की है। प्रशासन और चिकित्सा विशेषज्ञ भी वांगचुक के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

बांदीपोरा में आतंक समर्थकों पर बड़ी कार्रवाई पांच लोगों की करोड़ों की संपत्ति जब्त

जेएंडके में आतंक नेटवर्क पर प्रहार पांच सहयोगियों की संपत्तियां सील

भारतेंदु संवाददाता, बांदीपोरा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए सुरक्षाबलों और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बांदीपोरा पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग करने वाले पांच लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई जिले के चिट्टीबांडे और गुंडपोरा गांवों में की गई। कुर्क की गई संपत्तियों में कृषि भूमि और अन्य भूखंड शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों की संपत्तियां जब्त की गई हैं उनकी पहचान मीर हसन खुर्शीद अहमद शेख फारूक अहमद वानी मुजफ्फर अहमद लोन और गुलाम अहमद लोन के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि इन लोगों की संपत्तियां कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों में शामिल थीं। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए इन संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की गई।

बांदीपोरा पुलिस ने कहा कि आतंकवाद और उसके समर्थन तंत्र को पूरी तरह खत्म करने के लिए यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस का उद्देश्य उन लोगों पर शिकंजा कसना है जो किसी भी रूप में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुंचाते हैं या उनके नेटवर्क को मजबूत करने का काम करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सोच बेहतर लेकिन अमल की रफ्तार धीमी : सुकृति सूरी

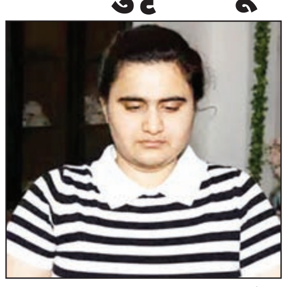

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए दृष्टिबाधित छात्रा सुकृति सूरी ने कहा कि नीति के उद्देश्य और सोच सकारात्मक हैं, लेकिन इसका वास्तविक लाभ तभी मिल पाएगा जब इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर देने के लिए केवल नीति बनाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसके क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सुकृति सूरी ने दिव्यांग छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके लिए सुलभ शिक्षण सामग्री, आधुनिक सहायक तकनीक, प्रशिक्षित शिक्षक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को भी अधिक निष्पक्ष और सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता बताई ताकि दिव्यांग छात्र अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर सकें।

उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों में मजबूत शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए जिससे छात्रों की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। सुकृति ने जोर दिया कि समावेशी शिक्षा का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब नीतियों को स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक सही तरीके से पहुंचाया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समानता और गुणवत्ता वाली शिक्षा पर जोर दिया गया है, लेकिन इसके लिए संसाधनों की उपलब्धता और प्रभावी निगरानी जरूरी है। सुकृति सूरी का कहना है कि नीति को सफल बनाने के लिए सरकार, शिक्षकों और संस्थानों को मिलकर काम करना होगा ताकि हर छात्र को बेहतर शिक्षा का अधिकार मिल सके।

राजोरी में फ्लैश फ्लड से बस स्टैंड जलमग्न, चार लोगों की मौत

भारतेंदु संवाददाता, राजोरी। जम्मू-कश्मीर के राजोरी और पुंछ जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राजोरी जिले में अचानक आई बाढ़ के कारण धरहल नदी उफान पर आ गई, जिससे न्यू बस स्टैंड बेला सहित कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। बाढ़ का पानी बस स्टैंड की पार्किंग में घुस गया और वहां खड़े अनेक वाहन बह गए या पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों के अनुसार तड़के करीब तीन बजे आई इस भीषण बाढ़ ने कुछ ही मिनटों में पूरे क्षेत्र का स्वरूप बदल दिया।

कई बाजारों, सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में पानी भर जाने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। वहीं पुंछ जिले में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के लापता होने की भी सूचना है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और अनेक लोगों का सामान तथा वाहन तेज बहाव में बह गए। अनुमान है कि करीब 200 से 250 वाहन लापता हो गए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं तथा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस, आपदा प्रबंधन और अन्य एजेंसियों की टीमें तैनात की गई हैं।

सांबा में सेना को मिला संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, सीमा पर बढ़ी सतर्कता

भारतेंदु संवाददाता, सांबा। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले सांबा में सेना को एक संदिग्ध ड्रोन मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। यह घटना जिले में एक सप्ताह के भीतर ड्रोन मिलने का दूसरा मामला है। अधिकारियों के अनुसार सीमा पार से होने वाली तस्करी और घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक टेरिटोरियल आर्मी के जवानों ने शनिवार देर रात सांबा जिले के पुरमंडल क्षेत्र के संगर खेतों से एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया। जवानों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाकर ड्रोन को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद ड्रोन को तकनीकी और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि ड्रोन कहां से आया था और इसका इस्तेमाल किसी सीमा पार गतिविधि के लिए किया गया था या नहीं।

अधिकारियों ने बताया कि फोरेंसिक जांच के दौरान ड्रोन की तकनीकी क्षमता उसकी उड़ान सीमा और उससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जाएंगी। इसके अलावा यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या इसके जरिए किसी तरह की सामग्री या हथियारों की तस्करी की कोशिश की गई थी।

जम्मू-कश्मीर के स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां 22 जुलाई तक बढ़ीं

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के सर्दियों वाले इलाकों के सभी सरकारी तथा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां तीन दिन और बढ़ाने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब इन क्षेत्रों के स्कूल 22 जुलाई तक बंद रहेंगे। सरकार ने यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है।

◆ **कश्मीर और जम्मू के सर्दी वाले इलाकों में स्कूल रहेंगे बंद**

इससे पहले भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण कश्मीर संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 6 जुलाई से 19 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन मौसम की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए छुट्टियों की अवधि को आगे बढ़ाया गया है।

अधिकारियों के अनुसार लगातार बदलते मौसम और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। सरकार ने सभी स्कूल प्रबंधन से निर्देशों का पालन करने को कहा है। अभिभावकों ने भी बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इस निर्णय का स्वागत किया है। मौसम में सुधार होने के बाद ही स्कूलों के नियमित संचालन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की मांग को लेकर उमर अब्दुल्ला ने संभाला मोर्चा

जेएंडके के राज्य दर्जे की मांग को लेकर उमर अब्दुल्ला दिल्ली रवाना

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए श्रीनगर से दिल्ली रवाना हो गए हैं। उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य के दर्जे की तत्काल बहाली की मांग को लेकर इस प्रदर्शन का आयोजन किया है। पार्टी की ओर से कई राजनीतिक दलों के नेताओं को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। कांग्रेस के भी इस आंदोलन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

यह प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब दिल्ली में सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। वांगचुक के समर्थन में आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया है। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस घटनाक्रम के बाद जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा और तेज हो गई है।

उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अनुमति मिले या नहीं वह जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रशासनिक अधिकारों को लेकर कई सवाल उठे हैं और जनता की भावनाओं को देखते हुए राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए।

वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आंदोलन में शामिल होने को लेकर कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि यदि प्रदर्शन में अनुच्छेद 370 की बहाली और अन्य राजनीतिक मुद्दों को भी शामिल किया जाता है तभी उनकी पार्टी इसमें भाग लेने पर विचार करेगी।

जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे की मांग लंबे समय से राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है। अब दिल्ली में होने वाले इस प्रदर्शन से इस विषय पर केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ने की संभावना है।

रामबन में दर्दनाक हादसा खाई में गिरी कार, एक की मौत, चार घायल

भारतेंदु संवाददाता, रामबन। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। खारी बनिहाल इलाके में आरामडाका के पास पहाड़ी मांगित रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। अधिकारियों के अनुसार यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक ऑल्टो कार मांगित से बनिहाल की ओर जा रही थी। आरामडाका के पास पहाड़ी रास्ते पर मोड़ काटते समय चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और कार सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और बचाव दल मौके पर पहुंचे और कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला। सभी घायलों को तुरंत उप जिला अस्पताल बनिहाल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने 50 वर्षीय गुलाम मोहम्मद लोन पुत्र अली मोहम्मद लोन को मृत घोषित कर दिया। वहीं चार अन्य घायलों का उपचार जारी है। घायलों की पहचान मोहम्मद इशाक पुत्र अब्दुल रहमान खांडे, मोहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल रशीद, नवाज अहमद पुत्र अब्दुल अहद और जबा बेगम पत्नी अब्दुल अहद के रूप में हुई है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि पहाड़ी मार्ग पर मोड़ के दौरान वाहन अनियंत्रित होने से यह दुर्घटना हुई। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए प्रशासन वाहन चालकों से सावधानी बरतने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील करता रहा है।

राजौरी के बाद पुंछ में गोलीबारी कर घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सेना ने दिया जवाब

भारतेंदु संवाददाता, पुंछ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। बालाकोट सेक्टर में शनिवार को पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब एक घंटे तक दोनों ओर से रुक-रुक कर फायरिंग होती रही जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। सूत्रों के अनुसार शनिवार सुबह करीब 11 बजे पाकिस्तान की चौकियों से भारतीय ठिकानों पर गोलीबारी शुरू की गई। इसमें यूनिवर्सल मशीन गन सहित अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की और सीमा पार से हो रही फायरिंग को रोकने में सफलता हासिल की। इससे पहले शुक्रवार रात नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों ने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी थीं। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि आतंकियों ने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने का प्रयास किया। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी ताकि उसकी आड़ में घुसपैठ कराई जा सके। हालांकि भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर तैनात जवानों ने छोटे हथियारों से जवाबी कार्रवाई की। दोनों पक्षों के बीच करीब डेढ़ घंटे तक रुक-रुक कर गोलीबारी हुई। भारत की प्रभावी कार्रवाई के बाद सीमा पार से फायरिंग बंद हो गई।

न्यूज ब्रीफ

पठानकोट में सड़क हादसा, युवक की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल परमानंद के सामने हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक दिनेश कुमार की मौत हो गई। वह तारागढ़ के गांव दनौर का निवासी था व बढ़ई का काम करता था। पुलिस के अनुसार, दिनेश अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से निजी काम के लिए दीनानगर जा रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उसकी बाइक को साइड से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसके सिर और माथे पर गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दिनेश को तुरंत पठानकोट के अमनदीप अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। मृतक के पिता पुरुषोत्तम लाल ने पुलिस को बताया कि चश्मदीदों के अनुसार, वाहन चालक तेज रफ्तार व लापरवाही से गाड़ी चला रहा था तथा बिना हॉर्न दिए बाइक को टक्कर मार दी। तारागढ़ पुलिस ने पिता के बयान पर अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि वाहन और आरोपी चालक की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जा सके।

शिमला में खाई में गिरी कार, दो की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला जिले के चौपाल उपमंडल में रविवार को एक सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई। नेरवा तहसील के ग्राम पंचायत पुजारली के दोछी के पास किरी-नाव सड़क पर एक अल्टो कार (एचपी08ए-8441) अनियंत्रित होकर करीब 100 से 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार में सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान नरेश कुमार (35) पुत्र अनंत राम, निवासी गांव दोछी, तहसील नेरवा और जितेंद्र पुत्र धाजू राम, निवासी चाडचधार (धबास क्षेत्र) के रूप में हुई है। नरेश कुमार लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में मल्टीटास्क कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थे। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में शोक की लहर फैल गई। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद नेरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को गहरी खाई से बाहर निकाला गया। इसके बाद शवों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार कार सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिरी। दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

भाईचारे का संदेश देते हैं संत रविदास के विचार: चंदेल

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। हिमुडा निदेशक मंडल सदस्य जितेंद्र चंदेल ने तल्याणा पंचायत के डोला गांव में आयोजित परम पूज्य संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के पावन सत्संग में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सत्संग का श्रवण कर आध्यात्मिक शांति और प्रेरणा प्राप्त करने की बात कही। सत्संग स्थल पर हरी राम सहित स्थानीय श्रद्धालुओं के सहयोग से संत रविदास जी के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बताया गया कि यह मंदिर भविष्य में श्रद्धालुओं के लिए आस्था, सामाजिक एकता और सद्भाव का प्रमुख केंद्र बनेगा। जितेंद्र चंदेल ने मंदिर निर्माण कार्य के लिए हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक लोगों को इस पुण्य कार्य से जोड़ें और संत रविदास जी की शिक्षाओं–मानवता, समानता, प्रेम और भाईचारे–को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी के विचार समाज को सत्य, सेवा और समानता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जो वर्तमान समय में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं।

पीड़ित परिवार को दी 10 हजार की आर्थिक मदद

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर के गांव सुन्हाणी में गत माह खड्ड में डूबने से एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार की सहायता के लिए मण्जुषा सहायता केंद्र, कलोल आगे आया है। इस सराहनीय कार्य में क्षेत्र के समाजसेवी हंसराज वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने मृतक के वृद्ध माता-पिता को सहायता केंद्र तक पहुंचाया। मृतक की पहचान गांव समोह निवासी राजेश, पुत्र लेख राम के रूप में हुई है। उल्लेखनीय है कि लेख राम पिछले लगभग 30 वर्षों से दृष्टिबाधित हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। ऐसे में अंतिम संस्कार एवं अन्य आवश्यक रस्मों के खर्च को देखते हुए मण्जुषा सहायता केंद्र, कलोल ने मानवीय पहल करते हुए लेख राम को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता चेक के माध्यम से प्रदान की। इस अवसर पर केंद्र के अध्यक्ष कर्नल जसवंत सिंह चंदेल ने कहा कि संस्था हमेशा जरूरतमंद और पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध रही है तथा भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य निरंतर जारी रहेंगे। स्थानीय लोगों ने इस मानवीय पहल के लिए मण्जुषा सहायता केंद्र और समाजसेवी हंसराज वर्मा का आभार व्यक्त किया।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की दी जानकारी

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राज्य सहकारी बैंक शाखा धार टटोह द्वारा नाबार्ड के माध्यम से धार टटोह गांव में वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक राजीव शर्मा ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को योजनाओं के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाते हुए अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बैंक की अन्य योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा कीं। शिविर में पंचायत प्रधान अभिषेक ठाकुर, पूर्व प्रधान सुंदर राम, उपप्रधान इंद्र ठाकुर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शाखा प्रबंधक राजीव शर्मा ने बताया कि इससे पहले द्रोबड़ पंचायत में भी वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को राज्य सहकारी बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई थी। दोनों शिविरों में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बैंक की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टैट की अनिवार्यता का विरोध, 5 सितंबर को जंतर-मंतर पर होगा राष्ट्रीय महाधरना

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, दिल्ली/शिमला/मंडी। देशभर के शिक्षा का अधिकार आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए नई दिल्ली के सिविल लाइंस में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश सहित देश के लगभग 20 शिक्षक संगठनों तथा 10 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टैट की अनिवार्यता थोपे जाने का पुरजोर विरोध किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विशाल राष्ट्रीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस आंदोलन में देशभर के हजारों शिक्षक भाग लेकर केंद्र सरकार एवं संबंधित संस्थाओं से इस अनिवार्यता से पूर्णतः मुक्त करने की मांग करेंगे। प्रतिनिधियों ने कहा कि आरटीई अधिनियम, 2009 से पूर्व हुई सभी नियुक्तियां उस समय के प्रचलित नियमों एवं निर्धारित पात्रता के आधार पर हुई थीं। ऐसे शिक्षकों पर वर्षों बाद टैट की शर्त लागू करना न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, बल्कि उनके सेवा अधिकारों और सम्मान पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बैठक में आगामी आंदोलन के संचालन, विभिन्न राज्यों के समन्वय तथा राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय कोर कमेटी का गठन किया गया। इस समिति में हिमाचल प्रदेश से हितेंद्र साहसी, मध्य प्रदेश से जगदीश यादव, पश्चिम बंगाल से भास्कर घोष, दिल्ली से मंजीत राणा, हरियाणा से बिपुल तथा पंजाब से विक्रम देव को शामिल किया गया। बैठक में सभी संगठनों ने एक स्वर में कहा कि यह संघर्ष किसी एक राज्य का नहीं, बल्कि देशभर के लाखों आरटीई पूर्व नियुक्त शिक्षकों के अधिकार, सम्मान और सेवा सुरक्षा का संघर्ष है। सभी शिक्षक संगठनों ने देश के शिक्षकों से आह्वान किया कि वे 5 सितंबर को जंतर-मंतर, नई दिल्ली पहुंचकर इस राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाएं और अपनी लोकतांत्रिक आवाज को मजबूती दें।

हिमाचल के 36 विशिष्ट उत्पादों को मिलेगी नई पहचान, ओडीटीपी योजना से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

औद्योगिक नीति में उत्पाद आधारित उद्यमों को मिलेंगे विशेष प्रोत्साहन : सीएम सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 'वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट' (ओडीटीपी) कार्यक्रम के तहत कार्य तेज कर दिया है।

इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाना, उनकी ब्रांडिंग को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के नए अवसर सृजित करना है। ओडीटीपी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों से तीन–तीन विशिष्ट उत्पादों का चयन किया गया है। आर्थिक संभावनाओं, बाजार में मांग और स्थानीय महत्व के आधार पर कुल 36 उत्पादों को चिन्हित किया गया है। इनमें बिलासपुर से अदरक, रेशम उत्पादन (सेरीकल्चर) और मत्स्य पालन, चंबा से चंबा चप्पल, सफेद मक्की और ऊन, हमीरपुर से हल्दी, बांस और मक्की तथा कांगड़ा से कांगड़ा चाय, कांगड़ा लघु चित्रकला और

गिलोय शामिल हैं। इसी प्रकार किन्नौर से हिमाचली चुल्ली तेल, किन्नौरी शॉल और चिलगोजा, कुल्लू से ट्राउट मछली, हेम्प ऑयल और कुल्लू टोपी, लाहौल–स्पीति से सी–बकथॉर्न, पुल्ले और हरी मटर को चयनित किया गया है। मंडी से सेपू बड़ी, धातु शिल्प तथा पत्थर एवं लकड़ी की नक्काशी, शिमला से सेब आधारित उत्पाद, स्थानीय शहद, जौ का माल्ट एवं आटा और गुच्छी मशरूम को शामिल किया गया है।

सिरमौर से लहसुन, अदरक और सिरमौरी लोइया, सोलन से मशरूम, टमाटर और फार्मास्यूटिकल उत्पाद तथा ऊना से आलू, लीची और ड्रैगन फ्रूट को ओडीटीपी में स्थान दिया गया है। स्थानीय उत्पादकों को संभावित खरीदारों और उद्योगों से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से तीन विक्रेता विकास कार्यक्रम और पांच रोजगार विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। योजना के अगले चरण में अक्तूबर में चयनित उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी और रिवर्स बायर–सेलर मीट आयोजित की जाएगी। इसमें उत्पादकों, निर्यातकों, निवेशकों, खुदरा विक्रेताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की आगामी औद्योगिक नीति में चिन्हित उत्पादों से जुड़े उद्यमों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें भूमि पर रियायत, स्टांप शुल्क में छूट, रियायती बिजली, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इससे उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

चयनित उत्पादों की ब्रांडिंग व मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि चयनित उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्पादकों को प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के साथ-साथ व्यापारिक मेलों, प्रदर्शनियों और बायर-सेलर मीट में भागीदारी के लिए सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओडीटीपी कार्यक्रम हिमाचल की पारंपरिक कला, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों के संरक्षण के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

एनडीपीएस मामलों में वांछित महिला गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर की पीओ सेल ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों में उद्घोषित अपराधी घोषित महिला को गिरफ्तार किया है। एएसपी धर्म चंद वर्मा ने बताया कि आरोपी महिला राजेश कुमारी पत्नी राकेश कुमार, निवासी गांव तमोटा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश), उम्र करीब 50 वर्ष को पंजाब के तिब्बा, लुधियाना से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला थाना इंदौरा में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों में वांछित थी। न्यायालय द्वारा उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के बाद नियमानुसार उसका चिकित्सीय परीक्षण (एमएलसी) सिविल अस्पताल इंदौरा में करवाया गया। वहीं, गिरफ्तारी की सूचना उसके पुत्र को फोन के माध्यम से दी गई। इसके बाद आरोपी महिला को आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए थाना इंदौरा के जांच अधिकारी के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को आगामी दिन न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून से बचने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नाहन में श्रद्धा के साथ निकाली भगवान जगन्नाथ की 18वीं रथ यात्रा

जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंजा शहर

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन स्थित प्राचीन विष्णु पीठ श्री जगन्नाथ मंदिर में रविवार को भगवान जगन्नाथ की 18वीं भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। उड़ीसा के पुरी से रियासत काल में लाई गई भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की प्रतिमाओं से सुशोभित इस मंदिर की सिरमौर ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी विशेष धार्मिक मान्यता है।

रथ यात्रा से पूर्व मंदिर परिसर में हवन–यज्ञ और विशेष पूजा–अर्चना का आयोजन किया गया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों को परंपरा के अनुसार अलग–अलग सुसज्जित पालकियों में विराजमान कर मंदिर से बाहर लाया गया। पालकियां ढोल–नगाड़ों और जय जगन्नाथ के जयघोष के बीच काली स्थान पहुंचीं, जहां पूजा–अर्चना के उपरांत कुछ समय विश्राम किया गया। इसके बाद शोभायात्रा चौगान पहुंची,

जहां भव्य रथ तैयार रखा गया था। चौगान में उपायुक्त प्रियंका वर्मा, विधायक अजय सोलंकी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल तथा सांसद सुरेश कश्यप ने भगवान की पूजा–अर्चना कर 56 भोग अर्पित किए। इसके पश्चात भगवान जगन्नाथ अपने परिवार सहित रथ पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण के लिए निकले।

श्रद्धालुओं ने रस्सों की सहायता से रथ को खींचते हुए जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ यात्रा को आगे बढ़ाया। यह रथ यात्रा चौगान से नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शाम को कच्चा टैंक स्थित रघुनाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां भगवान विश्राम करेंगे। इसके बाद पालकियों के माध्यम से शोभायात्रा बाजार से होकर पुनः श्री जगन्नाथ मंदिर लौटेगी। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान का रथ खींचकर पुण्य अर्जित किया। यात्रा की विशेष बात यह रही कि इसमें राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर सभी जनप्रतिनिधि एक साथ धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने एक साथ पूजा–अर्चना की।

जल शक्ति विभाग समस्या का जल्द करे समाधान : जम्वाल

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। विधायक त्रिलोक जम्वाल ने बिलासपुर शहर व आसपास की ग्राम पंचायतों में जारी पेयजल समस्या को लेकर प्रदेश सरकार और जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में भी कई क्षेत्रों के लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। विधायक ने कहा कि कई बार बारिश के दौरान पानी की सप्लाई आती भी है, लेकिन मटमैला होने के कारण वह पीने और अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयोग योग्य नहीं होता। ऐसे में लोगों को दूरदराज के क्षेत्रों से पानी ढोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनके दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि बरसात शुरू होने के बावजूद बिलासपुर शहर के कई इलाकों सहित बामटा और बिद्यात जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट बना हुआ है। गर्मी के मौसम में इस समस्या का सामना कर चुके लोगों को उम्मीद थी कि बरसात में राहत मिलेगी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायत है कि उनके घरों में लगे नलों में पानी कभी–कभार ही आता है। जब सप्लाई होती भी है तो कई बार पानी गंदा और मटमैला होता है, जिसके कारण उन्हें हैंडपंपों और अन्य जल स्रोतों का सहारा लेना पड़ रहा है। विधायक ने आरोप लगाया कि पानी की समस्या को लेकर लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कभी बिजली कट और कभी पंपिंग मशीनरी खराब होने का हवाला देकर समस्या से पल्ला झाड़ लिया जाता है। प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि जल शक्ति विभाग को पेयजल समस्या के तत्काल समाधान के निर्देश दिए जाएं, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

बिलासपुर से शिमला रवाना हुई प्राथमिक शिक्षा बचाओ न्याय यात्रा

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश की 25 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाली जा रही 'प्राथमिक शिक्षा बचाओ न्याय यात्रा' रविवार को नौवें दिन बिलासपुर से शिमला के लिए रवाना हुई। बिलासपुर में शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, मिड–डे मील वर्कर्स व मल्टी टास्क वर्कर्स ने यात्रा का स्वागत किया। लक्ष्मीनारायण मंदिर से शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। संघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि संगठन न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम का विरोध कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों को छठे वेतन आयोग का एरियर, डीए की लंबित किस्तें और हायर ग्रेड पे का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से मांगें जल्द पूरी करने की अपील की। उन्होंने बताया कि यात्रा 25 जुलाई को शिमला पहुंचेगी और 26 जुलाई को चौड़ा मैदान में प्रदेशभर के शिक्षकों के साथ विशाल धरना–प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

पर्यटन आर्थिक विकास और रोजगार का मजबूत आधार बन रहा : अनुराग

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पर्यटन अब केवल सेवा क्षेत्र नहीं रह गया है, बल्कि यह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक कूटनीति का एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है, जो विकसित भारत 2047 की यात्रा में देश के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बन सकता है। वे फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन्स इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी (एफएआईटीएच) द्वारा आयोजित 'इन्क्रेडिबल इंडिया : इनवैल्यूएबल इकोनॉमिक्स' विषयक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

अनुराग ने एफएआईटीएच के विजन–2047 का स्वागत करते हुए 3 ट्रिलियन डॉलर की पर्यटन अर्थव्यवस्था, 10 करोड़ रोजगार सृजन तथा वर्ष 2047 तक भारत की अनुमानित 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में लगभग 10 प्रतिशत योगदान के लक्ष्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसके तहत पर्यटन को आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व भारत को उसकी प्राचीन सभ्यता, अध्यात्म, संस्कृति और विविधता के कारण 'इन्क्रेडिबल इंडिया' के रूप में पहचानता है, लेकिन अब पर्यटन के

माध्यम से उत्पन्न हो रहे आर्थिक अवसरों के कारण भारत 'इनवैल्यूएबल इंडिया' के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। हिमाचल प्रदेश को पर्यटन आधारित विकास का सफल उदाहरण बताते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने धर्मशाला मॉडल को राष्ट्रीय अध्ययन का विषय बताया। उन्होंने कहा कि एचपीसीए स्टेडियम केवल क्रिकेट का मैदान नहीं रहा, बल्कि यह पूरे कांगड़ा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला केंद्र बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों से पर्यटकों की संख्या, होटलों की व्यस्तता, परिवहन सेवाओं की मांग, स्थानीय व्यापार और रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। वहीं, गैर–मैच दिनों में भी हजारों पर्यटक स्टेडियम का भ्रमण कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हैं।

हड़ेटा में 4 करोड़ रुपए से बन रहा ईको–टूरिज्म पार्क

पर्यटकों को मिलेगा एक अलग अनुभव, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। घने जंगलों से सजी पहाड़ियों की सुंदर, शांत व स्वच्छ वादियों के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताने का अवसर मिल जाए, तो इससे अच्छा अनुभव और क्या हो सकता है।

इसी की तलाश में हर वर्ष देश–विदेश से लाखों पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं और यहां के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। इससे न केवल पर्यटकों को सुंदर, स्वच्छ व शांत वादियों में सुकून भरे पल बिताने का अवसर मिलता है, बल्कि कई स्थानीय लोगों की रोजी–रोटी भी इसी से चलती है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री सुक्खू शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी और प्रदेश के अन्य विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के अलावा जिला हमीरपुर जैसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी पर्यटन की संभावनाओं के उचित दोहन पर विशेष बल दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। इसकी एक झलक देखने को मिल रही है नादौन विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ गांव हड़ेटा में। जी हां, नादौन–सलौणी–दियोटसिद्ध मुख्य सड़क मार्ग पर चीड़ के घने जंगलों से सजी छोटी–छोटी पहाड़ियों वाले इस सुंदर गांव में मुख्यमंत्री के प्रयासों के परिणामस्वरूप एक भव्य ईको–टूरिज्म पार्क बनकर तैयार होने वाला है। मुख्यमंत्री ने जनवरी 2025 में गांव हड़ेटा की सुंदर वादियों में आर्थिक विकास और आजीविका सृजन परियोजना (नवजीवन) के तहत इस पार्क का शिलान्यास किया था। इसका निर्माण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वन विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है। लगभग 125 कनाल भूमि पर चार करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पार्क में पर्यटकों के लिए कॉटेज, कैफेटेरिया, योगा प्वाइंट, चिल्ड्रन पार्क, वॉकिंग ट्रेल्स, वॉच टॉवर, एनिमल स्ट्रक्चर्स और कई अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

इस पार्क के निर्माण में स्थानीय लोगों की आजीविका का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसके लिए कॉटेज और कैफेटेरिया के साथ ही दुकानों का निर्माण भी किया गया है। ये कॉटेज एवं कैफेटेरिया स्थानीय लोगों द्वारा ही संचालित किए जाएंगे और दुकानों में स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री का प्रावधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की इस दूरदर्शी सोच एवं दीर्घकालीन योजना के कारण प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों ज्वालामुखी–नादौन और दियोटसिद्ध के बीच मुख्य मार्ग पर बन रहा यह पार्क जहां पर्यटकों को ठहराव के लिए एक बेहतरीन स्थल मुहैया करवाएगा, वहीं स्थानीय लोगों को भी रोजगार मुहैया करवाएगा। उधर, वन विभाग के डीएफओ अंकित सिंह ने बताया कि इस पार्क का अधिकांश कार्य पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा।

प्रेरित — खनोट गांव के प्रगतिशील किसान ने रसायनमुक्त खेती अपनाकर घटाई लागत, बढ़ाई आमदनी

'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना' बनी किसानों के लिए वरदान

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना' किसानों की आय बढ़ाने के साथ–साथ उन्हें रसायनमुक्त एवं टिकाऊ खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।

प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि विभाग के तत्वावधान में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) द्वारा संचालित इस योजना का लाभ उठाकर विकास खंड गोपालपुर के खनोट गांव निवासी प्रगतिशील किसान सुनील कुमार सफलता की नई मिसाल बन गए हैं। प्राकृतिक खेती के माध्यम से वे अपनी लगभग दो बीघा भूमि पर नकदी एवं पारंपरिक फसलों का उत्पादन कर प्रतिवर्ष डेढ़ से दो लाख रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं। सुनील बताते हैं कि वे वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस विधा को अपनाने के बाद उनकी खेती की लागत में कमी आई है, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह बंद हो गया है तथा मिट्टी की उर्वरता में लगातार सुधार हुआ है। विभाग की ओर से उन्हें देसी गाय की खरीद, गौशाला के फर्श के पक्कीकरण तथा प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक उपकरण एवं ड्रम जैसी सुविधाएं तथा अन्य तकनीकी सहयोग भी मिला है। सुनील कुमार ने पिछले वर्ष पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती भी शुरू की। उन्होंने पौधों पर लगभग 10 से 15 हजार रुपए का निवेश किया, जिससे उन्हें 60 से 70 हजार रुपए की आय प्राप्त हुई तथा लगभग 50 हजार रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। वर्तमान में वे कद्दू, खीरा, लौकी, करेला के अलावा भिंडी, टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक, अरबी, जिमीकंद, मक्का तथा गेहूं की प्राकृतिक खेती कर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं।

सरकार का जताया आभार

सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किए जाने से किसानों को बड़ा आर्थिक संबल मिला है। विशेष तौर पर प्राकृतिक रूप से उत्पादित गेहूं, मक्का तथा कच्ची हल्दी के लिए क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए तथा 150 रुपएप्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक निर्णय है। इस पहल से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

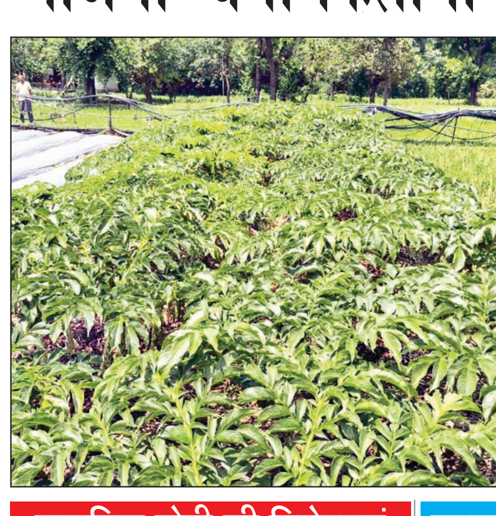

प्राकृतिक खेती के लाभ

सुनील कुमार का कहना है कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, उत्पादन रसायनमुक्त होता है तथा किसानों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। कीटनाशकों के स्थान पर गोमूत्र आधारित प्राकृतिक घोल का उपयोग करने से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक खेती अपनाएं तो न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ वातावरण, उपजाऊ भूमि तथा रसायनमुक्त खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाया जा सकता है।

प्राकृतिक खेती की विशेषताएं

प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य खेती में उपयोग होने वाले अधिकांश संसाधनों को स्थानीय स्तर पर स्वयं तैयार करना है। जीवामृत, घनजीवामृत, फसल सुरक्षा घोल तथा अन्य आवश्यक जैविक घटक देशी गाय के गोबर एवं गोमूत्र से तैयार किए जाते हैं। इस पद्धति में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर निर्भरता समाप्त होती है, जिससे खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आती है। प्राकृतिक खेती का प्रमुख संदेश है। 'गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में।

सरकार दे रही आर्थिक सहायता

प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। योजना के अंतर्गत देसी गाय की खरीद के लिए अधिकतम 25 हजार रुपए तथा परिवहन व्यय के लिए 5 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। गौशाला का फर्श पक्का करने के लिए 8 हजार रुपए तक तथा 200 लीटर क्षमता के प्लास्टिक ड्रम की खरीद पर 750 रुपए की सब्सिडी भी दी जाती है, ताकि जीवामृत एवं अन्य प्राकृतिक घटकों का निर्माण आसानी से किया जा सके।

आपदा की सूचना में देरी न करें, तुरंत करें कंट्रोल सेंटर से संपर्क: राज कुमार

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। उपमंडलाधिकारी (ना.) सदर, बिलासपुर राज कुमार ने आम जनता से अपील की है कि मानसून सीजन के दौरान भूस्खलन, बादल फटना, पेड़ गिरना अथवा किसी भी अन्य प्राकृतिक

आपदा की स्थिति में इसकी सूचना तुरंत उपमंडल सदर, जिला बिलासपुर के कंट्रोल सेंटर के दूरभाष नंबर 01978–224798 पर दें, ताकि संबंधित विभागों द्वारा समय पर राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किए जा सकें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें तथा नदी–नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है तथा आम जनता के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा।

अप्सरा से कम नहीं एवगेनिया मेदवेदेवा

एवगेनिया मेदवेदेवा रूस की प्रसिद्ध फिगर स्केटर हैं। उनका जन्म 19 नवंबर 1999 को मॉस्को में हुआ। वह दो बार विश्व चैंपियन रही हैं और 2018 शीतकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीत चुकी हैं। उनकी शानदार कलात्मक शैली और तकनीक के लिए उन्हें जाना जाता है।

टोक्यो में गूंजा पीवी सिंधु का नाम जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास

घरेलू स्टार अकाने यामागुची को सीधे गेमों में हराकर बनीं पहली भारतीय चैंपियन

एजेंसी, टोक्यो

भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान की अकाने यामागुची को सीधे गेमों में हराकर जापान ओपन 2026 महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सिंधु जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं।

फाइनल मुकाबले में सिंधु ने आक्रामक स्मैश, सटीक ड्रॉप शॉट और बेहतरीन कोर्ट कवरेज का प्रदर्शन करते हुए घरेलू खिलाड़ी यामागुची को 21-17, 21-17 से मात्र 50 मिनट में पराजित किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर का पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 खिताब भी जीत लिया।

31 वर्षीय सिंधु के लिए यह सिंगापुर ओपन सुपर 500 (2022) के बाद पहला बड़ा खिताब है। पिछले दो वर्षों में चोटों के कारण उन्हें कई कठिन दौर से गुजरना पड़ा था और वह अपनी लय व निरंतरता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही थीं।

जापान ओपन का यह खिताब उनके शानदार वापसी का प्रमाण है। इस जीत के साथ सिंधु ने तीन बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची के खिलाफ अपने आमने-सामने के रिकॉर्ड को 16-14 कर लिया। इससे पहले उन्होंने यामागुची को 2022 थाईलैंड ओपन में पूर्ण मुकाबले में हराया था। पहले गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।

मध्यांतर तक यामागुची दो अंकों की बढ़त पर थीं, लेकिन इसके बाद सिंधु ने अपने खेल का स्तर ऊंचा किया और लगातार दबाव बनाया। 17-15 के स्कोर पर दोनों खिलाड़ियों के बीच 38 शॉट की शानदार रैली हुई, जिसमें यामागुची ने बेहतरीन रक्षण किया। हालांकि 17-17 की बराबरी के बाद सिंधु ने लगातार चार अंक जीतकर पहला गेम 21-17 से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ पी.वी. सिंधु ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह विश्व बैडमिंटन की सबसे बड़ी खिलाड़ियों में शामिल हैं और आने वाले बड़े टूर्नामेंटों के लिए भी उन्होंने अपने मजबूत इरादों का संकेत दे दिया है।

दूसरे गेम में नहीं दिया मौका

दूसरे गेम में भी सिंधु ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और 8-3 तथा फिर 14-7 की मजबूत बढ़त बना ली। यामागुची ने अंतिम चरण में वापसी करते हुए स्कोर 19-17 तक पहुंचाया, लेकिन सिंधु ने संयम बनाए रखा और लगातार दो अंक जीतकर मैच तथा खिताब अपने नाम कर लिया।

फीफा विश्व कप 2026: इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान झटका

एजेंसी, मियामी

इंग्लैंड ने फीफा विश्व कप 2026 के तीसरे स्थान के मुकाबले में फ्रांस को रोमांचक मुकाबले में 6-4 से हराकर 1966 में विश्व चैंपियन बनने के बाद विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। इंग्लैंड ने पहले हाफ में ही चार गोल दागकर मैच पर मजबूत पकड़ बना ली थी। हालांकि दूसरे हाफ में फ्रांस ने चार गोल कर जोरदार वापसी की कोशिश की, लेकिन अंत में बुकायो साका ने पेनल्टी पर अपना हैट्रिक गोल दागा और जूड बेलिंगहैम ने स्टॉपेज टाइम में गोल कर इंग्लैंड की जीत पर मुहर लगा दी।

इंग्लैंड के लिए पहले हाफ में डेक्लान राइस और एज़री कॉन्सा ने भी गोल किए, और टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। एम्बाप्पे बने गोल्डन बूट की दौड़ में शीर्ष पर फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने मुकाबले में दो गोल किए। इसके साथ ही वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल (10) करने वाले खिलाड़ी बन गए और गोल्डन बूट की दौड़ में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए।

एम्बाप्पे ने विश्व कप में अपने कुल गोलों की संख्या 22 तक पहुंचा दी, जिससे उन्होंने अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी (21 गोल) को पीछे छोड़ते हुए विश्व कप इतिहास के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी बढ़त हासिल कर ली। ओलीसे ने तोड़ा पेले का रिकॉर्ड फ्रांस के लिए ब्रैडली व उस्मान डेम्बेले ने भी गोल किए, जबकि ओलीसे ने एम्बाप्पे के दोनों गोल में असिस्ट किया। इन दो असिस्ट के साथ ओलीसे के इस विश्व कप में कुल 7 असिस्ट हो गए, जिससे उन्होंने एक ही विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक असिस्ट करने के पेले के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

स्पोर्ट्स विंडो

जिदान बनेंगे फ्रांस फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच, डिडिएर डेशां युग का अंत

एजेंसी, पेरिस। फ्रांस के दिग्गज फुटबॉलर जिनेदिन जिदान एक सितंबर से फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच का पद संभालेंगे। फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जिदान डिडिएर डेशां की जगह लेंगे, जिनका 14 वर्षों का शानदार कार्यकाल फीफा विश्व कप 2026 के बाद समाप्त हो गया। डेशां के नेतृत्व में फ्रांस ने 2018 फीफा विश्व कप और 2021 यूईएफए नेशंस लीग का खिताब जीता। इसके अलावा टीम 2022 विश्व कप के फाइनल और 2026 विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंची। फ्रेंच फुटबॉल महासंघ ने डेशां के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने टीम में अनुशासन, एकजुटता और जीत की संस्कृति को मजबूत किया।

श्रीलंका दौरे के लिए मुनीबा संभालेंगी पाकिस्तान टी-20 टीम की कमान

एजेंसी, लाहौर। पाकिस्तान ने श्रीलंका दौरे पर जाने वाली 15 सदस्यीय टी-20 महिला टीम की कमानी मुनीबा अली को सौंपी है। वहीं नियमित कप्तान फातिमा सना एकदिवसीय टीम की अगुआई करेंगी। चयनकर्ताओं ने इस दौरे के लिए टी-20 टीम में आठ बदलाव किए हैं। पाकिस्तान की महिला टीम श्रीलंका में तीन मैचों की वनडे सीरीज और इसके बाद तीन मुकाबलों की टी-20 सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के बीच होने वाली यह सीमित ओवरों की सीरीज हंबनटोटा में आयोजित की जाएगी। चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों को मौका देने के साथ टीम को संतुलित बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान टीम इस दौरे पर बेहतर प्रदर्शन कर आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहेगी।

'ईसीबी ने मैकुलम के उत्तराधिकारी का नाम पहले से ही तय कर लिया है': डैरेन

एजेंसी, एडगबैस्टन। नॉर्थैंट्स के कोच डैरेन लेहमन ने कहा कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट (ईसीबी) ने ब्रेंडन मैकुलम की जगह लेने वाले व्यक्ति के बारे में पहले ही फैसला कर लिया है। नॉर्थम्प्टनशायर को रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए तीसरा टी-20 ब्लास्ट खिताब जिताने के बाद डैरेन लेहमन ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया कि वह इंग्लैंड के टेस्ट कोच बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईसीबी ने ब्रेंडन मैकुलम की जगह लेने वाले व्यक्ति के बारे में 'पहले ही फैसला कर लिया है'। 2018 में बॉल-टैम्परिंग स्कैंडल के बाद लेहमन ने ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच का पद छोड़ दिया था और तब से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोचिंग नहीं की है। वह पिछले साल हेड कोच के तौर पर नॉर्थेंट्स से जुड़े थे और इस सीजन की शुरुआत में उन्होंने 2029 तक अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया था। इस भूमिका के साथ-साथ वह इंग्लैंड में सर्दियों के दौरान ऑस्ट्रेलिया में एबीसी रेडियो के लिए ब्रॉडकास्ट का काम भी करते हैं।

पेपर लीक के विरोध में आज सीजेपी का संसद मार्च

एजेंसी, नई दिल्ली। रीक्षा प्रश्नपत्र लीक के मामलों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकालने की घोषणा की है। पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने समर्थकों से बड़ी संख्या में मार्च में शामिल होने की अपील करते हुए प्रदर्शन को पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित करने का आग्रह किया है। दीपके ने रविवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी संदेश में कहा कि सभी समर्थक अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या उकसावे से दूर रहें। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक गतिविधियों में शामिल होता है तो वह पार्टी या आंदोलन की भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करता। सीजेपी का कहना है कि लगातार सामने आ रहे प्रश्नपत्र लीक मामलों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। पार्टी ने इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग की है। इस बीच, जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन और प्रस्तावित मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। सीजेपी ने सभी कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन में भाग लेने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

मस्कट में बजेगा भारतीय हॉकी का बिगुल

एफआईएच यूथ हॉकी5एस एशियाई चैंपियनशिप में भारत की नजर खिताब पर

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय सब-जूनियर पुरुष और महिला हॉकी टीमें 20 से 25 जुलाई तक ओमान के मस्कट में होने वाली उद्घाटन एफआईएच यूथ हॉकी5एस एशियाई चैंपियनशिप में दमदार प्रदर्शन के लक्ष्य के साथ उतरेंगी। यह प्रतियोगिता उद्घाटन एफआईएच अंडर-18 यूथ हॉकी5एस विश्व कप 2026 के लिए एशियाई क्वालीफायर भी है।

सरदार सिंह के मार्गदर्शन में पुरुष टीम हाल ही में अंडर-18 एशिया कप जीतने के बाद पूरे आत्मविश्वास से मैदान में उतरेगी। भारत ने फाइनल में जापान को 4-1 से हराकर खिताब जीता था। टीम को एलीट पूल में मेजबान ओमान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रखा गया है।

पूर्व भारतीय कप्तान रानी की कोचिंग में महिला टीम भी मजबूत चुनौती पेश करेगी। टीम ने अंडर-18 महिला एशिया कप 2026 में कांस्य पदक जीता था। महिला टीम के एलीट पूल में चीन, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 जुलाई को करेगा। महिला टीम पहले कजाकिस्तान से भिड़ेगी, जबकि पुरुष टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। इसके बाद दोनों टीमें लीग चरण में डबल राउंड-रॉबिन प्रारूप के तहत अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों से दो-दो बार मुकाबला करेंगी। वर्गीकरण और पदक मुकाबले 25 जुलाई को होंगे। टूर्नामेंट में लीग चरण की शीर्ष दो टीमें सीधे फाइनल में पहुंचेंगी, जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम कांस्य पदक मुकाबला खेलेगी। मुख्य कोच सरदार सिंह ने कहा कि टीम ने हॉकी5एस के तेज प्रारूप के अनुरूप अच्छी तैयारी की है और लक्ष्य विश्व कप के लिए क्वालीफाई करना है। वहीं, महिला टीम की मुख्य कोच रानी ने विश्वास जताया कि खिलाड़ी निडर खेल दिखाते हुए लगातार बेहतर प्रदर्शन करेंगी और विश्व कप का टिकट हासिल कर देश का गौरव बढ़ाएंगी।

नरेन-जेसन होल्डर का कहर, एलए नाइट राइडर्स पहली बार बनी एमएलसी चैंपियन

एजेंसी, ऑकलैंड

सुनील नरेन और जेसन होल्डर की शानदार गेंदबाजी के दम पर लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स (एलए नाइट राइडर्स) ने इतिहास रचते हुए पहली बार मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) का खिताब अपने नाम कर लिया।

ओकलैंड कोलिजियम में स्थानीय समयानुसार शनिवार रात खेले गए रोमांचक फाइनल में एलए नाइट राइडर्स ने गत चैंपियन वॉशिंगटन फ्रीडम को एक रन से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस जीत के साथ एमआई न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन फ्रीडम के तीन साल के दबदबे का भी अंत हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एलए नाइट राइडर्स की टीम 19.4 ओवर में 164 रन पर सिमट गई। टीम के लिए आंद्रे फ्लेचर ने 27 गेंदों में 47 रन, कॉलिन मुनरो ने 29 गेंदों में 40 रन और मैथ्यू ट्रॉम्प ने 21 गेंदों में 39 रनों की तेज पारी खेली। वॉशिंगटन फ्रीडम की ओर से बेन ड्वारशुइस ने तीन विकेट, जबकि रचिन रविंद्र और निखिल चौधरी ने दो-दो विकेट लिए।

165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वॉशिंगटन फ्रीडम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अनुभवी स्पिनर सुनील नरेन और कप्तान जेसन होल्डर ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर टीम को दबाव में बनाए रखा। नरेन ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 13 रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि होल्डर ने तीन विकेट हासिल किए। हालांकि, ओबस पीनार ने निचले क्रम में 24 गेंदों में 53 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर मुकाबले को आखिरी गेंद तक पहुंचा दिया। उन्होंने अकेले दम पर वॉशिंगटन की उम्मीदें जिंदा रखीं, लेकिन उनकी शानदार पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। वॉशिंगटन की टीम निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट पर 163 रन ही बना सकी और उसे एक रन से हार का सामना करना पड़ा। एलए नाइट राइडर्स ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में दबाव के बीच संयम बनाए रखते हुए पहली बार एमएलसी ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

नग्न अवस्था में मंदिर पहुंची महिला इंजीनियर

एजेंसी, हैदराबाद। हैदराबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 25 साल की एक युवती ने नग्न अवस्था में मंदिर में प्रवेश किया। इसके बाद वह देवी अम्मावरु की मूर्ति उठाकर भागी और पास के एक तालाब में कूद गई। पुलिस ने तालाब से युवती का शव बरामद कर लिया है, लेकिन देवी की मूर्ति अभी तक नहीं मिली है। पुलिस गोताखोरों की मदद से मूर्ति की तलाश कर रही है, जिसे जांच में एक महत्वपूर्ण सबूत माना जा रहा है।

◆ देवी की मूर्ति लेकर तालाब में लगाई छलांग

◆ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी युवती

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृत युवती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। वह पहले बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। इसके बाद वह विशाखापत्तनम में रहने लगी थी। युवती के माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था। इस वजह से उसके पिता विशाखापत्तनम में रहते हैं, जबकि उसकी मां हैदराबाद के पीरजादिगुडा में रहती थीं। पुलिस के अनुसार, मृत युवती और उसकी मां दोनों ही भय व डर से ग्रस्त थीं।

राष्ट्रपति मुर्मू तीन देशों की यात्रा के पहले चरण के लिए माल्दोवा रवाना

द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार व सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर

एजेंसी, नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को अपने सात दिवसीय तीन देशों के राजकीय दौरे के पहले चरण के लिए मोल्दोवा रवाना हो गई। वह 19 और 20 जुलाई को मोल्दोवा की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी।

मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अपनी समकक्ष राष्ट्रपति मैया सैंडू के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी तथा मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से भी मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। उन्होंने कहा कि यह भारत के किसी राष्ट्रपति की मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की पहली राजकीय यात्रा है, जबकि रोमानिया की राष्ट्रपति स्तर की यात्रा तीन दशक बाद हो रही है। इस दौरे से तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू और राष्ट्रपति मैया सैंडू के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच कृषि, स्वास्थ्य सेवा, औषधि उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच परस्पर लाभकारी साझेदारी की व्यापक संभावनाएं हैं। रोमानिया यूरोपीय संघ में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में हो रही प्रगति से आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के और मजबूत होने की संभावना है।

उत्तर मैसेडोनिया-रोमानिया से रिश्तों को मजबूती

मोल्दोवा यात्रा के बाद राष्ट्रपति मुर्मू 21 और 22 जुलाई को उत्तर मैसेडोनिया जाएंगी। वह भी किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली राजकीय यात्रा होगी। वहां वह राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजानोव्स्का-दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ह्रिस्टिजन मिकोस्की और संसद के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी तथा उत्तर मैसेडोनिया की संसद को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत-उत्तर मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। दोनों देशों के बीच कृषि, औषधि उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा आईटी आधारित सेवाओं में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। दौरे के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की राजकीय यात्रा करेंगी। यह तीन दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया यात्रा होगी। वहां वह राष्ट्रपति निकुशोर डैन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी, भारत-रोमानिया बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगी।

अभिषेक के कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

एजेंसी, कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी के दक्षिण 24 परगना जिले के अमताला स्थित पार्टी कार्यालय पर रविवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर कार्रवाई की गई। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है।

यह राहत अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स (Leaps and Bounds) की ओर से दायर याचिका पर मिली। कंपनी ने अदालत में दावा किया कि जिस जमीन पर कार्यालय बना है, उसके सभी वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसी आधार पर कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी। कार्यालय पर हुई कार्रवाई के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि जब मामला पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित था, तब भी प्रशासन ने कार्रवाई की। पार्टी ने दावा किया कि यह कार्रवाई भाजपा नेताओं की मौजूदगी में हुई और इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य थे। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अदालतों की ओर से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उनके कार्यालय को गिराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने भाजपा समर्थकों के साथ मिलकर कार्यालय से लैपटॉप, प्रिंटर, दस्तावेज और अन्य सामान बाहर निकाला। अभिषेक ने इस घटना को 'वर्दी में चोरी' बताते हुए कहा कि यह कानून के शासन पर हमला है। मामले की अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट के आदेश से कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी।

मायावती ने संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार होने की जताई आशंका

एजेंसी, लखनऊ

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका जताते हुए कहा कि राम मंदिर चढ़ावा समेत कई अहम मुद्दे सदन में उठेंगे, जिन पर पूरे देश की नजर रहेगी। उन्होंने सभी दलों से संसद का मानसून सत्र बिना किसी उत्तेजना, रोष और विद्वेष के शांतिपूर्ण एवं सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है।

मायावती ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर सात पॉइंट में लंबा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अब जबकि संसद का मानसून सत्र कल 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। एक बार फिर यह देश व आमजन की चिन्ता है कि क्या इस बार भी फिर से संसद का सत्र हंगामा व स्थगन आदि की भेंट चढ़ जायेगा या फिर महंगाई, बेरोजगारी, महिला असुरक्षा, महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपरलीक आदि से जुड़े देश के ज्वलन्त मुद्दों से उत्पन्न माहौल को शान्त करने व इनके संतोषजनक समाधान के लिए गंभीरता दिखाई जायेगी। मायावती ने आगे लिखा कि अयोध्या श्रीराम मन्दिर में चढ़ावा हेराफेरी व गबन आदि को लेकर व्यापक जन आक्रोश से उप्र व देश को झकझोर कर रख दिया है। लोग जवाबदेही मांग रहे हैं, जिसकी गूंज सड़कों से लेकर अदालत तक में है और संसद में भी यह मुद्दा जरूर गर्म होगा। बसपा प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद के हालात, राजस्थान में सरकार की लापरवाही के कारण गर्भवती महिलाओं की मौत सहित विभिन्न राज्यों में बढ़ती महिला असुरक्षा, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे भी हैं। भारत की अर्थव्यवस्था व यहां के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध और रुपये का अवमूल्यन आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनपर राजनीतिक द्वेष, स्वार्थ व आरोप-प्रत्यारोप की संकीर्णता/वैमनस्य को त्यागकर सत्ता व विपक्ष दोनों को एकजुट होकर अच्छा उपाय ढूंढ कर सराहनीय कार्य करना होगा।

रातोंरात बदले जाएंगे जनता को नुकसान देने वाले फैसले : लामिछाने

एजेंसी, काठमांडू। नेपाल में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने कहा है कि यदि सरकार के किसी फैसले से जनता को बड़ा नुकसान होता है, तो उसे रातोंरात बदला जा सकता है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि यह कोई अपरिवर्तनीय नीति नहीं है। जरूरत पड़ने पर बदलाव किया जाएगा। सरकार को थोड़ा समय और धैर्य दीजिए।

लामिछाने ने कहा कि सरकार जिस उद्देश्य से निर्णय लेती है, यदि वही निर्णय जनता के लिए नुकसानदायक साबित होता है, तो उसे बदला जाएगा। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें सरकार को थोड़ा समय देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि कई बार किसी नीति को लागू करने के दौरान व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आती हैं। यदि किसी निर्णय से व्यापक नुकसान होता है, तो उसे तत्काल बदलना आवश्यक हो जाता है।

चढ़ावा चोरी की स्वतंत्र जांच कराएं मोदी: कांग्रेस

खड़गे और राहुल गांधी ने दान और चढ़ावे के प्रबंधन में पारदर्शिता की उठाई मांग

एजेंसी, नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र और व्यापक जांच कराने की मांग की है। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट में वित्तीय अनियमितताओं से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था प्रभावित हुई है और इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी चिंताजनक है।

खड़गे और राहुल गांधी ने अपने संयुक्त पत्र में कहा कि देशभर के लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था और विश्वास के साथ अपनी मेहनत की कमाई ट्रस्ट को दान स्वरूप अर्पित की थी, लेकिन वित्तीय अनियमितताओं के कारण वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि श्रद्धालुओं के विश्वास और दान की पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है। पत्र में दोनों नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, जबकि ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की गई। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट के कई सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और उनसे जुड़े संगठनों से जुड़े रहे हैं तथा ट्रस्ट के पूर्व महासचिव भी प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री की चुप्पी उचित नहीं है और जवाबदेही सुनिश्चित करना उनका दायित्व है।

पत्र में मांग की गई है कि ट्रस्ट के सभी वित्तीय लेनदेन तथा नकद, सोना, चांदी सहित सभी प्रकार के चढ़ावे के संग्रह, प्रबंधन और उपयोग की स्वतंत्र एवं व्यापक जांच कराई जाए। साथ ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि प्रत्येक श्रद्धालु यह जान सके कि उसके द्वारा दिया गया दान किस प्रकार उपयोग में लाया गया। संयुक्त पत्र साझा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की निष्पक्ष और व्यापक जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आस्था और विश्वास के साथ दान देने वाले लाखों श्रद्धालु वित्तीय गड़बड़ियों के कारण स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी 'एक्स' पर पत्र साझा कर कहा कि श्री राम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ अपनी कमाई अर्पित की, लेकिन चढ़ावा चोरी का मामला अब सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य का चयन केंद्र सरकार ने किया था और इसे पूरे मामले पर पीएम की चुप्पी अस्वीकार्य है।